सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा सोमवार,तिथि 01 जुलाई,2019 ई0

त्रयोदश सत्र 10 आषाढ़,1941 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, चमकी रोग से बिहार में 200 बच्चे ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इसको समय पर उठाईयेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : चमकी रोग से बच्चे मर रहे हैं, दवा का अभाव है और डाक्टरों का भी अभाव है ।..

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी चमकी रोग पर तो ध्यानाकर्षण भी है, कार्य स्थगन भी है अभी क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह अत्यंत ही लोक महत्व का विषय है । इसलिए इस पर नियमानुकूल काम होने दीजिये । आप सूचना दिए हैं, ठीक है तो उस पर समय पर निर्णय होगा । आप सदन चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सदन चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव हमलोगों ने दिया है ।

अध्यक्ष : जब वह मोशन आयेगा तब न बोलियेगा ? चलिए, अब अल्प सूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आपलोग ?

श्री भाई वीरेन्द्र : सब काम छोड़कर इसी पर बहस करायी जाय ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण तो है ही आज ?

(व्यवधान)

अभी तो सदन चलने दीजिये । कार्य स्थगन के समय इसको उठाईयेगा ।

सदानंद बाबू आप तो हमारी वाली कुर्सी पर रहे हैं पॉच साल, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री सदानंद सिंह : इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि विषय बहुत ही संवेदनशील है, यह ठीक है कि प्रश्नोत्तर काल चलना चाहिए, प्रश्नोत्तर काल चले और ध्यानाकर्षण के बाद काम रोको प्रस्ताव जो हमलोग लाए हैं उसपर विचार हो तब ही कोई कार्य आगे हो ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव हो, प्रश्नोत्तर काल चला के क्या करियेगा ?

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? माननीय सदस्यगण बोलें क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : सारे कार्य स्थगित करके कार्य स्थगन पर बहस हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण भी तो है न ? नियम क्या कहता है ? कार्य स्थगन की सूचना किन्होंने दी है, लाईये ।

श्री श्रवण कुमार (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नियमावली में सारा प्रावधान उल्लिखित है और अल्प सूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न का समय निर्धारित है, उसके हिसाब से विपक्ष के द्वारा काफी संवदेनशील विषय पर कार्य स्थगन लाया गया है, इनको सिर्फ चिन्ता इस बात पर है कि हमको पॉलिटिकल माईलेज मिलना चाहिए । जब संवदेनशील मामले को ध्यानाकर्षण के जरिये उठाया है और स्पीकर साहेब ने इसको स्वीकृत किया है तो ऐसे मामले पर इनको गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, हमारी इजाजत से तो पढ़िये वरना पढ़ियेगा तो उसका क्या महत्व होगा ?

श्री भाई वीरेन्द्र : आपकी इजाजत से पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष : हमने इजाजत दी कहॉं ? आप जबर्दस्ती इजाजत ले रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार : हुजूर, एक पढ़ने वाले रहें तब न, एक इधर से पढ़ रहे हैं और एक उधर से पढ़ रहे हैं, सदानंद बाबू तीसरी तरफ से । किनकी किनकी बात सुनी जाय । हाउस को औंर्डर में रहना चाहिए तब बात को सुना जायेगा । ये विषय वस्तु को डायभर्ट कर रहे हैं । ऐसे संवेदनशील मामले पर विपक्ष का रुख एक होना चाहिए । विपक्ष अलग अलग बंटा हुआ है और संवेदनशीलता की धज्जी उड़ाने में लगे हुए हैं । सरकार चाहती है कि ऐसे संवेदनशील मामले पर बहस हो और इनके जो बहुमूल्य सुझाव हो वह सरकार जानना चाहती है । ये सुझाव नहीं देना चाहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल माईलेज लेना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सदन तो चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, एक मिनट । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आसन की बात सुन लें, आप तमाम सदस्य उत्तेजित हैं, मामला भी अत्यंत लोक महत्व का है, सरकार ने भी कहा है, सारे विपक्षी दलों की इच्छा है और आप सब कह रहे हैं । यह समाचार भी राज्य सहित पूरे देश में आया था इसलिए अब इस विषय की महत्ता को देखते हुए, इसका लोक महत्व से जुड़ाव देखते हुए, मैं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को नियम 99 के तहत सदन की अनुमति के लिए पेश कर रहा हूं ।

माननीय सदस्यगण, मुजफ्फरपुर में जो चमकी या ए.इ.एस. बीमारी के मद्देनजर बच्चों की मौत हुई है, उसके मद्देनजर हमें आज तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहला है श्री महबूब आलम, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री सुदामा प्रसाद इनका 9.05 पर आया है फिर श्री भाई वीरेन्द्र, डा0 फैयाज अहमद, मो0 नेमतुल्लाह, श्री अब्दुल बारी सिद्दकी,

श्री विजय प्रकाश, श्रीमती एज्या यादव, श्री समीर कुमार महासेठ और डा0 अब्दुल गफूर जी का इनका 9 बजकर 7 मिनट पर प्राप्त हुआ और तीसरा है श्री राजेश कुमार जी का, यह 9 बजकर 31 मिनट पर प्राप्त हुआ है । जैसी सम्पूर्ण विपक्ष की भावना है और जो इस विषय का लोक महत्व है, सरकार ने भी जो अपनी भावना प्रकट की है उसके अनुरूप मैं इस प्रस्ताव को अपने अधिकार से आप सबों की स्वीकृति के लिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए, मैं सदन में पेश करता हूं ।

अध्यक्ष : ''प्रश्न यह है कि

इस कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाय ।''

(सभा की सहमति हुई)

यह कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम अपना विचार रखिये । अब बहस जारी रहेगी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली की धारा 98 के तहत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं ।

क्रमशः

टर्न-2/01.07.2019/बिपिन

श्री महबूब आलम : क्रमशः ... महाशय, विगत 2006 से ही प्रतिवर्ष 150 से 300 तक बच्चे मुजफ्फरपुर सहित 23 जिलों में इंसेफलाइटिस चमकी बुखार से मारे जा रहे हैं । महोदय, मृत 287 बच्चों के परिवार का सरकारी सर्वे में पाया गया कि 77.4 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं । 91 परिवारों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है और सबसे भयावह यह है कि मृत बच्चों में 61 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने महोदय, बीमार पड़ने से पूर्व रात्रि में खाना तक नहीं खाया था । इस बार 17 बच्चे जापानी इंसेफलाइटिस से पीड़ित पाए गए जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन का इंसेफलाइटिस के इलाज का एक मानक प्रावधान है । इसके तहत अगर बच्चे भूखे न रहें और बीमार पड़ने के घंटा भर के भीतर इलाज शुरू हो जाए तो करीब-करीब 70 प्रतिशत् बच्चों को बचाया जा सकता है । यह तभी संभव है जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर रेफरल, जिला अस्पताल और मेडिकल

कॉलेज में इलाज की सर्वांगीण एवं कारगर व्यवस्था हो । लेकिन तथ्य बताते हैं कि उपरोक्त तमाम संदर्भों में सरकारी व्यवस्था पूर्णत: फेल है, सरकार पूर्णत: संवेदनहीन है और जनता के साथ आपराधिक लापरवाही कर रही है । अत: इसी गंभीर मामले पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर बहस की मांग करते हैं । हमारी मांग स्वीकृत हुई है महोदय । मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सिद्दिकी साहब आएंगे तब । श्री राजेश कुमार बोलिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, विगत्....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जिन लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है मैं उनका प्राथमिकता से नाम पुकार रहा हूं ।

(व्यवधान)

संजय सरावगी जी, जो नेता विपक्ष में बैठे हैं उनकी सुनिए न ! जो नहीं हैं, वहां कहां जा रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन का आभार प्रकट करता हूं कि बिहार में विगत पांच वर्षों से जिस तरह से चमकी बुखार और इंसेफलाइटिस के प्रकोप से हमारे मासूम बच्चों का देहान्त हो रहा है, उसके लिए आसन द्वारा बहुत ही संजीदगी से इसपर बहस कराई जा रही है उसके लिए पूरे सदन का, आपका आभार प्रकट करता हूं ।

सबसे पहले तो मैं दो-तीन बातों को प्वायंट आउट करना चाहता हूं कि सरकार विगत पांच वर्षों से छोटी-बड़ी प्रयास की होगी और कर रही है लेकिन दो बातों पर यह ध्यानाकर्षण हमको देना है, आपको बताना है । पहली बात तो यह कि आखिर हम इन मासूम बच्चों को जो 172 के आसपास हैं, उनकी मृत्यु हुई, हम उस पर किस संजीदगी से काम कर रहे हैं और पांच वर्ष से हम क्यों इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं और उसपर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं । पहली तो यह है कि सरकार यदि यह प्रयास करती है और ईमानदार प्रयास करती और इसपर रिसर्च करती और जिस तरह से लिच्ची पर हम उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं लेकिन मूल बातें जो हैं, जो दलित के बच्चे हैं, पीड़ित हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनके रहन-सहन पर हमको प्रकाश डालनी चाहिए । चूंकि जिस तरह से ऐस्बेस्टस के मकानों में, खासकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों में जो हमारे गरीब बच्चे रहते हैं, दलित, शोषित के बच्चे रहते हैं, उनके घर की भी आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर उनके घर की मनोदशा और रहन-सहन कैसी है । पहले तो सरकार को इस पर लगनी चाहिए । चूंकि सामने कुछ बातें आई हैं कि उनकी जो एस्बेस्टस की घर है

उसके उपर उनकी झोपड़ियां लगी हुई हैं और वे जब 42 और 52 डिग्री के टेम्परेचर, जो पहले नहीं आता था और दिनों-दिन यह टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, ऐस्बेस्टस के लोहे के मकान में जो उनकी छत होती है तो वह कहीं-न-कहीं उनकी शारीरिक दशा और दिशा जो है वह रोग अवरोधक जो होनी चहिए, वह रोग अवरोधक क्षमता उनकी घट रही है, इसपर इस सरकार को मंथन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए । पहला सुझाव मेरा यह है ।

दूसरे, कि आजतक, हम पांच वर्ष से लगातार प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दो पहलू हैं लेकिन यदि हम ईमानदार प्रयास करते हैं तो आज जब हम अंतरीक्ष में जा सकते हैं, सैटेलाइट छोड़ सकते हैं तो क्या हम 172 बच्चों की जान नहीं बचा सकते ? इसलिए सरकार से अभी तत्काल मेरी यह सदन के माध्यम से मांग है कि इसके लिए रिसर्च टीम अलग से गठित हो और वह इसपर लगातार, यह नहीं कि यह वर्षा के मौसम में चमकी बुखार आता है, उस समय सारे टीम लग जाते हैं, सारी मशीनरी लग जाती है, तो यह पूरे पांच वर्ष काम करने की आवश्यकता है और सालों-साल काम करने की आवश्यकता है ।

तीसरी बात यह है कि कहीं-न-कहीं हम, इसमें एक्सपर्ट जो होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको यदि विदेश से बुलाना हो और यदि वो पूरे देश के रिसर्चर को बुलाना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, काफी संजीदगी हैं इस मामले में लेकिन कहीं-न-कहीं इसका रिसर्च लगातार होना चाहिए । आज सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसको अंतिम परिणाम तक ले जाकर इस चमकी बुखार पर हमको काबू पाना चाहिए, मैं सरकार से यह मांग करता हूं सदन के माध्यम से । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पूरे सदन को और चेयरपर्सन को, आपको अध्यक्ष जी और अपने दल के कांग्रेस के तमाम लीडर का आभार प्रकट करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी बात को सुनी । इन तीन बातों को हम समझते हैं कि पूरे वर्ष इसपर रिसर्च करिए और इसपर काबू पाइए । हम यही सदन के माध्यम से मांग करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि इसको गंभीरता से लिया और मुझको लगता है कि वित्तीय वर्ष में कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरी जानकारी में दूसरी बार स्वीकृत किया गया है और जो आपने स्वीकृति दी है, इससे मैं कह सकता हूं कि सदन की भी गरिमा बढ़ी है और सदन के जो नेता हैं और जो सदस्य हैं उनके प्रति भी गंभीरता दिखाने का

और पूरे देश में यह संदेश देने का इस विधान सभा ने यह काम किया है कि इस घटना से हम मर्माहत भी हैं, दु:खी भी हैं, हम इसका उपाय भी सोचते हैं, मगर महोदय, एक मेरा बीच में यह था कि चूंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव जब आपने स्वीकृत कर लिया तो कार्य सूची के आज के सभी कार्य स्थगित हो गए और चूँकि कार्य स्थगन प्रस्ताव आपने स्वीकृत किया है तो इसके लिए एक तो समय निर्धारित कर देते, समय निर्धारित नहीं किए हैं तो इसका मतलब कि जब तक यह बहस चलता रहेगा, तब तक अन्य कार्य स्थगित हो जाएंगे । महोदय..

अध्यक्ष : एक मिनट, यह आपकी नियमावली में ही स्पष्ट रूप से रेखांकित है कि जब कभी कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह है कि इसका समय दो घंटे होगा। यह कार्यसूची में ही है और यह भी लिखा है कि यदि आरंभ से दो घंटे के भीतर वाद-विवाद समाप्त न हो तो दो घंटे का अंत होने पर वह स्वत: समाप्त हो जाएगा । यह आपकी नियमावली में लिखा है । यह एक बात ।

दूसरी बात यह भी इसमें है कि वाद-विवाद समाप्त हो जाने के बाद सभा उस दिन का कोई अन्य कार्य संपादित कर सकेगी । आगे आप जारी रखिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, पहला दिन जब सत्र था तो उस दिन भी सदन ने अपनी गंभीरता दिखाई और उन मृत बच्चों के प्रति सदन ने शोक-संदेश ज्ञापित किया ....

क्रमश:

टर्न : 3/कृष्ण/01.07.2019/

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : (क्रमश:) महोदय, यह जो घटना घटी है, यह कोई आज का, इस साल का या पहली घटना नहीं है, बल्कि 10-15 सालों से ये घटनायें घट रही हैं । मगर इस बार जो घटना घटी है और इस बार जो बच्चे हमारे मरे हैं, उसने सारे देश को झकझोर दिया है और देश ही नहीं बल्कि मीडिया ने जो रूख अपनाया है, हालांकि मीडिया की बहुत बातों से हम सहमत नहीं हैं, एकतरफा अटैकिंग का उन्होंने एक तरह से एजेंडा बनाया । मगर यह जो घटना है, यह जो बिहार है, बिहार भारत का अंग है । भारत एक गणराज्य है और उस गणराज्य का एक सूबा बिहार भी है । बिहार सरकार की जहां जिम्मेदारी बनती है, वहीं केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है । केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकती है । मैं प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक तरह से

सख्त टिप्पणी की । मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग भी हैं, वे सख्त टिप्पणी कर देते हैं, मगर इसका उपाय क्या होगा, इसके लिये बजटरी प्रोविजन क्या होगा, इसके लिये बिहार को विशेष सुविधा क्या दी जायेगी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है । जब घटना घट जाती है, जब आते हैं लोग और वही बात दोहरा कर चले जाते हैं, जो 5 साल पहले उन्होंने बिहार में आकर कही थी । मुझे माफ कीजियेगा । मैं किसी तरह की राजनीति नहीं कर रहा हूं, बल्कि संयोग से अभी जो केन्द्रीय मंत्री हैं डा0 हर्षवर्द्धन, मैं तो इनको बहुत अच्छा व्यक्ति समझता रहा हूं, इनको गंभीर आदमी समझता रहा हूं और पेशा से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति समझता रहा हूं । मगर 5 साल पहले भी वह आये इस बिहार में और बिहार में आने के बाद उन्होंने जो उस वक्त घोषणा की थी, टोटो घोषणा इस बार भी आकर करके गये । तो अब इससे बड़ा मजाक बिहार के लिये क्या हो सकता है कि एक केन्द्रीय मंत्री आये और 5 साल पहले जो घोषणा किये थे और वह घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हो तो इसका मतलब चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी प्राथमिकता सूची में बच्चों की मौत की रोकथाम करने का विषय नहीं है । अगर बच्चों की मौत की रोकथाम करने का विषय होता तो केन्द्र सरकार भी मदद करती, कार्यक्रम बनाती, विशेषज्ञ भेजते और उसके बाद कोई न कोई निदान निकलता ।

महोदय, मगर जो समाचार पत्रों में आये हैं कि सरकार आधिकारिक रूप से बोलेगी । सरकार की अपनी आदत होती है कि उनके अस्पताल में जिनलोगों की मृत्यु हुई, उसकी सूचना वह उपलब्ध कराते हैं । प्राईवेट हॉस्पीटल में कितने लोग मरे, फिर दूसरे अस्पताल में कितने लोग मरे, उसकी सूचना नहीं है । मगर कमोबेश लोगों का मानना है कि 200 से अधिक बच्चे मर गये । अब यह कह सकते हैं कि ये जो 200 बच्चे मरे हैं, गरीबों के बच्चे मरे हैं । अगर ये बच्चे बड़े होते तो हो सकता था कि इसमें से दूसरा नीतीश कुमार पैदा होता, हो सकता था कि इसमें से कोई दूसरा लालू यादव पैदा होता था, हो सकता था कि कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी पैदा होता, तो मैं कह सकता हूं कि गरीबों के बच्चों को सुनियोजित मारने की साजिश केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिली-भगत से हुई है । अब आप कहियेगा कि कोई सरकार नहीं चाहती है

किसी को मारना । मगर जब आप बार-बार फेल कर रहे हैं तो आरोप तो आप पर लगेगा और जब आरोप लगेगा तो उसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं होती है । गलतियों को स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करना, यह हमारा और आपका दायित्व होना चाहिए ।

महोदय, अभी तो आय-व्ययक बजट पर बहस होना है । हर साल सरकार बजट पेश करती है । दो साल हम पेश किये, उसके पहले श्री सुशील कुमार मोदी जी पेश करते रहे । इस बार भी इन्होंने दो साल का बजट पेश किया और जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, वह अपने विभाग का डिमांड लेकर आते हैं । सरकार बताये कि बजट में जो स्वास्थ्य के लिये राशि का प्रोविजन किया गया, उसमें क्या इस चमकी की रोक-थाम करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाये गये, क्या उसके लिये कोई राशि निर्धारित की गयी, क्या उसके लिये सरकार ने युद्ध स्तर पर कोई अभियान छेड़ा ? तो महोदय, निश्चित रूप से इन्होंने सोचा कि यह इस मौसम में आता है और बरसात हो जाती है, तब यह मर्ज खत्म हो जाता है । तो जब सरकार की मंशा में यह बात घर गयी हो कि भई, यह तो अपने-आप लोग हल्ला-गुल्ला करेंगे कि इतने बच्चे मर गये, फलाने मर गये । अब जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय अलग-अलग भी है और बहुसंख्यक की राय एक सी है । पहले लोग कह देते थे कि लीची खा लेता है उससे मर जाता है । हमारा बच्चा, आपका बच्चा लीची खाता है तो कहां मरता है ? मर रहा है वही जो भूखे पेट रहता है । मर रहा है वही जो कुपोषित है । मर रहा है वही, जो झोपड़ी में रहता है । मर रहा है वही, जो एस्वेस्टस पैड के अंदर रहता है, मर रहा है वही, जो खेत और खलिहान में सोता है तो खेत और खलिहान में सोनेवाले के लिये, गरीबों के लिये, झोपड़ी वाले के लिये, एस्वेस्टस पैड वाले के लिये आपने क्या कार्यक्रम बनाया ? मैं समझता हूं कि आपने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है । आप फेल कर गये, आप भी फेल कर गये और केन्द्र सरकार भी फेल कर गयी । महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ, प्रधान मंत्री जी ने कॉगनीजेंस लिया तो लोगों को लगा कि साहब प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आयी हैं । अब जो है बिहार को कुछ स्पेशल फैसलिटिज इस

काम के लिये मिलेगा और मुख्य मंत्री बतायें कि उनको प्रधानमंत्री जी ने क्या वादा किया । प्रधान मंत्री जी ने तो आपके बिहार में आकर स्पेशल पैकेज का वादा करके गये थे । प्रधान मंत्री जी से आप सबों ने इस सदन में सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी । तो मुझको लगता है कि जिस तरह से टर्न डाउन स्पेशल पैकेज को किया, जिस तरह से टर्न डाउन इन्होंने विशेष राज्य के दर्जा को किया, उसी तरह बच्चे मर रहे हैं, बच्चे का हाथ टूट गया, बड़े दुख की बात है । मगर भई, बच्चे मर रहे हैं तो उसके भविष्य के लिये, इलाज की व्यवस्था अगर आप करेंगे तब समझ में आयेगा कि साहब आप सार्थक पहल कर रहे हैं और सचमुच में आप दुखी है ।

महोदय, अब श्री मंगल पाण्डेय जी है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे मित्र भी हैं । आपका जो कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में इनसे मैंने पूछा कि भई, अभी आप कहां-कहां के प्रभारी है ? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि क्या कहें, हम तो हमेशा एलेक्शन में फंसे रहते हैं, कभी झारखंड, कभी उतराखंड, फलाना । अब जब इनकी प्राथमिकता संगठन है तो सरकार का स्वास्थ्य विभाग का हालत तो खराब होगा ही । अगर इनको स्वास्थ्य मंत्री रखना है, सुशील कुमार मोदी जी की चलती है संगठन में, तो कम से कम प्रभारी से हटवा दीजिये और अगर प्रभारी रखना है तो इनको स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से इस्तिफा करवा दीजिये ।

क्रमशः

टर्न-4/अंजनी/दि0 01.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : क्रमशः ... आप किसी को भी अपने ही घटक दल के लोगों को बना दीजिए । मैं उनका दर्द समझ रहा हूँ, मगर इनकी प्राथमिकता संगठन है, इनकी प्राथमिकता जीत है, इनकी प्राथमिकता वोट है, इनकी प्राथमिकता गरीबों के बच्चे का नहीं है, गरीबों के बच्चों का प्राथमिकता होता तो बजट में और स्वास्थ्य के डिमांड में जरूर इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया होता और कार्यक्रम तय किये गये होते । महोदय, एक तरह से प्रधानमंत्री ने ही कहा कि बड़ी चूक हुई है, तो अगर बड़ी चूक हुई है तो उसका तो बड़ा निदान होना चाहिए कि सिर्फ कह

देना कि बड़ी चूक हुई है । महोदय, मैं कह सकता हूँ कि जो इस बार की घटना घटी है और जितने लोग मरे हैं तो इसमें सरकार भी शर्मसार हुई है । बिहार भी शर्मसार हुआ है, राजनीतिक लोगों पर भी उंगुली उठी है । असल इस वजह से कि यह जरूरी है कि इसको युद्धस्तर पर फिर कल इस तरह की घटना न घटे और फिर हर्ष वर्धन जी को आकर यह नहीं कहना पड़े कि साहेब हमने तो पिछले साल यह घोषणा करके गये थे और फिर उसी को रिपीट करें । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब पता नहीं किस वजह से कुछ लोग, जिम्मेदार तो आप भी हैं, पूरा मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है और केन्द्र सरकार भी, ऐसा नहीं है कि वे जिम्मेदार नहीं हैं, मगर टारगेट आपको किया जा रहा है । ठीक है, टारगेट आपको होना भी चाहिए, जैसा आपने काम किया, उसमें टारगेट कर रहा है लोग तो बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है । मगर टारगेट कहां हो रहे हैं हर्षवर्धन, टारगेट कहां हो रही है केन्द्र सरकार, टारगेट कहां हो रहे हैं मंगल पाण्डेय, टारगेट कहां हो रहे हैं सुशील कुमार मोदी, टारगेट कहां हो रहे हैं बजट पेश करनेवाले लोग, टारगेट कहां हो रहे हैं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेकर कार्यक्रम बनानेवाले लोग, इसलिए मैं संक्षेप में इसको कहूंगा कि इसको कतई राजनीति के साथ जोड़ा नहीं जाय, इसको कतई पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं माना जाय, इसमें कतई किसी तरह की चीज को छुपाया जाय । हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और हम सब लोग शर्मसार हुए हैं कि बार-बार, हर साल हमारे बच्चे मर रहे हैं । अब कई कार्यक्रम चलते हैं, मतलब हमको लगता है कि जहां मुख्यमंत्री जी का ध्यान जायेगा वहां प्रायोरिटी फिक्सड हो जायेगी । अब जो बच्चे, गरीब के बच्चे भूमिहीन, मजदूर, पोखरा, डबरा में नहानेवाले लोग, अब तो पोखरा, डबरा भी सूख गया है, उसका अतिक्रमण करके मकान भी लोगों ने बना लिया है कब्जा करके तो जो लोग इस तरह के हैं, वहां सर्वे कराकर फिर अगले बार एसबेस्टस का नहीं बनाइयेगा, देखा हमने अखबार में कि एसबेस्टस का मकान उनका बनाया जायेगा । एसबेस्टस का बनेगा तो दूसरी बीमारी होगी । सुशील मोदी जी, यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने ही कहा कि नहीं, इतने मुल्क ने कहा कि यह खराब है और इतने मुल्क ने कहा कि ठीक है । उससे भी बीमारी होती है तो अगर आप संदेश दुनिया को देना चाहते हैं तो उस एरिया में जो प्रभावित एरिया है, चाहे गोपालगंज का एरिया हो, चाहे सीवान का एरिया हो, चाहे सीतामढ़ी का एरिया हो, चाहे मुजफ्फरपुर का एरिया हो, सीतामढ़ी या दरभंगा का एरिया हो, वहां से सूचनायें कम हैं, मगर इसको आप स्पेशल टास्क बनाकर बिना किसी भेदभाव के आप अभी से बजटरी, आप तो फर्स्ट सप्लमेंटरी, सेकेंड सप्लमेंटरी, थर्ड सप्लमेंटरी लाते हैं, उसमें आप इतनी राशि का प्रावधान

कीजिए, जिसमें मकान का भी निर्माण हो, आई0सी0यू0 का भी निर्माण हो और जितने हमारे पी0एच0सी0 है, एडीशनल पी0एच0सी0 है, उनको आप वेलएक्युट कीजिए । आपके यहां डॉक्टर है ? डाक्टर की कमी है और इसको आपने अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा है, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि क्यूबा की तरह, क्यूबा में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वह सब कुछ करता है- सर्जरी से लेकर असाध्य बीमारी तक का इन्तजाम करता है और वही बीमारी, जो रिसर्च का बीमारी होता है, वह हेडक्वार्टर में जाता है । नीतीश जी कहते, किया भी उन्होंने बहुत सा तो कहते कि हमने पहल किया तो स्वास्थ्य में आप क्यूबा की पैटर्न पर पी0एच0सी0 की व्यवस्था कर दीजिए तो मुझको लगता है कि कुछ कमी आयेगी और जिन लोगों ने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, आप एक टीम बनाइए और टीम बनाकर उसको बैठाइए और कहिए कि एक सप्ताह के अन्दर आप हमको कार्यक्रम बनाकर दो कि उस एरिया में हमको क्या-क्या करना है । तो मैं अंत में फिर यही कहूंगा, भले अभी आप अपनी पीठ थपथपाइए कि तीन सौ के पार, तीन सौ के पार हमलोगों ने वह भी दिन देखा है, इंदिरा जी का भी दिन देखा है, राजीव गांधी जी का भी दिन देखा है, चार सौ कुछ लाने वाले लोग दूसरी बार चले जाते हैं । तो अगर तीन सौ के पार अगर जनता ने आपको बहुमत दिया है तो उसका सदुपयोग गांव के लिए, गरीब के लिए, भूमिहीन के लिए सबके लिए कीजिए । यही कहकर मै माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूँ कि इस चमकी बीमारी को जड़मूल से खत्म करने के लिए कोई-न-कोई उपाय करेंगे और मुझको लगता है कि संतोाषजनक अगर उत्तर आया तब तो विपक्ष मानेगा, संतोषजनक उत्तर अगर नहीं आया, केन्द्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया, यहां के वित्त मंत्री ने क्या किया, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया, इन सब विन्दुओं पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि मैंने कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहा, आप भी गरीब घर से आये, बचपन में अगर हमलोग मर गये होते तो यहां आते थोड़े । उसी तरह बहुत सारी प्रतिभाओं को सिर्फ नेता नहीं, इंजीनियर बन सकता था, टीचर बन सकता था, उसको हमने एक तरह से अपनी नासमझी से और अपनी अकर्मण्ता से या हल्के-फुल्के ढंग से लेने के कारण उन प्रतिभाओं को हमलोगों ने एक तरह से हत्या कर दिया है, इसलिए अगर यह कहा जाय कि इस हत्या के अपराधी आप हैं तो इसको स्वीकार करना चाहिए । यही कहकर, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : और कौन ? आप सदानंद बाबू ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप संवेदनशील हैं और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज चमकी बीमारी से बच्चों की अकाल मृत्यु जो हुई है, इस संदर्भ में आपने कार्यस्थगन-प्रस्ताव स्वीकृत किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-5/राजेश/1.7.19

श्री सदानंद सिंह, क्रमशः बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि संवेदनशील मामले में आपने गंभीरता दिखाई है । अध्यक्ष महोदय, यह चमकी बीमारी आज से नहीं चल रहा है, 2010 से यह चमकी बीमारी चल रही है और प्रत्येक साल कुछ न कुछ इसमें मृत्यु होती ही थी । यह बात अलग है कि इस बार मृत्यु अधिक हुई है, इसके लिए प्रयास भी अधिक किये गये थे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री पिछले चार, पॉच वर्ष पहले आश्वासन भी दिये थे, जिसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, खुद केन्द्रीय मंत्री जी ने स्वीकारा और आज की स्थिति जो है अध्यक्ष महोदय, लगभग 27 जून, 2019 सरकारी ऑकड़ों के अनुसार 180 बच्चों की मृत्यु हुई है, जबकि मृत्यु तो अधिक हुई है और यह बीमारी इस वर्ष 28 मई को देखी गयी मुजफ्फरपुर एरिया में, 28 मई से 10 जून तक काफी बच्चों की म्त्यु हो गयी लेकिन बिहार का कोई मंत्री और खास करके स्वास्थ्य मंत्री 10 जून के पहले एक बार झॉकने भी नहीं गये मुजफ्फरपुर जो मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है कि जाकर देखें तो हमारे सिदिदकी साहब ने ठीक ही कहा कि 17वीं लोक सभा में आप अपार बहुमत से जीते हैं, बिहार में भी इनका गठबंधन 39 सीटों पर जीता, सत्ता के सुख में इन गरीबों को ये लोग देख नहीं पाये । मैंने देखा था टेलिविजन में, हमें अपेक्षा भी थी कि भाजपा के साथ जदयू को भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में लिया जायेगा, जाते वक्त नीतीश बाबू को और बगल में आर0सी0पी0 को देखा था टेलिविजन में, यह लोग हॅसते हुए गये थे, मुसुकते हुए गये थे और लौटे तो चेहरा गंभीर था, आकर इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, यह इनकी बातें हैं लेकिन 10 जून तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार का नहीं जाना, यह अपराध की गिनती में आयेगा कि नहीं, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यह तो अपराधिक कृत्य है और माननीय मंत्री जी गये, तो शायद उस दिन क्रिकेट का मैच हो रहा था, टेलिविजन वाले ने दिखाया कि माननीय मंत्री जी पूछ रहे हैं किसी से कि कितना विकेट गिरा है, कितना रन हुआ है, तो इतने संवेदनशील मामले में आप स्वास्थ्य मंत्री जी गये और 16 दिनों के बाद केन्द्रीय मंत्री गये, मंगल पांडे जी भी गये और भारत सरकार के

स्वास्थ्य राज्यमंत्री भी गये, यों तो स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारत सरकार के दो दिन पहले भी यहाँ आये हुए थे और दो दिनों तक पटना में ही रहे लेकिन उनको फुर्सत नहीं मिली थी जाने की और उस दिन गये, तो देखा गया होगा टेलिविजन में कि केन्द्रीय मंत्री प्रेस कन्फ्रेंस कर रहे हैं और नींद की झपकी ले रहे हैं, वाह रे संवेदनशीलता, दुख होता है, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख होता है, पिछले चार वर्षों में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना, उनके द्वारा दिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं होना दुखद है और ठीक कहा सिदिदकी साहब ने कि एक सुनियोजित ढंग से प्रचार मीडिया जो आज कल बिकी हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी का पक्षधर नहीं हूँ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जवाबदेही बनती है लेकिन उनकी बाद में बनती है, स्वास्थ्य मंत्री जी की पहले बनती है लेकिन कहाँ कोई बोल रहा है, छोटी सी बात होती थी, तो इस्तीफे की बात होने लगती थी, मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखवार को पढ़ा था अध्यक्ष महोदय, उसमें इस बीमारी का काफी विश्लेषण किया गया था और एक कोई दवा है, 10, 15 दिन पहले लेख निकला था दिल्ली के अच्छे चिकित्सक का कि यदि एक घंटे के अंदर वह बीमारी शुरु होती थी, तो हाफ यूनिट दवा अगर उसको इनजेक्ट कर दिया जाता, तो फिर वह मरने वाला नहीं था लेकिन उस दवाई का भी अभाव था, दवाई नहीं थी वहाँ, बेड्स का तो अभाव था ही, आपने देखा कि किस तरह से गर्मी थी और गर्मी के कारण वह बीमारी होती है लेकिन एयरकंडीशन या एयरकुलर वगैरह किस तरह से 10, 15 दिनों के बाद जब मंत्री जी वहाँ गये, तब लगाया गया, तो इतना बड़ा मजाक इस राज्य में हुआ है अध्यक्ष महोदय, हमारे सिदिदकी साहब ने इसपर बेसिक ढंग से कहा है कि जहाँ केन्द्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी दुख प्रकट करते हैं, चिंता प्रकट करते हैं, तो हमको तो नहीं कहना चाहिए था लेकिन पहले ही दिन 17वीं लोक सभा में जो इनका अभिभाषण हो रहा था, तो उसमें यह मामला आना चाहिए था, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन यह बात नहीं आयी, बाद में प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया राज्य सभा में लेकिन शोक प्रकट करने से क्या होगा, यदि पिछले चार वर्षों से दिये गये आश्वासन का कार्यान्वयन नहीं हुआ, तो सिर्फ आश्वासन से तो कार्यान्वयन नहीं हो जायेगा, माननीय विरोधी दल के हमारे उप-नेता सिदिद्की साहब ने ठीक कहा कि जब तक राज्य सरकार इसके लिए संकल्पित नहीं होगी, जब तक राज्य सरकार इसके लिए प्रावधान नहीं करेगी और जब तक राज्य सरकार राजगृह में उड़नखटोला वाली बात को संज्ञान में नहीं लेकर उससे अधिक, तो यह नहीं हो पायेगा । माननीय मुख्यमंत्री जी यह बहुत ही गंभीर

मामला है, आपके पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में इसतरह की मृत्यु नहीं हुई थी, इसको देखना चाहिए और इसे संवेदनशीलता के साथ देखे, यही हमारा आग्रह होगा। धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया, आपने सदन के मान को बढ़ाया है । अध्यक्ष महोदय, यह जो चमकी बुखार जो इनसेफलाईटिस सिंडरम, इस चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में विशेष करके 172 बच्चे का जो मौत हुआ है और अगल बगल के जिला जैसे वैशाली है तथा अन्य जिले भी हैं, तो इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है महोदय, तो जितना इसको दुखद घटना माना जाय और लगता है कि सरकार कहीं न कहीं इस मामले में संवेदनहीन हो गयी थी, यदि संवेदनशील रहती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती महोदय ।

क्रमशः

टर्न-6/सत्येन्द्र/1-7-19

श्री ललित कुमार यादव(क्रमशः): पूरे राज्य में जो स्वास्थ्य का हाल है वह बेहाल है महोदय, हमलोगों की जो सबसे प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए स्वास्थ्य पर लेकिन स्वास्थ्य की जो प्राथमिकता है, कहीं डॉक्टर नहीं है महोदय, कहीं दवा है तो उस दवा की कोई गुणवत्ता नहीं है और विशेषकर के मुजफ्फरपुर में यह जो चमकी बुखार का मामला है यह 2014 में ही उजागर हुआ था और 2014 में केन्द्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था और उस समय केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी यहां आये थे और महोदय आज यह पांच साल के बाद फिर वह दोबारा घटना घटी । महोदय, कहीं न कहीं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की यह पूर्णतः विफलता है। यदि सरकार सजग रहती, संवेदनशील रहती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती महोदय । महोदय, जब स्वास्थ्य ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं है बिहार सरकार का तो हम विभाग की बात नहीं करे तो क्या बात करें । महोदय, सर्वोच्च प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए सबसे पहले स्वास्थ्य का, मनुष्य यदि स्वस्थ्य ही नहीं रहेगा तो आप शिक्षा और अन्य क्षेत्र में आप क्या विकास की बात करियेगा । महोदय, ये स्वास्थ्य में इनका जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफौरमेशन सिस्टम है उसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मृत्यु राज्य सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी विफलता है । महोदय, सफाई, दवाई और आहार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है महोदय । महोदय, अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के

काम को देखे, न्यायालय यदि देखे तो ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए महोदय, ऐसी सरकार को कोई नैतिक आधार नहीं है सरकार में बने रहने का महोदय, इतना बड़ा राज्य में घटना घट गयी महोदय, देश और दुनिया के लोग क्या इस पर टिप्पणी की महोदय और आप कहते हैं सुशासन है, आप कहते हैं चमकता हुआ बिहार है, बढ़ता हुआ बिहार है, यही है बढ़ता हुआ बिहार महोदय, तो हमलोगों को शर्म करना चाहिए और लोग कहते हैं कि जंगल राज और चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं । आप देख आईए, किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में मवेशी, भूसा और चारा रहता है, वहां एक भी डॉक्टर और कर्मचारी नहीं रहते हैं। एक जगह नहीं, सारे पी0एच0 सी0 में हमलोग देखते हैं, हमारे गांव में भी पी0एच0सी0 है महोदय, वहां एक डॉक्टर नहीं रहते है लेकिन लोग आते हैं अस्पताल में और यह एक जगह नहीं है, पूरे राज्य की यही स्थिति है । हम पूरे राज्य का और अपने गांव के अस्पताल से ही एस0के0एम0सी0एच0 का भी हाल जान सकते हैं महोदय, और महोदय इतनी बड़ी घटना 2014 में हो गयी तो उस समय से आप क्या कर रहे थे? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की यही इच्छाशक्ति है । आपने तो कहा कि हम इस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं कि बिहार का नाम हो, बिहार का यही नाम है कि यहां 172 बच्चे की मौत हुई और हमलोग तमाशा देख रहे हैं । महोदय, मुख्यमंत्री जी का मन कब जगा ? वे कितने दिनों के बाद एस0के0एम0सी0एच0 गये, 17-18 दिन बीत गये और इतने बच्चे की मौत हो गयी, उसके वाबजूद भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान वहां नहीं गया और एक दिन के लिए भी अपने बगल के मुजफ्फरपुर नहीं गये । जब 17-18 दिन के बाद सैंकड़ों मौत हो गयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं महोदय, संवेदना व्यक्त करने से नहीं होगा, 172 बच्चे, 200 से ऊपर बच्चे की पूरे राज्य में एक चमकी बुखार से मौत हुई है महोदय, उसके जिम्मेवार कौन लोग होंगे, यह स्पष्ट करना होगा । आज की जनता मांग कर रही है कि 172 से ऊपर 200 बच्चे की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी किनके माथे जायेगा ? क्या यह जिम्मेवारी राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लेंगे ? क्या मुख्यमंत्री लेंगे इसकी जिम्मेवारी ? महोदय कौन लेंगे इसकी जिम्मेवारी और जिम्मेवारी महोदय तय होना चाहिए । जब आपने सर्वोच्च प्राथकिता तय किया सदन में और आप एक सर्वोच्च मांग स्थापित किया है महोदय, आपने आजतक हमलोग कभी भी कार्यस्थगन दिया हो उसको आपने अस्वीकृत ही किया है लेकिन आज आपने सदन में बहस के लिए तय कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। महोदय, इसके लिए आपके प्रति हमलोग आभार प्रकट करते हैं, आसन के प्रति हम आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं महोदय लेकिन

महोदय, आसन का यह भी कर्त्तव्य है कि सरकार यदि विफल हो रही है तो सरकार को सही दिशा दे और सही निर्देश दे सरकार को, क्या हमलोग सदन में, हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं महोदय, हमलोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्या हमलोग सरकार को कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं क्या ? क्या सुपीम कोर्ट जब फटकार लगायेगी और सरकार को बर्खास्त करेगी तो उस दिन का हम इंतजार करते रहेंगे महोदय, क्या हम उस दिन का इंतजार करें ? महोदय, इतनी बड़ी घटना में अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ, सुशील मोदी जी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इसकी नैतिक जवाबदेही नहीं ली, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ महोदय, इससे शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है महोदय । महोदय, क्या सरकार का हम चेहरा देखने के लिए यहां बैठे हुए है, सरकार को यदि मैनडेट मिला है महोदय, चाहे वह बैकडोर से ही क्यों न आये हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों न हों, इनकी जिम्मेवारी है बिहार की जनता के स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का लेकिन अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन्हीं की सरकार केन्द्र में भी हैं और बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार है, डबल मंत्री हैं, ट्रिपल मंत्री है । एक राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी अलग से है, अश्विनी चौबे जी क्या बोलते हैं, जब इतने गंभीर विषय पर मीटिंग होती है तो वे सो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी क्रिकेट के मैच का स्कोर पूछते रहते है। महोदय, स्वास्थ्य विभाग यदि जनता के स्वास्थ्य की, जो 2019 में इनका ..

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपस में टोकी टोकी कर के इस विषय की गंभीरता नहीं घटाईए ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, 2014 में 100 बेड का आई0सी0यू0, एन0आई0सी0यू0, पी0आई0सी0यू0 जो बनाने की घोषणा की गयी परन्तु आजतक उसकी उपलब्धता शून्य है महोदय, इस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे बड़ा दुखद घटना नहीं हो सकती है, हम भी इस पर चिन्तित हैं । महोदय, चिन्तित होने से नहीं होगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी घटना घट गयी महोदय और आपने क्या संज्ञान लिया, आपके स्तर से क्या कार्रवाई हुई, महोदय इतना ही नहीं यहां राष्ट्रीय मानक जो है प्रति 1000 व्यक्ति पर एक चिकित्सक की उसकी जगह राज्य में 28391 व्यक्ति पर एक चिकित्सक है महोदय, तो इसमें इतना बड़ा अंतर का गैप है महोदय । महोदय, राज्य में 11373 डॉ0 की जगह मात्र 6712 डॉ0 ही कार्यरत हैं महोदय । महोदय, राज्य में 4045 लोग की आबादी पर सिर्फ एक बेड उपलब्ध है महोदय, इस राज्य में 1210 सब सेंटर 131 पी0एच0सी0 तथा तथा 89 सी0एस0सी0 की कमी बनी हुई महोदय । महोदय, जी0डी0पी0 में

आप कहते हैं 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत ही स्वास्थ्य पर महोदय खर्च हुआ है । महोदय, इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विफलताएं कितनी गिनायें। महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार पूर्णत: विफल है और हमलोग एक ही मांग करते हैं महोदय कि ये जो बच्चे की मौत हुई है इसकी जिम्मेवारी किन्हीं को लेनी चहिए महोदय । महोदय जिम्मेवारी चाहे राज्य सरकार ले या केन्द्र सरकार ले और यदि यह जिम्मेवारी सरकार नहीं लेती है महोदय और कोई निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो इससे नीचे हमलोग मानने वाले नहीं है। हमलोगों का सड़क से सदन तक का आन्दोलन चलता रहेगा महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इतने संवेदनशील मामले को आपने सदन में उठाने का अवसर दिया है, सदन में चर्चा करने का और सरकार से उत्तर दिलवाने के लिए इसके लिए आपका हम आभार प्रकट करते हैं महोदय।

श्री अत्रिमुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, संवदेनशील मुद्दे पर आज कौगनिजेंस सदन ने भी लिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इससे आसन की कहीं न कहीं गरिमा जरूर बढ़ी है । हमारे नेता आदरणीय सिद्दिकी साहब ने आपके समक्ष चमकी बुखार से हुई मौत के बाद लोगों के मन में जो प्रश्न तैर रहे थे उन सबालों पर किन किन कमियों के कारण यह हुआ उस पर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया महोदय । मैं इन बातों को नहीं दोहराऊंगा लेकिन दो तीन बात मैं जरूर कहूंगा कि सात सदस्यीय टीम भी आयी थी भारत सरकार की तरफ से यह जानने कि स्वास्थ्य की स्थिति अद्यतन क्या है राज्य के अन्दर में, अस्पताल में क्या है उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट जो दी गयी है उसकी रिपोर्ट इस बात का पूरा पूरा परिचायक है कि राज्य की जो सरकार है या उसके जो कस्टोडियन हैं वे गंभीर नहीं है और इस गंभीरता को आपको समझनी पड़ेगी । महोदय, यह एक क्रिमिनल नेगलीजेंसी है और जिस दिन से यह घटना घटी है तो क्रिमिनल नेगलीजेंसी के लिए रिस्पौंसब्लिटी किसके ऊपर फिक्स की जायेगी।(क्रमश:)

टर्न-7/मधुप/01.07.19

...क्रमश:...

श्री अत्रिमुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : आदरणीय सिद्दिकी साहब ने, आदरणीय सदानन्द बाबू ने, ललन जी ने, महबूब आलम जी ने भी इन बातों को कहा कि आखिर रिसपौंसबलिटी कौन लेंगे ? अगर किसी थाने में भी कोई घटना होती है तो

थानेदार ससपेंड हो जाते हैं, कहीं पर किसी की संलिप्तता होती है तो वे ससपेंड हो जाते हैं । प्रथम दृष्टया यह आपराधिक मामला है, इतने बच्चों की मौत, उनका आक्रांत मेडिकल पार्टियों को सोने नहीं दे रही है, उनके रूदन-क्रंदन में आपकी जो असफलता है, कहीं न कहीं आपको इंगित कर रहा है ।

महोदय, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त कर दिया, क्रिकेट खिलाड़ी को चोट आती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं प्रधानमंत्री जी, करना भी चाहिए, कथा सुनाने वाले की मौत होती है तो ट्वीट करते हैं, करना चाहिए, यह संवेदना का मानक है, हम उसके प्रति आस्था दिखाते हैं लेकिन महोदय, लम्बे दिनों के बाद, इतने दिन बीत जाते हैं, जब टैग करता है बिहार का लोग ट्वीटर हैंडल पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इतने बच्चे की मौत के बाद भी आप चुप क्यों हैं, लगातार जब ट्वीटर हैंडल पर आपके टैग किए जाते हैं तब जाकर सदन में आकर राज्य सभा में आप बातें रखते हैं । आपकी रिसपौंसबलिटी है । हर्षवर्द्धन जी के सवाल पर, 2014 में जो बयान दिया, उसको ही कट-पेस्ट आपने 2019 में कर दिया । वही पुरानी चीजों को आपने परोस दिया । क्या आपकी रिसपौंसबलिटी नहीं है क्या ? है । इस राज्य में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यू0एस0पी0 पर सवाल खड़े हुए हैं तो इस्तीफा लोगों ने दिया है लेकिन इन्होंने स्वीकारा नहीं है । आज तो सवाल सामने खड़ा है, विवशता नहीं चलेगी । कहीं न कहीं प्रथम-दृष्टया जिनके उपर रिसपौंसबलिटी है, जो कस्टोडियन हैं डिपार्टमेंट के, उनको लेनी पड़ेगी । नैतिकता के आधार पर लें चाहे जिस रूप में लें, आपका सम्मान और बढ़ जायेगा कि आपने स्वीकार किया कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत कहीं न कहीं हमारे डिपार्टमेंट की लापरवाही से हुई है, यह हमारी चूक है । इसके बाद, और जिनके उपर जिम्मेवारी होगी उनपर भी सवाल खड़े होंगे । सवाल यह है कि इसके दूरगामी जो रोकथाम के उपाय हो सकते हैं, ठीक कहा आदरणीय सिद्दिकी साहब ने कि इस स्वास्थ्य महकमे पर, लगातार 2006 से लेकर 2019 तक जो बच्चे की मौत हो रही है, बच्चे की मौत की रोकथाम के लिए आपने बजटरी प्रोवीजन स्पेशल किया क्या ? आपने इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया क्या ? क्या कर सकते हैं ? आदरणीय ललित जी ने जो कहा कि पी0एच0सी0 के जो हाल हैं, मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि जो सुझाव आदरणीय सिद्दिकी साहब ने दिया है, उस स्तर का पी0एच0सी0 राज्य के अन्दर होना चाहिए । अस्पताल बन जाय, विद्यालय बन जाय, सिर्फ उसी से सुधार हो जायेगा, ऐसा मानना हमारी समझ से उचित नहीं है । जबतक उसके अन्दर में

क्वालिटी नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे तो कहाँ से आप उसके निराकरण का उपाय सोच सकते हैं ? ठीक कहा कि सभी पी0एच0सी0 के हाल बदहाल हैं, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी बनती है । अगर कहीं लोकतंत्र में लोग लोक-लाज की बात करते हैं, हम तो पुराने लोगों से सीखते हैं, जो वरिष्ठ यहाँ नेता लोग हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनके सदन के अन्दर में लम्बे अनुभव रहे हैं, उनका कहना है कि लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है, तो लोक-लाज कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है । आपको आगे बढ़कर नैतिकता का तकाजा मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि राज्य के अन्दर यह मेसेज जाय, देश में मेसेज जाय कि बच्चों की मौत पर वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी असफलता को मानते हुए इस्तीफा दिया । आपका स्तर और बढ़ जायेगा, राजनीतिक कद भी बढ़ जायेंगे अगर आप यह करते लेकिन सात दिन के बाद, जानते हैं, क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं ? आप जैसा गम्भीर व्यक्ति बच्चों की मौत पर क्रिकेट का स्कोर पूछे, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है । भारत सरकार के आपके स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रेस कांफ्रेंस में सो जाते हैं ? बच्चों की मौत पर कहते हैं कि हम मनन कर रहे हैं, यह कैसा मनन जिसपर सकारात्मक पहल करके आपने दिखाया कुछ नहीं ? कोई पहल में तत्परता आपने नहीं दिखाई ।

प्रधानमंत्री जी जाकर सदन में घोषणा करते कि जो भी विशेष सहायता होगी, बिहार को हम स्पेशल पैकेज देकर वहाँ के स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हमें लगता है कि वह ज्यादा सार्थक होता । उससे गम्भीरता बढ़ती, उनके बयानों की गम्भीरता बढ़ती लेकिन कहीं न कहीं हम असफल रहे हैं । कई मंत्री रामनन्दन बाबू, रामानन्द सिंह जी जैसे लोगों ने छोटी घटनाओं पर भी इस्तीफा दिया है, मंजू वर्मा भी इस्तीफा दे चुकी हैं, जब विपक्ष ने सवाल खड़े किये तो अभी तक चुप्पी क्यों ? यह यक्ष प्रश्न है आपके सामने । इन प्रश्नों का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है, सदन भी जानना चाहता है कि आखिर किन कारणों से, कुछ तो मजबूरियां रही होंगे वरना आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता ।

महोदय, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जो गम्भीरता दिखाई है सदन की गम्भीरता है, यह पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है, यह सवाल कोई राजनीतिक तकाजा या दृष्टिकोण से नहीं, यथार्थ के दृष्टिकोण से है । आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस गम्भीरता को हर हाल में बहाल रखा है और इससे आसन का कहीं न कहीं मान और सम्मान और बढ़ेगा आने वाले कल में । सिद्दिकी साहब ने जैसा कहा कि कभी-कभार ऐसे मौके होते हैं जब राज्य के अन्दर और

सदन के अन्दर में कार्य स्थगन मंजूर किये जाते हैं । आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर हुआ है, बच्चों की मौत पर मंजूर हुआ है। इससे बड़ा सवाल और कुछ नहीं हो सकता है । इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि निश्चित तौर पर इसकी गम्भीरता को देखते हुए इन सारे प्रावधानों के प्रति, सारे चूकों के प्रति, सब पर बिन्दुवार तरीके से, तथ्यात्मक ढंग से इन बातों पर सदन में प्रतिपक्ष को जवाब मिलेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद आसन के प्रति, सभी के प्रति ।

अध्यक्ष : और कोई सदस्य बोलना चाहते हैं ? नहीं तो फिर मैं सरकार को रेसपौंड करने कहूँगा ।

श्री विजय शंकर दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आज आपने राज्य के महत्वपूर्ण मसले पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत करके लोकतंत्र को मुखरित किया है । वैसे तो आपने अध्यक्ष की हैसियत से राज्य के हित में, सदन के हित में बहुत सारे परिवर्तन किये हैं लेकिन आज लम्बे समय के बाद 181 बच्चों की मौत के मसले पर देश चिंतित है, लोक सभा चिंतित है, राज्य सभा चिंतित है, ऐसे अवसर पर राज्य के विधान सभा में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराकर आपने सराहनीय कदम उठाया है ।

महोदय, चर्चा काफी देर से हो रही है, मैं सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप संवेदनशील हैं, वैसे तो देश के सबसे ज्यादा काम करने वाले, 22 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री ही हैं, प्रचारित है ऐसा, नीतीश कुमार जी भी राज्य के एक-एक विषय को देखने का काम करते हैं, यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं । मैं एक दिन गया पशुपालन विभाग में, अध्यक्ष महोदय, अनबोलतों के इलाज के लिए जो नई व्यवस्थाएँ की गई हैं तो सचमुच में मुझे लगा कि एक समय में यह डिपार्टमेंट जो बहुत बदनाम था, आज राज्य में कुछ काम ऐसा हो रहा है । लेकिन वैसे मुख्यमंत्री जी का विचलन कैसे हुआ ? पिछले समय यह घटनाएँ घटीं मुजफ्फरपुर में, उपाय किये गये थे कुछ, इतना वृहद रूप नहीं लिया । भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया, भारत सरकार के भी मंत्री ने कहा कि प्रोग्राम देंगे । भारत सरकार ने किया या नहीं किया, जिम्मेदारी उनकी भी है लेकिन ऐसे अनेक काम हैं जो भारत सरकार पैसा नहीं देती है फिर भी राज्य सरकार की ओर से नीतीश जी करते हैं । इनका ध्यान क्यों नहीं गया ? इसीलिए महोदय, सत्र के प्रथम दिन कांग्रेस ने अवधेश बाबू के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी से

इस्तीफा माँगा और मुख्यमंत्री जी से भी इस्तीफा माँगा । राज्य के प्रमुख इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ।   ...क्रमशः ...

टर्न-8/आजाद/01.07.2019

.... क्रमशः ....

श्री विजय शंकर दूबे : और 15 साल से नीतीश जी जिन्दाबाद सुन रहे हैं तो मुर्दाबाद सुनने के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा । वो कौन सुनेंगे, 181 बच्चे मर गये, गरीबों की बात सब लोग करते हैं, सभी दल के लोग करते हैं । पिछड़े हल्कों की बात, सुधारने की बात सब लोग करते हैं । आज तो 15 साल से आपकी हुकूमत है, उन बच्चों के बीमारी पर अनुसंधान होना चाहिए, उपाय किये जाने चाहिए थे, जिसमें लेप्सेज हुए हैं और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी केन्द्र सरकार इसके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविजन करे या न करे लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रथम जिम्मेदारी है आपकी और आप उसके उपाय करें और ऐसी घटनायें कुपोषित बच्चों की मौत निरीह लोगों की मौत न हो, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपके मुझे समय दिया, इसके लिए आसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्येदव राम और उसके बाद फिर मो0 नेमतुल्लाह । दोनों 5-5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद सरकार का रिसपौंस होगा ।

श्री सत्यदेव राम : इस गंभीर विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस विषय को भी आपने स्वीकार किया है, इसके लिए भी मैं आपका आभारी रहूँगा ।

अभी बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में जिन बच्चों की मौत हुई है, जो आंकड़ा आया है, वह अपर्याप्त है । आंकड़े 287 है महोदय, जो लोग विभिन्न जगहों पर इलाज कराये हैं, वह आंकड़े आपके पास नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसके पहले जाँच करा ली जाय । दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जो अभी चमकी बुखार की चर्चा हो रही है और 10 वर्षों से यह बीमारी बिहार में है लेकिन सरकार उसके प्रति लापरवाह है । यह सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि अपराधिक लापरवाही है जिसमें प्रतिवर्ष इतने बच्चे मर रहे हैं और इस साल सबसे ज्यादा बच्चे मरे हैं । जो सर्वे हुआ है, वह सर्वे क्या कहता है महोदय, वह सर्वे कहता है, सरकारी सर्वे कहता है कि 77 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहा है, यह एक गंभीर मसला है महोदय । स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आया है लेकिन यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पूरे तौर पर

पोल खोल देता है सबका साथ और सबका विकास नारे का, पूरे तौर पर पोल खुल जा रहा है कि 77 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है । 91 प्रतिशत परिवारों के पास कोई राशन कार्ड नहीं मिला है महोदय और सबसे भयावह स्थिति है कि 61 बच्चे जो मरे हैं वे बीमारी के पहले वे खाना नहीं खाये थे, यह कितनी शर्मनाक बात है और इससे शर्म से हमलोगों का माथा झुक जाता है कि आज भी हमारे राज्य में बिहार में हमारे बच्चे भूखे सोते हैं । इस सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा, यह शर्म की बात है महोदय । बहुत सारी बातें तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा, मीडिया ने बताया, मंत्री लोगों ने बताया, सांसद लोगों ने बताया कि यह कुपोषण का मामला है, सफाई का मामला है, महोदय कैसे सफाई रहेगी ? मामूली जगह पर कम जगह में ज्यादे परिवार रहेगा तो कैसे साफ रहेगा ? हमलोग लगातार मांग करते रहे हैं कि बिहार की गरीबों को कम से कम 10 डिसमिल जमीन दी जाय । इसको आप इग्नोर करते जा रहे हैं, इस बात को झुठलाते जा रहे हैं । गरीब वोट दिया है, मुझे मालूम है । आपको बिहार का सारा सीट मिला है एक सीट छोड़कर । आपकी जीत हुई है, कहियेगा तो आपको पूरा धन्यवाद देंगे लेकिन वोट जो मिला है, इसके लिए नहीं कि बिहार के 287 बच्चे मरे, इसके लिए आपको जनादेश नहीं मिला है । आपका काम करने के लिए मिला है, आपको प्रेस कॉफ्रेंस में जाकर के सोने के लिए नहीं मिला है, आपको क्रिकेट का विकेट पूछने के लिए नहीं मिला है, अगर आपके अन्दर संवेदना होती तो आप यह पूछते हैं कि अभी कितने बच्चे बीमार हैं और उनको कैसे इलाज करके जल्दी ठीक करने की जरूरत है, उनको कैसे ठीक किया जाय, यह काम करने की जरूरत है । लेकिन आपके अन्दर गरीबों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है, जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी संवेदना रखने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी, हमारे जिले से ही आते हैं, अच्छी उनसे हमारी बातचीत होती है लेकिन आज यह पूरा हालात को देखकर के स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यदि आपके अन्दर राज्य के गरीबों के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी है, थोड़ी सी भी राजनीतिक नैतिकता है तो आज इस सदन में आप घोषणा करिए कि मुझसे गलती हुई है, अपराधिक लापरवाही हुई है और मैं इस्तिफा देता हूँ ताकि हम राजनीति के मानक को थोड़ा और आगे बढ़ा सकें । इसको अगर आप नहीं सोचेंगे कि इतने बच्चे मरे हैं, वोटर नहीं हैं इसलिए हमारी जवाबदेही नहीं है । ये भी वोटर होंगे, आप विश्वास रखिए, आज ये वोटर नहीं हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इसलिए उनको मरने

नहीं दीजिए, आगे ये लोग ही वोटर लिस्ट में होंगे और ये वोट देंगे । वोट का व्यापार ......

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राय : मैं साफ शब्दों में मांग करता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तिफा दें, अगर नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बर्खास्त करें और जितने बच्चे मरे हैं, उन सभी परिवारों को 10-10 लाख रू0 मुआवजा दी जाय और जहां इस तरह की गंदगी फैली है, जहां पर इस तरह का कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, वहां पर स्पेशल सर्वे चलाकर के बिहार के सभी गरीबों को 10 डिसमिल जमीन और खाद्य सुरक्षा में उनका नाम और हर महीने उन्हें अनाज देने की गारंटी करें, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में इन बच्चों की मौत को रोकने में कोई उपाय नहीं है । इसलिए सरकार नीयत साफ करें गरीबों के प्रति और गरीबों का काम करें । सिर्फ वोट मिल गया है, इसके लिए नहीं कि ये बच्चे मरें और हम ऐश फरमावें, इसके लिए नहीं मिला है। वोट काम करने के लिए मिला है, आप काम में लगिए, अगर आप काम नहीं करेंगे, आपको पता है कि जिन लोगों ने जैसा किया, वो आज भोग रहे हैं, इसलिए आपको भी उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : मो0 नेमतुल्लाह ।

मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, आज आपने एक मिसाल कायम किया, आज आपने कार्य-स्थगन को स्वीकृत करके हम सबका, विधान सभा का मान-सम्मान बढ़ाया है महोदय ।

महोदय, ऐसे मसले पर, एक ऐसे गंभीर मसले पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं । वो बच्चे जो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से उनकी मौत हो गई । कौन बच्चे थे महोदय, ए0सी0 में बैठकर रहने वाले बच्चे नहीं थे । अगर हमारे आपके बच्चे होते तो मुख्यमंत्री अगर बीमार पड़ते, अगर चमकी बुखार होता, एक्युट इनसेफलाइटिस सिंड्रोम होता तो मुख्यमंत्री जी एयर एम्बुलेंस से ले जाकर के दिल्ली में इलाज करा देते ।

...... क्रमशः ......

टर्न-9/शंभु/01.07.19

श्री मो0 नेमतुल्लाह : क्रमशः..लेकिन वे बच्चे गरीब थे, मजलूम थे, मुसीबत के मारे हुए थे । वे रात को भूखे पेट सोये हुए थे और सुबह उठकर दिन के उजाले में अपने भूख को मिटाने के लिए बाग-बगीचों, लीची के बगानों में वह सड़ेपचे लीची और आम खाकर के

अपने-आप को बीमार कर लिये लेकिन उनको पूछनेवाला कोई नहीं है । मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में बना और वहां कितने बच्चों को जला दिया गया इसको भी आपने टी0वी0 में देखा होगा- लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को जला दिया गया । वह कौन सी लाश थी, बच्चों की लाश थी, लावारिश लाश थी उसको जला दिया गया? इसके बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री जी को । माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अनुसरण करना चाहिए माननीय मंत्री जी को जब रेल दुर्घटना होती है तो आप एक छोटी सी दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते हैं पार्लियामेन्ट में मंत्री पद से, लेकिन इतना बड़ी घटना हो गयी है तो क्या आपके मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते हैं ? बहुत सी चर्चा हुई, बहुत सी बात लोगों ने यहां पर कहा चमकी बुखार के सिलसिले में, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यह इस साल का मामला नहीं है । यह पिछले कई सालों से इस तरह की बीमारी होते आ रही है, लेकिन कभी सिरियस नहीं हुए हम इस मसले पर - स्वास्थ्य विभाग हमारा मरा हुआ विभाग है । प्रधानमंत्री जो कह के गये कि बिहार बीमारू राज्य है और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने साबित कर दिया कि सही मायने में बिहार एक बीमारू राज्य है और इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेन्ट में की है और कहा कि चूक है । जब चूक हुई तो किससे चूक हुई ? माननीय मुख्यमंत्री जी से चूक हुई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चूक हुई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से चूक हुई ? चूक हुई स्वास्थ्य मंत्री जी तो आप इस्तीफा कर दीजिए । जब मंजू वर्मा इस्तीफा कर सकती है, आप उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं तो मुजफ्फरपुर के कांड पर आप मंगल पाण्डेय जी क्यों नहीं इस्तीफा कर सकते हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं उनका इस्तीफा मांग सकते हैं ? आपको मांगना चाहिए इस्तीफा चूंकि यह एक बहुत बड़ी घटना है । इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्नीजेंस लिया, पार्लियामेन्ट में इसपर बहस हुई, हाईकोर्ट ने नोटिस किया और सबसे बड़ी बात है कि आपने इसको स्वीकृत करके इसपर चर्चा कराने के लिए लाया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इसका एक परमानेन्ट निदान ढूढ़ना चाहिए इस मसले का चूंकि आयेदिन हमारे बच्चे का- आपके बच्चे बड़े-बड़े हॉस्पीटलों में जाकर इलाज करा लेते हैं । पटना में होगा तो पारस हॉस्पीटल में चले जाते हैं और ज्यों ही पारस हास्पीटल में गया तो मीटर डाउन होने लगता है । वे गरीब के बच्चे कहां जायेंगे, जब हॉस्पीटल में जाते हैं तो बेड नहीं है । आपके केन्द्रीय मंत्री कहते हैं एलान करके

2014 में चले जाते हैं फिर 2019 में जब आते हैं तो उसी का एलान करते हैं वही चीज दुहराते हैं तो यह कब तक होगा ? कब आप इसका सुधार कीजिएगा ? माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने निगरानी में एक बहुत जबर्दस्त कमिटी बनाइये और सदन की कमिटी से इस विषय की जाँच कराइये । मुख्यमंत्री जी डिस्मिश कीजिए अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है- नहीं तो हम कहते हैं संवेदनशील हैं अगर वे आपका अनुसरण करें तो खुद ही इस्तीफा करके साबित कर दें कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेलमंत्री से इस्तीफा किया तो मैं स्वास्थ्य मंत्री के पद से यहीं इसी सदन में इस्तीफा करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब सरकार का रेस्पोंस ।

(व्यवधान)

अब छोड़ दीजिए । क्या है एक मिनट बोल लीजिए । एक लाइन बोल लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, चमकी बीमारी से जो प्रोब्लम है उसमें जो छूट रहा है, सारे वक्ता ने बोल दिया है मैं आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो मरे उनको 4 लाख उन्होंने कहा लेकिन जो 40 परसेंट से 80 परसेंट तक विकलांग होंगे, दिव्यांग होंगे उनके बारे में चर्चा करता हूँ । बस इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : आप लिखित दे दीजिएगा, अपना सुझाव दे दीजिएगा ।

(व्यवधान)

क्या ? भाई वीरेन्द्र जी और सिद्दिकी जी, मेरे ख्याल से....बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : इसपर माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉग्नीजेंस लेना चाहिए और इसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सिद्दिकी साहब और भाई वीरेन्द्र जी, आप सब जानते हैं कि आसन या आप, सरकार की जो सामूहिक जिम्मेवारी होती है उसके तहत कौन मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोलें हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं । जो उनके मंत्री हैं मैं नहीं जानता हूँ

कौन बोलनेवाले हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी बोलेंगे । मुख्यमंत्री जी तो संज्ञान ले रहे हैं जो पूरी चर्चा में यहां उपस्थित हैं । सरकार का रेस्पोंस ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में ए0इ0एस0 से होनेवाली मृत्यु आहत करनेवाली है । सरकार इस विषय पर पूरी तरह से संवेदनशील है । माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय पर अवगत कराना है कि राज्य सरकार ने ए0इ0एस0 के......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय मंत्री जी । भाई वीरेन्द्र जी, हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि आप सबने अत्यंत लोक महत्व के मुद्दे को उठाया है और पूरे सदन ने गंभीरता से आप सबों की बातों को सुना है । अब सरकार की बात सुनने में कोई अव्यवस्था करके इस मुद्दे के महत्व को कमतर नहीं करिये, इसको चलने दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : सरकार इस विषय पर पूरी तरह से संवेदनशील है । माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय पर अवगत कराना है कि राज्य सरकार ने ए0इ0एस0 के नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास किये हैं । वस्तुतः ए0इ0एस0 बीमारी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह बीमारियों का समूह है जिसके प्रारंभिक लक्षण एक समान होते हैं । ए0इ0एस0 बीमारी का प्रकोप मुजफ्फरपुर जिले में 1995 से ज्ञात है । इसके इलाज हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यथा नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली, ऑल इंडिया इन्सटीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, दिल्ली, राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्सटीच्यूट अगमकुआं, पटना, सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल अटलांटा अमेरिका द्वारा समय-समय पर शोध किया गया, किन्तु किसी भी निश्चित कार्य की जानकारी नहीं पायी जा सकी । बीमारी का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ता गया ।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम भी बोलेंगे । ये कुछ जानकारी रख रहे हैं सुन लीजिए उसके बाद हम भी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे महबूब जी, आप जरा अपने नाम पर भी गौर करिये और सरकार को उत्तर देने दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : बीमारी का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ता गया । फलतः 2012 में भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा बिहार सहित कुल 5 राज्यों के 7 जिलों को आवश्यक विरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया इन 60 जिले में से बिहार के 15 जिले यथा- पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा एवं नालन्दा सम्मिलित है । मंत्री समूह द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में ए0इ0एस0 मरीजों को चिकित्सा सुविधा हर स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु निदेशानुसार स्डैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज्योर की संरचना की गयी एवं वर्ष 2013 एस0ओ0पी0 के आधार पर ए0इ0एस0 के मरीजों की चिकितसा एवं स्वास्थ्यकर्मी द्वारा जागरूकता की जाती रही है । एस0ओ0पी0 के आधार पर ही बीमारी के प्रकोप माह जून के पूर्व से ही ए0इ0एस0 प्रभावित 12 जिलों यथा पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सदर अस्पतालों एवं इन जिलों के अन्तर्गत पड़नेवाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों एवं दवाओं की व्यवस्था की जाती रही है । बिहार में मस्तिष्क ज्वर का मुख्य केन्द्र मुजफ्फरपुर है जबकि जापानी इन्सेफलाइटिस का गया है।

क्रमशः

टर्न-10/ज्योति/01-07-2019

क्रमशः

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मुजफ्फरपुर जिले में तापमान एवं आद्रता के बढ़ने के साथ ही मस्तिष्क ज्वर के मरीज प्रतिवेदित होने लगते हैं जो बरसात शुरु होते हुए समाप्त हो जाते हैं जबकि गया जिला में बरसात शुरु होते हुए जापानी इन्सेफेलाईटिस के मरीज प्रतिवेदित होने लगते हैं जो जाड़े की शुरुआत के साथ ही समाप्त हो जाते हैं । विगत वर्षों में मजफ्फरपुर में ए.इ.एस. बीमारी की पहचान हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न शोधों में किसी विशेष कारक की पहचान नहीं की जा सकी है । मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के पहचान और उसके जो

लक्षण हैं उसमें सरदर्द, तेज बुखार आना जो कि पॉच सात दिनों से ज्यादा का न हो अद्‌र्ध चेतना एवं मरीजों में पहचानने की क्षमता नहीं होना भ्रम की स्थिति में होना बच्चे का बेहोश हो जाना, शरीर में ऐंठन चमकी होना अथवा पैर में थरथराहट होना पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चे का शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होना । इस वर्ष सर्वाधिक मृत्यु हाईपोग्लेसिमिया जो ए.ई.एस. का ही लक्षण है से हुई है जिसका कारण प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी, आद्रता एवं बारिश का नहीं होना है । बीमारी के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए आम जन में यह संदेश दिया जा रहा है कि बच्चे को धूप से बचायें क्योंकि इसके कारण डिहाईड्रेशन की शिकायत होती है फलस्वरुप बच्चों की रुचि भोजन एवं पानी में कम हो जाती है और हाईपोग्लेसिमिया उत्पन्न होता है साथ ही आमजनों को बच्चों को दिन में दो बार स्नान कराने और रात में खाली पेट नहीं सोने देने सोने के समय नींबू पानी शक्कर अथवा ओ.आर.एस. के घोल पिलाने के संबंध में प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाता रहा है इसके अतिरिक्त बच्चों में चमकी बुखार शारीरिक अथवा मानसिक संतुलन में कमी होते ही तुरत नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में भेजने के संबंध में अवगत कराया जाता रहा है जिससे कि प्राथमिक उपचार के पश्चात आवश्यकता होने पर 102 एम्बुलेंस से नि:शुल्क मरीज को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जा सके । ए.ई.एस. नियंत्रणार्थ गतिविधियों की जो विवरणी है भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा वर्ष 2012 के दिए निर्देश के आलोक में क्षेत्र विशेष एवं लीची पैदावार वाले जिले को ध्यान में रखते हुए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर वर्ष 2013 में तैयार किया गया जिसके आधार पर मरीजों की चिकित्सा एवं जागरुकता हेतु प्रचार प्रसार किया जाता रहा हैं । विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं क्षेत्र से प्राप्त फीड बैक के आधार पर पुन: वर्ष 2018 में एस.ओ.पी. को संशोधित करते हुए सभी जिलों को नया एस.ओ.पी. 2018 उपलब्ध कराया जा चुका है जिसकी एक प्रति मैं दिखाना चाहता हूँ । ये एस.ओ.पी. 2018 है । इसके आधार पर काम किया जाता है । मैं सारी जानकारी अपने सभी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्यों हड़बड़ी में हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, इससे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के वेब पोर्टल www.health.bih,nic.in के operational guideline

section पर भी पूर्व की तरह अपलोड कर दिया गया है । जे.ई./ए.ई.एस. के क्लिनिकल मैनेजमेंट के तहत 656 एस.ओ.पी. जो मैं दिखा रहा हूँ 2018 की प्रतियाँ सभी जिलों के चिकित्सा पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है । प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महोदय, मैं इस वर्ष की चर्चा कर रहा हूँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एस.ओ.पी. के आधार पर ए.इ.एस. जे.ई/ए.इ.एस. चिन्हित 12 जिलों के 222 स्वास्थ्य केन्द्रों यथा सभी पी.एच.सी., सभी अनुमंडलीय अस्पताल, सभी रेफरल अस्पताल, सभी सदर अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रथम चक्र गैप असेसमेंट 8 अप्रील से 11 अप्रील 2019 तक किया गया जिसकी समीक्षा प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23-05-2019 को की गयी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

तत्पश्चात् संपुष्टि हेतु द्वितीय चक्र गैप असेसमेंट 25 से 28 मई 2019 को किया गया जिसकी समीक्षा पुनः प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 मूई 2019 को गयी समीक्षोपरान्त पाया गया कि सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं । इस प्रकार जे.ई./ए.ई.एस. नियंत्रणार्थ आवश्यक अनुशंसित दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता बीमारी के प्रकोप से पहले कर दी गयी है। राज्य के चिन्हित 29 जिलों के 445 एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों एवं 472 आयुष चिकित्सकों को ए.ई.एस. के ट्रीटमेंट प्रोटोकोल पर रिऔरिएण्टेशन ट्रेनिंग दिया जा चुका है सभी सरकारी अस्पतालों में इस रोग के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभाग एवं जिला अस्पताल में अलग से आई.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. वार्ड की स्थापना की गयी है ताकि ए.ई.एस. के मरीजों का त्वरित उपचार किया जा सके । जे.ई./ए.ई.एस, ए.ई.एस. मरीजों का लेप्रोस्कोपिक टेस्ट भी आर.एम.आई.एम.एच. पटना में 2018 से प्रारम्भ कर दिया गया है । वायरल एवं बैक्ट्रिया टेस्ट के सैम्पल की क्रौस चेकिंग 2014 से आर.एम.आर.आई. में करायी जा रही है । चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक जीवन रक्षण दवाओं का स्थानीय व्यवस्था से क्रय एवं भंडारण किया गया है । आवश्यकतानुसार प्रभावित जिलों में एम.बी.बी.एस. चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सक एवं एम्बुलेंस

की प्रतिनियुक्ति की गयी है । राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों यथा पी.एम.सी.एच. पटना एन.एम.सी.एच., पटना एवं एस.के. एम.सी.एच.,मुजफ्फरपुर, मगध मेडिकल कॉलेज, गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दराभंगा, एवं जे.एल.एम.एन.सी.एच.,भागलपुर को जे.ई/ए.इ.एस. नियंत्रणार्थ भारत सरकार द्वारा सेन्टीनल साईट्स के रुप में चयनित है । इन चिकित्सा महाविद्यालयों में नि:शुल्क की जॉच के लिए एलीशा टेस्ट कीट उपलब्ध है इसके अतिरिक्त कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, महावीर वात्सल्य अस्पताल, पटना, आर.एम.आर.आई. पटना एवं आई.जी.आई.एम. एस. पटना को नि:शुल्क जे.ई. की जॉच के लिए एलीशा टेस्ट कीट उपलब्ध कराया गया है । मरीजों हेतु नि:शुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है एम्बुलेंस के अलावा अन्य वाहन से अस्पताल आने पर 400 का प्रावधान रखा गया है । आशा द्वारा पैम्फलेट का वितरण किया जाता रहा है साथ ही आशा एवं आंगनवाड़ी सेविका द्वारा ओ.आर.एस. का वितरण किया जाता रहा है । मृत मरीजों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख मात्र देने का प्रावधान किया गया है । जे.ई.एस. नियंत्रणार्थ बिहार के चयनित 24 जिलों में सामूहिक टीकाकरण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा कराया गया है जिसमें 93.1 परसेंट बच्चों को टीका दिया गया है । जापानी इंसेफलाइटिस के संपुष्ट मरीजों के गांव में टेक्नीकल मालाथिओन का फौगिंग कराया जा रहा है । विगत वर्षों में इस वर्ष एस.ओ.पी. के द्वारा जागरुकता अभियान या जो अन्य व्यवस्थाएं की गयी हैं वह मैं बताना चाहता हूँ । वर्ष 2018 में कुल 6656 संशोधित एस.ओ.पी. 2018 पुस्तिका राज्य के सभी जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराया गया जिसका वितरण स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाईन कार्यकर्ता एवं कर्मी द्वारा हुआ । लीची पैदावार जिलों के लिए 2018 में 21 लाख पैम्फलेट उपलब्ध करायी गयी । वर्ष 2019 में आशा दीदी द्वारा माईकिंग के साथ अभी तक लगभग 14 लाख पैम्फलेट्स बांटे गए हैं साथ ही लगभग 17 लाख ओ.आर.एस. के पैकेट का वितरण किया गया है । वर्ष 2019 में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से समाचारपत्रों, टेलीवीजन, रेडियो, एवं सोशल मीडिया यथा फेस बुंक ट्वीटर आदि पर ए.ई.एस. विषयक संदेशों का प्रसार किया गया है । ए.इ.एस. से संबंधित विविध सामग्रिया यथा एस.ओ.पी. सामान्य

मार्गदर्शिका, आशा एवं ए.एन.एम. के लिए मार्गदर्शिका, लीची पैदावार जिलों के लिए मार्गदर्शिक फ्लैट्स बैनर का नमूना इत्यादि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के वेब पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है इन सामग्रियो को जिला स्तर पर छपवाने संबंधी निर्देश वित्तीय मार्गदर्शिक में अंकित है । जिलों को प्लैट्स राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अलग से उपलब्ध कराया जाता रहा है । विगत वर्षों के अनुरुप इस वर्ष समय समय पर समाचारपत्रों में ए.ई.एस. के लक्षण बचाव एवं उपचार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है जीविका विकास मित्र, किसान सलाहकार एवं जन प्रतिनिधि द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है । चिकित्सकीय सलाह एवं आपातकाल स्थिति हेतु 104 नंबर का कौल सेंटर कार्यरत है । महोदय, विगत 9 वर्षों का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ । वर्ष 2011 में कुल 944 मरीज प्रतिवेदित हुए, जिसमें से 740 स्वस्थ होकर गए, 204 की मृत्यु हुई जिनका औसत मृत्यु दर 22 प्रतिशत रहा । 2012 में कुल 1247 मरीज प्रतिवेदित हुए, 823 स्वस्थ होकर घर गए, 424 मृत हुए कुल कैजुएल्टी का मृत्यु दर रहा वह 34 प्रतिशत रहा , 2013 में कुल 580 मरीज प्रतिवेदित हुए 358 स्वस्थ होकर घर गए, 222 मृत हुए और 38 प्रतिशत मृत्यु दर प्रतिवेदित हुआ । 2014 में 1341 मरीज प्रतिवेदित हुए 962 स्वस्थ होकर घर गए, 379 बच्चों की मृत्यु हुई और 28 प्रतिशत मृत्यु दर प्रतिवेदित हुआ उसके बाद से लगातार राज्य के अंदर जो प्रयास हुए उसके कारण इन आंकड़ों में कमी आयी ।

क्रमशः

टर्न-11/01.07.2019/बिपिन

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : क्रमशः उसके बाद से लगातार राज्य के अंदर जो प्रयास हुए, उसके कारण इन ऑकड़ों में कमी आई । 2015 में 298 मरीज प्रतिवेदित हुए, 208 स्वस्थ हुए, 90 मृत हुए और कैजुएल्टी का जो दर है, मृत्यु दर वह 30 प्रतिशत रहा । 2016 में कुल 324 मरीज प्रतिवेदित हुए, स्वस्थ 221 होकर घर गए, जो मृत्यु बच्चों की हुई उसकी संख्या 103 रही और 32 प्रतिशत मृत्यु दर रहा । 2017 में 189 मरीज प्रतिवेदित हुए, 135 स्वस्थ होकर घर गए, 54 बच्चों की मृत्यु हुई, 29 प्रतिशत मृत्यु दर रहा । 2018 में 124 मरीज प्रतिवेदित हुए, 91 बच्चे स्वस्थ होकर गए, 33 बच्चे

मृत हुए और मृत्यु दर 27 प्रतिशत् रहा । अभी 28 जून तक का जो आंकड़ा हमारे पास प्राप्त है उसके अनुसार 720 मरीज प्रतिवेदित हुए हैं, 566 स्वस्थ हुए हैं और 154 बच्चों की दु:खद मृत्यु हुई है और मृत्यु दर घट कर इस बार 21 प्रतिशत पर आ गया है । यह जो तालिका मैंने आपके सामने रखा, उससे स्पष्ट है कि सरकार के प्रयास से लगातार पिछले वर्षों में मृत्यु दर में इस बीमारी के कारण जो मृत्यु दर होता है उसमें कमी आई है ।

2014 के बाद ए.इ.एस. के इलाज हेतु जो बढ़ाई गई चिकिस्तकीय सुविधाएं हैं उसके बारे में महोदय आपको बताना चाहता हूं एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में पिकु में बेड की संख्या 14 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है । इसमें पिकु के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध है । ए.इ.एस./जे.इ. नियंत्रणार्थ वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य के सात जिलों यथा- पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन चार जिलों के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल के शिशु रोग विभाग में और वैशाली, पूर्वी चम्पारण इन दो जिलों के सदर अस्पताल में तथा नवादा जिला के अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में पिकु पेडियट्रिक इंटेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना कर संचालन प्रारंभ किया गया है । आयुष्मान भारत पी.एम.जे.ए.वाई. कार्यक्रम अंतर्गत एम.200078 एवं एम.00035 पैकेज के अंतर्गत ए.इ.एस. के मरीजों का इलाज किया जा रहा है । एम्स. पटना, डी.एम.सी.एच., दरभंगा एवं पी.एम.सी.एच., पटना से शिशु रोग विशेषज्ञों से एवं नर्सों की प्रतिनियुक्ति एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में की गई है । सेंट्रल टीम द्वारा 10 शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा एवं 5 पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति मुजफ्फरपुर में की गई है ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ एलर्ट ऐडवाइजरी भी जारी की गई है । 2013 एवं 2018 का एस.ओ.पी. जो है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, सर्वप्रथम 2013 में एस.ओ.पी. का निर्माण किया गया । इसके आधार पर मरीजों के इलाज में कुछ नए तथ्यों को समाहित करने की आवश्यकता चिकित्सों द्वारा महसूस की गई । इसी के आधार पर पुन: वर्ष 2018 में संशोधित एस.ओ.पी. का निर्माण किया गया । वर्ष 2018 में इटियोलौजी / कॉजेज औफ ए.इ.एस. में कुछ नई बीमारियों को समाहित किया गया जिसमें नीपा इंसेफलाईटिस, चॉदीपुरा वायरस, हीट पाइरेक्सिया, हाईपोग्लाइ

सेमिया, डाइसेलेक्ट्रोलाइटेमिया, लेप्टोस्पाइरोसिस इत्यादि को जोड़ा गया । इन बीमारियों में भी शुरूआती लक्षण ए.इ.एस. के पाए जाते हैं ।

मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु अन्य विभागों की सहभागिता एस.ओ.पी. में वर्णित है । चिकित्सा संस्थान में मरीजों के आते ही तुरंत क्या करना चाहिए, इसका एक चैप्टर शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त ट्रीटमेंट गाइडलाइन में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सुझाव पर आवश्यकतानुसार सुधार किया गया । मृत मरीजों का भर्बल ऑटोप्सी करने का प्रावधान किया गया है । इसमें जिला स्तर पर गठित कमिटी में अध्यक्ष सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य होते हैं ।

महोदय, इस वर्ष का तिथिवार, मरीजवार ऑकड़ा हमने तैयार किया है जो हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत आई.डी.एस.पी. है उसके द्वारा तिथिवार आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वह मैं अपने इस भाषण के साथ सदन के पटल पर उसको रखूंगा महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जो रिपोर्ट प्रतिवेदित हुआ है, अभी तक हमारे आई.डी.एस.पी. के अनुसार 29 जून तक का जो आंकड़ा है उसके अंदर हम 153 मरीज की मृत्यु हुई है और इस वर्ष का जो आंकड़ा है वह मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय । जनवरी में एक बच्चे की मृत्यु हुई, फरवरी में मृत्यु शून्य था इस बीमारी से, मार्च में एक बच्चे की मृत्यु हुई, अप्रैल में चार बच्चे की मृत्यु हुई, मई में आठ बच्चे की मृत्यु हुई और पांच जून तक 9 बच्चे अस्पताल में ऐडमिट हुए जो हमारे अस्पताल एस.के.एम.सी.एच. के अंदर आए थे । इसके उपरान्त 6 जून से मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोत्तरी होने लगी जिसके बाद भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर पर सिविल सर्जन एवं एस.के.एम.सी.एच. के अधीक्षक के स्तर पर युद्ध स्तर पर कदम उठाए गए । राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवरणी संलग्न है । मैं उसको आगे आपके ध्यान में लाऊंगा । उल्लेखनीय है कि मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही पिकु, पेडियट्रिक इंटेसिव यूनिट के बेड की संख्या क्रमशः बढ़ाई गई जो वर्त्तमान में 66 है ।

मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार ए.इ.एस. नियंत्रण हेतु कटिबद्ध है । आने वाले समय में एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में पिकु के बेड की संख्या वर्त्तमान में कार्यरत 66 से बढ़ाकर 100 की जाएगी । एस.के.एम.सी.एच. में अभी कुल बेड की संख्या 610 है । माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रथम चरण में इसे बढ़ाकर 1500 बेड किया जाएगा एवं द्वितीय चरण में अस्पताल के कुल बेड की संख्या 2500 की जाएगी । एस.के.एम.सी.एच. परिसर में वाइरोलॉजी लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । मरीजों के परिजन के लिए विश्रामालय का निर्माण किया जाएगा । साथ ही, एम्स, पटना में रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।

महोदय, उपर वर्णित प्रयासों से मुझे आशा है कि अगले वर्ष बेहतर आधारभूत चिकित्सकीय प्रबंधन, चिकित्सकीय प्रोटोकोल सहित तथा अनुसंधान के जरिए इस बीमारी पर कारगर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी पिछले दिनों, हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके लिए हम सिर्फ शोक प्रकट नहीं कर सकते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए ।)

यह बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विस्तार से अब तक इसके बारे में क्या जानकारी रही है, विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, उसके बाद अवेयरनेस लाने के लिए भी प्रयास किया गया है । इन सब बातों का इन्होंने जिक्र किया है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद जो इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है बच्चों की, तो इसके बाद तो इसके स्तर पर हमलोगों ने बैठक की । स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गए थे । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वहां आए थे । ये सब लोग गए और जिसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है । मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में हमलोगों ने अपने स्तर पर भी बैठक की और जो कुछ भी इसके बारे में, मुझे जो इसका पहले का एहसास और अनुभव था उसके आधार पर हमने चर्चा की और संबंधित विभागों के लोग जो बैठक में शामिल थे, मुख्य सचिव भी थे, हमने वहां पर कुछ सुझाव

दिया था । एक हम बता देना चाहते हैं कि 2014 की बात, तो यहां भी चर्चा हुई है और सबको मालूम है, उसके पहले से इस प्रकार की बीमारी और बीमारी से मौत का सिलसिला चल रहा था। इसके बारे में क्या कारण है, इसको लेकर जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं उनमें अलग-अलग ओपिनियन था । हमने अपने स्तर पर 2015 में एम्स, पटना में एक बैठक आयोजित की थी जिसमें सारे एक्सपर्ट्स भी थे और उसमें उनलोगों की बात सुन रहा था । अलग-अलग व्यूज लोगों के थे । कोई यह कह रहा था कि सरयू नदी में वह आ रहा है, गोरखपुर में भी यह घटना घटती थी । गोरखपुर में सबसे पहले होती थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में यह बात होती थी । तो उनका एक विचार था, दूसरे लोगों का कुछ और विचार था । अलग-अलग विचार था । तीन घंटे तक हम बैठक में शामिल हुए थे और अंत में हमने यही अनुरोध किया था कि वह अलग-अलग ओपिनियन, मुझको उस समय बताया गया

था कि

... क्रमश.....

टर्न :12/कृष्ण/01.07.2019/

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमशः) इसके बारे में रिपोर्ट यू0एस0 भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गयी लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट्स थे, डाक्टर्स थे जो इलाज करते हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या स्थिति है ? उस समय हमने कहा था कि भई, जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकीएक ज्वाइंट कमिटी बने और इस पर लोग नये सिरे से रिसर्च करें, अनुसंधान करें, स्टडी करें और उसके बाद किसी नतीजे पर आये, तब उसके हिसाब से लोगों के बीच में पूर्व में जो कार्रवाई करनी चाहिए, की जायेगी । लेकिन एक बात पहले से भी कहा था कि इसके बारे में अवेयरनेस कैम्पेन लाना चाहिए क्योंकि उस समय जो गर्मी होती है और वैसी स्थिति में यह बात आ जाती है, कोई आज से नहीं, बहुत पहले से प्रचारित था, किसी ने यह भी कहा था लेकिन वह बात लोगों ने कहा कि इससे इसका कोई संबंध नहीं, जो लीची की बात बहुत जगह कह दी जाती है । किसी ने कहा कि भई, बच्चा भूखा था, उसके घर के लोग उसी लीची का बगीचा है, उसमें काम करते हैं,

बच्चा को वहीं पर बैठा दिया, अगर नीचे लीची गिरा हुआ है, उसको खा लिया तो उसके कारण से भी, लेकिन यह किसी-किसी का विचार था । यह नहीं कि यही कारण है । तो अवेयरनेस के लिये सबसे बड़ी बात है कहीं भी लोग ले जाये तो बच्चे को भूखे पेट न ले जांय, इन सब चीजों के लिये अवेयरनेस कम्पेन भी चलाया गया । अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं घटी और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी । तो इसमें पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर लोगों को उसकी जानकारी मिली है कि सब लोग सब तरफ से सचेत हैं । अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आये और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है, सब लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक-एक चीज करेंगे । उसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी । मैं तो दो-तीन बात रखना चाहता हूं । जो कुछ भी हमने यहां चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रहती थी और उसके बारे में कि इसमें जो इसके विक्टिम हैं, वे गरीब परिवार के लोग होते हैं । आखिर ऐसी स्थिति क्यों है ? तो हमने यह उसी समय कहा था कि भई, इसके लिये हमलोगों को एक सोशियो इकॉनॉमिक सर्वे करना चाहिए और उसके अगले दिन हम फिर गये थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्त्ती थे और उनके साथ उनकी मां या उनके गार्जियन वहां थे, एक-एक लोगों से हमने बात की । एक बेड पर दो बच्चे थे चूंकि बेड्स की कमी थी और उसके पहले यह जानकारी मिली कि वहां पीकु, PICU का मात्र 14 ही बेड है । तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनको हमने कहा कि इससे काम नहीं चल सकता है, इसकी संख्या तो बढ़ा करके करना चाहिए । इनलोगों ने त्वरित कार्रवाई की और वहां जो जेल का वार्ड था, SKMCH में जो जेलर के लिये जगह थी, उस जगह को हटा करके वहीं पर इनलोगों ने और ज्यादा PICU की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया और अगले दिन इनसे जो बात पहले हुई थी और हमने एक दिन समीक्षा किया और उस समीक्षा बैठक में माननीय उप मुख्य मंत्री भी शामिल थे । अगले दिन जब हमलोग वहां पर गये और एक-एक लोगों से हमने जो बात की और सब का जो दृश्य देखा बच्चों का, बच्चियों का तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परीवार के बच्चे हैं और बच्चियों की संख्या ज्यादा है । हम सबसे पूछे कि आखिर हुआ क्या था और डाक्टर भी बता रहे थे कि कब बीमार हुये, कब आये और क्या हुआ, ये सारी बात वे

लोग कह रहे थे और सारी बात हमने देखा । तो वहां का दृश्य देखने के बाद जो मेरे मन में बात आयी और दूसरी बात है कि जब हम SKMCH गये, हम तो पहली बार गये थे, यह फैक्ट है, उसके पहले हमको जाने का अवसर नहीं मिला । वहां इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज एक अलग हो रहा था, उसके लिये अलग जगह था । लेकिन बाकी लोग अपने इलाज के लिये SKMCH जाते हैं, हमने देखा कि उनकी संख्या भी बहुत थी । हमने देखा SKMCH में, मुजफ्फरपुर इतनी बड़ी आबादी की जगह है और यह केन्द्र बिन्दु है तो एक बात मुझको यह देख करके लगा, फिर हमने जानकारी ली कि कितने बेड हैं, क्या है, सब कुछ और सबसे मिलने के बाद जब हमने बैठक की तो हमने फिर कहा कि भई, देखिये इसका सर्वेक्षण हो और सबसे पहले जो इस के विक्टिम हैं, उनके परिवार को देख लीजिये और इसके अलावे और विक्टिम को भी देख लीजिये और ये जिस किसी भी गांव के हैं, हमने वहां जानकारी चाही कि एक गांव का एक से अधिक आदमी हो, ऐसा कौन-सा इलाका है तो यह पता चलेगा कि किस जगह पर और क्यों ऐसी बात हो जाती है । फिर सारे लोगों के साथ जो मीटिंग हुई, केन्द्र से भी टीम आ गयी थी और वे लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे तो हमने उनको कहा कि मेडिकल प्वाइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को पूरे अच्छी तरह से देखिये कि आखिर किस परिस्थिति में यह बात आती है और हमने अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स को कहा और चीफ सेक्रेटरी भी थे, जो बात मैंने पहले कही है, उसके हिसाब से पूरे तौर पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए । आखिर यह पता चलेगा किस तरह का यह गांव है, उस गांव की क्या स्थिति है और उस गांव के जो गरीब लोग हैं, जो इसके शिकार हो रहे हैं, उस परिवार के और ऐसे कितने परिवार हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं । एक तो वे लोग जो प्रारंभिक विक्टिम थे, बीमार पड़े थे और पूर्व में भी जो बीमार पड़े, उनकी की पूरी सर्वे कर रहे हैं और हमने कहा कि अपनी तरफ से इसमें जीविका समूह को शामिल कीजिये, आंगनबाड़ी सेविकाओं को शामिल कीजिये, इन सबलोगों को लेकर हर प्रकार से एक-एक करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कीजिये कि कहां क्या है ? तो जो हमने वहां दृश्य देखा, बीमार लोगों का, बच्चों का, बच्चियों का, हमको बच्चियों की संख्या ज्यादा लगी नंबर-1, और यह साफ लगा कि सब गरीब परिवार के लोग हैं । तो वैसी स्थिति में जब हमलोग हर गांव के विकास के लिये स्कीम्स बनाये हुये हैं तो क्यों नहीं ये उस स्कीम्स का लाभ उठा पा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति हुई ? तो मैं यही जानकारी देना

चाहता हूं कि इसका जो सोशियो इकोनॉमी सर्वे है डिटेल्ड, उन इलाकों में कौन-कौन परिवार वंचित हैं, अभी एक बात आ रही थी, एस्वेस्टस की बात कर रहे थे, हम एक जानकारी दे देना चाहते हैं, वह मैं बता दे देना चाहता हूं, यह एस्बेस्टस है बहुत फालतू चीज । हमारा व्यक्तिगत रूप से विचार है । आप जान लीजिये लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है । हमने तो कह दिया है कि सरकार के काम में एस्बेस्टस मत लगाईये, अपने फर्स्ट टेन्योर में हमने ये बातें कही है । एक जगह कोई एस्बेस्टस के लिये इन्डस्ट्री लगा रहा था और जो इन्डस्ट्रीयल प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से जो सहायता मिलती थी, तो उसका प्रस्ताव उसको सहायता देने के लिये मेरे पास आया हुआ था । एस्बेस्टस की फैक्ट्री लग रही थी, जहांतक मुझे याद है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, समाप्त होने तक इसका समय बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मुख्यमंत्री का रेस्पांस समाप्त होने तक सदन की कालावधि बढ़ाई जाती है ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : तो एस्बेस्टस की जो फैक्ट्री लगा रहा था उसको लेकर वहां के लोगों ने विरोध प्रकट किया था और जो विरोध प्रकट करनेवाले थे, वे मुझसे मिलने आये थे । जब उनसे मिले और मुझे जानकारी मिली तो हमने कहा कि बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । उसके बाद हमने विभाग को निर्देश दिया और औपचारिक रूप से निर्णय लिया कि जो भी हमारा इन्डस्ट्रीयल प्रमोशन पॉलिसी है, उसके अन्तर्गत हम एस्बेस्टस का कारखाना यहां कोई लगायेगा या उसका काम करेगा, उसको किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे । नंबर-2, हमलोगों ने कहा कि सरकारी चीजों में एस्बेस्टस का यूज मत करिये, यह बहुत फालतू चीज है । लेकिन लोग तो यूज करता है । देश में एस्बेस्टस पर कोई प्रतिबंध नहीं है । अगर सच पूछिये, पर्यावरण के बारे में मेरी जो सोच और समझ है, उसमें तो हम नहीं चाहेंगे कि एस्बेस्टस का उपयोग हो । लेकिन हम अपनी तरफ से उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे और सरकारी चीजों में इसका प्रयोग करेंगे । बात बिल्कुल सही कहा है जो एस्बेस्टस के बारे में बोल रहे थे । हम तो उससे शत-प्रतिशत सहमत हैं । वह एक अलग विषय है। लेकिन इस बार जो कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आयेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वही रिपोर्ट आयेगा और उसके आधार पर जो हमलोगों ने जो स्कीम बनायी है, आज वे क्यों झोपड़ी में रह रहे हैं, भई, जब यह बात तय हो गयी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अब वह हो गया, अब 1 लाख 20 हजार रूपया एक घर को बनाने के लिये मिल रहा है । तो उसमें जो लोग भी वंचित रह गये थे, उसके बारे में भी हमलोगों ने केन्द्र सरकार से कहा और दूसरी बात, चूंकि ए0सी0सी0एस0 से संबंधित वह था, लेकिन उसके अलावे बहुत गरीब लोग हैं, जो छूट गये हैं, तब हमलोगों ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने जो कुछ भी तैयार किया था लिस्ट, अगर उसके हिसाब से वहां से मंजूरी मिल जाती है तो अच्छी बात है नहीं तो उसके अलावे प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जो परिवार वंचित हैं, उसके लिये हमलोगों ने दो चीज है, एक तो जो उससे वंचित हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, दूसरा, जो पुराने 1996 से जो इन्दिरा आवास बन रहे थे, एक साथ आवास बन रहे थे, अब वह जर्जर स्थिति में है, उसकी जगह पर उसका रीप्लेसमेंट करने के लिये, दोनों काम के लिये हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरूआत करायी है और उसके लिये भी 1 लाख30 हजार रूपया देंगे ।

क्रमशः

टर्न-13/अंजनी/दि0 01.07.2019

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ....क्रमशः.. अब ग्रामीण आवास योजना में जिन लोगों का नाम है, उसमें से बहुत लोग हैं, जिनके पास अपनी जगह नहीं है तो उन लोगों को जगह खरीदने के लिए 60 हजार रूपये की सहायता देने का भी हमलोगों ने एक कार्यक्रम बना दिया है । तो अब इन दोनों काम से और इस पूरे सर्वे से उस पूरे इलाके में, एक तो पूरे बिहार के लिए है, हमलोग यह देख लेंगे कि जो वंचित रह गया है तो सबसे पहले लोगों को ग्रामीण आवास के लिए यह सुविधा हमलोग उपलब्ध करायेंगे, नम्बर-1, यह हमलोगों ने सोच लिया है । दूसरी चीज है कि एक कार्यक्रम हमलोगों ने और शुरू किया सतत् जीविकोपार्जन योजना । यह दो काम के लिए है । एक तो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल हाशिये पर हैं, सरकार की योजनाओं की उनको जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं लेते हैं, उनको यहां तक कि राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे परिवारों को चिंहित कर लिया जाय और उन परिवारों को चिंहित करके उनको उन सारी योजनाओं का लाभ दिया जाय । यह भी हमलोगों ने स्कीम बना दिया है । स्कीम बना हुआ है और अब यह सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा तो एक तो सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ और सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ यह होगा कि उसको कोई-न-कोई काम करने के लिए हमलोग 60 हजार रूपया से लेकर एक लाख रूपया तक की मदद करेंगे ताकि वह कोई भी काम करे, कोई दुकान खोल ले,

कोई काम कर ले, गाय का पालन करे, कुछ भी करे तो उसके लिए उसको प्रेरित करके और इसके लिए हमलोगों ने जीविका समूह को लगाया ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए किसी को जिम्मेवारी दी?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप मेरी बात पहले सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष : जो बात कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ये सारी बात जरा जान लीजिए । हम आप लोगों को और बता रहे हैं । यह जो घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, बहुत ही हमलोगों के लिए चिन्ताजनक चीज है और आगे हम बता देना चाहते हैं कि इस बार जो मुझको लग रहा है, चाहे मौसम विज्ञान कुछ भी कहे, मुझको लग रहा है, शंका है कि भयंकर सूखा पड़नेवाला है और इसके लिए हमको जितना करना है, हम सब तैयारी कर रहे हैं और हमने आग्रह किया है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, आप में से बहुत से लोग थे कि एक तो अलग से सारे एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 के साथ सभी संबद्ध विभाग के अधिकारियों को बैठाकर दिन भर उनके क्षेत्र की स्थिति को जानकर, उनके विचार को जानकर आगे भी कुछ नहीं हो, अभी एक घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जो स्थिति मौसम की हो रही है उसमें क्या कल होगा, nobody knows, कोई नहीं जान रहा है, बहुत भयंकर स्थिति है तो इसलिए कृपा करके जो बात हम कर रहे हैं, उसको सुन लीजिए और उसके बाद आपको जो प्रतिक्रया देनी हो, आप प्रतिक्रिया व्यक्त करियेगा । इस तरह के स्कीम के माध्यम से हमलोग चाहते हैं कि सबको जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, वह मिले । आखिरकार वह गरीब आदमी को घर क्यों नहीं, घर क्यों नहीं है तो इसका मतलब है, न वह इंदिरा आवास से लाभान्वित था और न आज की नयी योजना से लाभान्वित था । तो अगर सर्वे करके जबतक पहचान नहीं हो जायेगी और सिर्फ जो प्रभावित हुए हैं, वही परिवार नहीं, बाकी अन्य परिवार हैं । आज एक परिवार प्रभावित हुआ है तो कल दूसरा परिवार प्रभावित हो जायेगा, इसलिए सबके लिए करना पड़ेगा पूरे तौर पर । जो स्कीम हमलोगों ने रखी है और उसके अलावे भी हमलोगों को ऐसे परिवारों को बिल्कुल गरीबी से निकालकर आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि एक भी परिवार इस तरह से हाशिये पर नहीं रहे । इतनी बात समझ में आयी है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं और जीविका समूह के माध्यम से भी उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं और जान लीजिए

कि जीविका समूह बनने से आज साढ़े आठ लाख स्वयं सहायता समूह बना है । करीब-करीब एक करोड़ परिवार की महिलायें जुड़ गयी है और यह जीविका समूह की शुरूआत हमने की वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर, 6 जिले के 44 ब्लॉक से और अब पूरे बिहार में लागू है । दस लाख स्वयं सहायता समूह का मेरा लक्ष्य था और आज अभी वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हम तो चाहेंगे कि जितने परिवार हैं, अगर वे जीविका समूह से जुड़ी नहीं हैं तो उसको जीविका समूह से जोड़ेंगे । महिलाओं में जागृति जीविका समूह के माध्यम से ही हमलोगों ने लाने की कोशिश की है और जीविका समूह से जुड़ जायेंगी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ जायेंगी तो उनमें बहुत चीजों की जानकारी और समझ होगी, उनमें जागृति आयेगी और इस जागृति की बदौलत ही आप उनको बता सकते हैं कि बच्चों को भूखे मत रहने दो, बच्चों को गंदी जगह पर मत रखने दो, बच्चे को साफ सुथरा रखो तो ये कुछ भी बात करेंगे तो ये सिर्फ सरकार की एजेंसी के माध्यम से हमलोग करना चाहेंगे, एक हद तक आप कर सकते हैं लेकिन जबतक आप पूरे तौर पर सामाजिक तौर पर इसके साथ जुड़ नहीं जायेंगे तो जीविका समूह से इसलिए जुड़ रहे हैं और उनको जीविका समूह से जोड़ेंगे, सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ और कोई भी बात हो, हम वहां गये हैं और इसके बाद जान लीजिए कि जापानी इनसेफलाइटिस होता है, गया और कई जिलों में होता है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गया की होती है । इस बार लोग लू से मर गये, बड़ी संख्या में लोग मर गये तो हम वहां भी गये और वहां भी जाकर सब लोगों को देखा कि सारे लोग बुजुर्ग थे, कई लोगों को देखा कि ये जो शिकार हैं, आज उनका डेथ नहीं हुआ लेकिन उनका इलाज चल रहा है तो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हैं । ज्यादा उम्र के लोग, सबसे हम पूछ रहे थे, उनके परिवार के लोगों से भी पूछ रहे थे तो सबसे बड़ी चीज है एवेयरनेस, वहां पर हमने जो बात की सब लोगों से मिलने के बाद, जो हमने चर्चा की लोगों के साथ बैठकर और सारे अधिकारी लोग मौजूद थे, उन सब लोगों से बातचीत कर हमने पूछा कि जापानी इनसेफलाइटिस के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि हमलोग इसके टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं और उन लोगों ने बताया कि जो जिले हैं, उसके अलावे 11 और जिलों में वैक्सिनेशन के लिए उनलोगों ने केन्द्र सरकार के पास भेजा है । चूंकि वैक्सिनेशन के लिए जो मेडिसीन चाहिए, वह केन्द्र सरकार से आती है तो वहां भेज दिया है और वे लोग इसको भेजेंगे, ये पूरे बिहार के और जिलों में हमने तो देखा कि मात्र चार जिला बचेगा तो हमने तो वहीं पर सबको कहा कि उन चार जिलों का भी ठीक से देख लीजिए, वरन् पता

चला कि हम बाकी सब जगह पर करा रहे हैं और बाकी जगह पर हो गया, तो क्यों नहीं सब जगह करेंगे । उससे जापानी इनसेफलाइटिस से बचेगा और ये जो है एक्युट इनसेफलाइटिस सिंड्रोम, कई तरह के लक्षण हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, क्या हैं लेकिन सिन्ड्रोम, अभीतक उसको सिन्ड्रोम कह रहा है । अभी तक कोई निश्चित बीमारी तक नहीं पहुंचे हैं लोग । इसपर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं और जिस परस्थिति में हुआ तो एक-एक चीज का, यह बहुत ही गंभीर मसला है और यह हम सब लोगों के लिए दुखद है । अगर ऐसे लोगों को हम पहले से ही बचा नहीं पायेंगे तब आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी काम कर लीजिए, अगर इस तरह की कोई घटना घट जायेगी तो मन इतना दुखित होता है, इतनी चिंता में डूब जाता है कि बहुत सारे काम भी प्रभावित होने लगते हैं कि मन में वही बात रहेगी और आज क्या है, सबके मन में वही बात है तो अन्य काम भी होना चाहिए । लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में उतनी ही चिंता है और इसके लिए सर्वे कराकर एक-एक काम और वही नहीं, यह हम मुजफ्फरपुर जिले की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सभी इलाकों में और उसी तरह से अन्य पूरे बिहार के एक-एक गांव का देखकर के और हमलोग एक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे और बजाप्ता अभी जो बजट का प्रावधान है, उससे काम नहीं चलेगा तो हम सेंकेंड सप्लमेंटरी में लायेंगे और इसके लिए हमलोगों को और इतना काम करना है । यह सबसे ज्यादे प्राथमिकता है । हम जबतक लोगों की स्थिति में सुधार नहीं लायेंगे और सबसे बड़ी चीज है कि रहने का जगह न हो, उसको कुछ काम करने के लिए उसको कुछ हम सहायता नहीं कर सकेंगे तो कोई उम्मीद करना और उसको किसी तरह की बीमारी न हो, इसके लिए जो भी पहले काम करना हो, उसके बचाव के लिए करना ही पड़ेगा । तो यह बहुत दुखद बात हुई है । इस पूरे चीज को लेकर हमलोग करते रहे हैं । एस्बेस्टस का हमको डिपार्टमेंट ने भेजा है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं । एस्बेस्टस की फैक्ट्री जो लगाना चाहता है जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे वही लिखा हुआ है । तो जो भी करेंगे, वह अच्छी तरह से सब परिवार के बच्चों को जबतक हम आंगनवाड़ी केन्द्र से नहीं जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा तो आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या बढ़ानी होगी । आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ायी जायेगी । कन्या उत्थान योजना की, अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए जो सहायता दी जाती है, यह सब काम, जीविका समूह से जोड़ना हमने बात किया । टॉयलेट तो सब जगह बनना है और इस बार बापू जयंती के

अवसर तक पूरे बिहार में हर घर में शौचालय का निर्माण करने का हमलोगों का लक्ष्य है ।

(क्रमशः)

टर्न-14/राजेश/1.7.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः.. यह करना है और इसके साथ जो हमलोग कर रहे हैं हर घर नल का जल, स्वच्छ पानी पीने का हो जाय और हम हर जगह कहते हैं, खुले में शौच से मुक्ति हो जाय ....(व्यवधान)

अरे भईया थोड़ा समझ लो, कान में सुनियेगा न, तो कभी-कभी थोड़ा बहुत आप भी बोलियेगा तो नीचे उसका असर पड़ेगा, वरना शौचालय बन जाता है और शौचालय में पाखाना करने के बजाय लोग खुले में चला जाता है, यह पुरानी आदत है,यह समझाना पड़ेगा कि खुले में शौच से मुक्ति और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाय, तो आज जितनी बीमारियाँ होती हैं, तो 90 प्रतिशत बीमारी नहीं होगी और हम प्रारंभ से ही लोगों के बीच कहते हैं, तो इसलिए हर घर नल का जल ...

(व्यवधान)

दो मिनट रुक जाइये, पहले इस बात को सुन तो लीजिये, आपके प्रचार में गये थे, तो भाषण नहीं दिये थे, अभी रुकिये, तो खुले में शौच से मुक्ति और हर घर नल का जल और स्वच्छता के प्रति अभियान, ये सारी बातें इसके साथ जोड़ करके और जो भी स्कीम्स हैं और एक-एक का, अभी का देख लीजिये, अभी का रिपोर्ट कितना है, हमने तो लक्ष्य रखा संपूर्ण टीकाकरण, बिहार में कितना था भाई, पहले तो 20 से 25 परसेंट के बीच टीकाकरण होता था, अभी 84 परसेंट से भी ज्यादा हो गया है लेकिन हमारा लक्ष्य है टॉप फाईव, देश में उपर के जो पाँच राज्य हों, जिसमें संपूर्ण टीकाकरण का और टीकाकरण नहीं कीजियेगा तो कहीं न कहीं कई प्रकार की बिमारियाँ गरीब बच्चों को हो जायेगी, जो टीकाकरण नहीं करायेगा, तो संपूर्ण टीकाकरण, इसको हम सब करेंगे और आप जान लीजिये, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो देखा हमने, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे इस बात की तकलीफ हुई है कि हमने पहले क्यों नहीं देखा था और हम वहाँ जाने के बाद ही तय किया, 600 कुछ का बेड है वहाँ, तो हमने कहा कि इसको भी जैसे नालंदा मेडिकल कॉलेज हास्टिपटल को 2500 बेड का कर रहे हैं या आई0जी0आई0एम0एस0 का 2500 बेड का कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर

मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 2500 बेड का करेंगे और अभी इमिडिएट काम शुरु हो जाये और 1500 बेड का तो पहले हम इसको बना दें, फिर आगे का, तो हमने वहॉ देख करके, कई सुझाव देकर आये हैं और क्या-क्या करना है, एक-एक हॉस्पिटल आई0सी0यू0 का पी0आई0सी0यू0 की तो बात हो चुकी है, वह 100 का तो बन ही जायेगा और इसके अलावे जब हम गया गये थे, गया में भी हमने देखा, गया का भी हॉस्पिटल हम इससे पहले नहीं जा सके थे, हमने देखा है गया का हॉस्पिटल भी 1500 बेड का बनेगा और इसके लिए भी हमलोगों ने निर्णय ले लिया है और इसके लिए डी0पी0आर0 तैयार करके जो भी धनराशि की जरुरत होगी, हमलोग अपनी तरफ से करेंगे, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, यह घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है लेकिन हम सब लोगों को, लोगों के बीच में कन्सेसनेस लाने के लिए, लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उत्थान करना और इन सब चीजों के अलावे अवेयरनेस जागृति लाना, यह एक-एक काम करना पड़ेगा, तभी हम भविष्य में ऐसी चीजों से मुक्ति पा सकेंगे, हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि कुदरत का कौन सा खेल का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जरा बताइये आज कल, पानी कम पड़ रहा है और वज्रपात हो रहा है, खूब वज्रपात हो रहा है, कभी-कभी गौर से देख लीजिये, एक डाक्टर तो वहॉ पर थे, वे तो विचित्र बात, उनसे हमने पूछा कि क्यों इसी इलाके में इस तरह की बीमारी होती है, तो वह तरह-तरह की बात कर रहा था, तो हमने कहा कि भाई थोड़ा इसको देख लीजिये, कह रहा था कि 1934 में जो अर्थ क्वेक हुआ था, उसके चलते यहॉ का इलाका इफेक्टेड हुआ, उसके कारण यह हो रहा है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि यही बात है । लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम तुरत हम ....

(व्यवधान)

कनक्लूड हम कर दें, उसके बाद आप बोलिये न, हम फिर बोलेंगे, आप कहियेगा तो फिर बोलेंगे, खाली सुन तो लीजिये, देखिये यह केवल सरकार की चीज नहीं है, यह अवेयरनेस की चीज है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति न आये, इसके लिए हम प्रयास करेंगे लेकिन कोई भी अगर दावा करेगा कुदरत के बारे में, जिस तरह से पर्यावरण में आज बिगाड़ आ रहा है, अब साहब हमने तो नल का जल पहुंचा दिया, अवेयरनेस लाना है, हम नल का जल पहुंचा रहे हैं पीने के लिए स्वच्छ पानी न, अब उसी पानी से भैंस धो रहा है, उसी पानी से बगल में उसका कुछ है, तो वह पटवन कर रहा है, यह करोगे भाई तो ग्राउन्ड वाटर लेवेल कहॉ जायेगा और एक बात जान लीजिये, अब यह पूरी दुनिया में क्राईसेस होने वाला है, बिहार में भी क्राईसेस आ

रहा है, अब उन इलाकों का नीचे का जलस्तर गिरा है, भूजल स्तर का, अब आप सोच सकते हैं दरभंगा में, कोई सोच भी नहीं सकता था, तो ऐसी स्थिति है कुदरत का, हम तो एक बार आग्रह करेंगे इस विषय पर जा कहिये लेकिन एक बार बैठिये सारे लोग, हाउस के बाहर सबको बैठायेंगे पूरे दिन, अपना-अपना अनुभव बताइये और जो स्थिति पर्यावरण की बिगड़ती चली जा रही है, तो लोगों को इसके लिए अवेयर भी करना पड़ेगा, अब बिजली पहुंचा रहे हैं, तो बिजली के लिए जो चीजें जरुरी हैं, उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अब तत्काल उसका और कुछ उपयोग कीजियेगा, तो धीरे-धीरे पर्यावरण पर तो इसका असर आयेगा, वायु प्रदूषण का क्या हाल है ? जिसके पास पैसा आ जाता है, तो वह बड़ी-बड़ी गाड़ी खूब खरीदने लगता है तो वायु प्रदूषण । तो कई तरह की समस्याएँ हैं, इसके लिए हमलोगों को अवेयरनेस लाना पड़ेगा, अगर अवेयरनेस नहीं लायेंगे, तो अलग-अलग समय में, अलग-अलग इलाकों मे, अलग-अलग ऐसी घटनाएँ घटेंगी, तो आप हम सब लोग इसके लिए चिंता में पड़ेंगे, तो हम सब लोगों को संयुक्त रुप से चिंतित होकर अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और क्या-क्या करना चाहिए, आज जो जहॉ की घटना घटी है, उसको देखते हुए उन इलाकों में और बचे खुचे बिहार के हरेक गॉव में, इन सब योजनाओं का लाभ पहुंचा देने का हमारा संकल्प है, निश्चय है और आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे और इसके मामले में जो कुछ भी हुआ है, हमलोगों ने ऐसे परिवार के परिजनों को जो लाभ देने की बात सोच सकते हैं, उन सब दिशा में हमलोगों ने निर्णय लिया है और आज तो चूंकि मेडिकल प्वायंट ऑफ व्यू से एक-एक डिटेल इन्होंने रखा है, आपलोग स्वास्थ्य मंत्री की बात को नहीं सुने लेकिन यह तो डौकुमेंट है, रेकर्ड का पार्ट होगा, हम हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि यहॉ पर भले नही सुने लेकिन कल जो आपका जायेगा, उसको जरुर पढ़ लीजियेगा, अगर उसको पढ़ लीजियेगा, तो आपको खुद लगेगा कि क्या इसमें और कुछ करना चाहिए, उसके बारे में भी आपलोग सुझाव दे सकते हैं, तो हमको इतना ही है और हम पूरे तौर पर अध्यक्ष महोदय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विषय पर जिसको ले करके हर आदमी चिंतित है, बाकी कार्य को स्थगित करके आपने इसपर परिचर्चा करायी, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कनक्लुड कर लेते हैं तो आपको एक सेकेंड जो पूछना हो, पूछेंगे ।

अध्यक्ष: आप एक ही सेकेंड मांगे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: जी एक ही सेकेंड । महोदय, मुझको ताज्जुब हुआ कि 15 साल के शासनकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहली बार श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गये, इनका भाषण तो हम सुन रहे थे.......

अध्यक्ष: आप एक सेकेंड में बोलिये न ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: एक सेकेंड । माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को हम सुन रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी रहे हैं और नालंदा के ही रहे हैं, उर्दू के बड़े शायर कलीम आजी साहब, तो कलीम आजी साहब का दो लाईन इनके भाषण पर हम पढ़ देते हैं महोदय:-

''कि न खंजर पर कोई रेस, न दामन पर कोई दाग,
तू कत्ल करोहो कि करामात करोहो ।''

बस यही मुझको कहना था ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: आपको मालूम नहीं है, सदानंद बाबू को अभी तकलीफ हो जायेगी, यह उनका, उस समय की जो थीं नेत्री, यह उनपर था ।

अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, अब कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विमर्श समाप्त हुआ ।

टर्न-15/सत्येन्द्र/01-7-19

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज सभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी । सभा की समाप्ति 4 बजे अप0 में निर्धारित है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सुनते जाईए न । आप सदस्य है, कार्यमंत्रणा समिति के तमाम सदस्यों से अनुरोध है कि आज के सदन की बैठक समाप्त होने पर मेरे कार्यालय कक्ष में आईए, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है । अब 2 बजे दिन तक के लिए सभा की बैठक स्थगित की जाती है।

टर्न-16/मधुप/01.07.19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक 01 और 02 जुलाई, 2019 की तिथि निर्धारित है । वाद-विवाद और सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	- 80 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 70 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 54 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 26 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 3 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 1 मिनट
निर्दलीय	- 4 मिनट
कुल	-240 मिनट

माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव ।

श्रीमती एज्या यादव : महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट का मैं विरोध करती हूँ । यह बजट गरीब को मारो-मिटाओ वाला बजट है । इसमें दूरदर्शिता नाम की चीज नहीं है और उसमें गरीबों को फायदा हो, उस तरह से इस बजट को नहीं बनाया गया है । मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं अपनी शुरूआत गृह विभाग से करती हूँ ।

बीते वर्षों में आगलगी की काफी घटनाएँ हुईं । खेत-खलिहान में गेहूँ जल गये, घर जल गये, मवेशी जल गये । सरकार के द्वारा कहा गया था कि फायर ब्रिगेड अग्निशामन वाहन को हर प्रखंड में उपलब्ध कराया जायेगा ।

लगता है कि सरकार अपने वादे को भूल गई है और अभी तक किसी भी प्रखंड में नया फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं कराया गया है । जहाँ फायर ब्रिगेड है जर्जर स्थिति में है, जहाँ जर्जर स्थिति में भी फायर ब्रिगेड है, वहाँ पर ड्राइवर नहीं है, कहीं परमानेंट ड्राइवर का प्रावधान नहीं किया गया है । शायद यह पुलिस डिपार्टमेंट या वहाँ के जो एस0डी0एम0 हैं उनके अंडर में होता है और होमगार्ड कंट्रैक्चुअल बेसिस पर होमगार्ड इसके ड्राइवर बनते हैं । परमानेंट बेसिस पर ड्राइवर की नियुक्ति की जाय ताकि जब आग लगने की स्थिति आये तो इमीडियेटली फायर ब्रिगेड को बुलाया जाय और एक फंक्शनल रूप में फायर ब्रिगेड काम कर सके ।

दूसरी बात, जब भूकम्प आया तो स्कूल में बच्चों को सिखाया गया कि कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए । आगलगी बिहार का एक कॉमन मैटर है, क्या हमारे बच्चों को जरूरी नहीं है कि सिखाया जाय कि आग जैसी स्थिति में कैसे सामान, माल-जाल, अपनी जान को बचाया जाय ? मैं उम्मीद करती हूँ कि एकेडमिक कैलेन्डर में सरकार की तरफ से एक समय तय किया जाय जिसमें अगर आगलगी हो, अर्थ-क्वेक हो, उससे बचने का तरीका बच्चों को, टीचर्स को, नन-टीचर्स को, स्टाफ को बताया जाय ताकि ऐसी स्थिति में वे अपनी सुरक्षा कर सकें । फायर सिक्योरिटी मेजर्स हर बिल्डिंग में, हर सरकारी स्कूल में होना अनिवार्य है, सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलता है, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हो जाते हैं, एक तो उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे बचा जा सके । इसलिए फायर सिक्योरिटी मेजर्स स्कूल में, सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक सेवा केन्द्र में जरूर होना चाहिए ।

मैं दूसरी बात बोलूँगी, यह भी गृह विभाग का विषय है, बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया है । हमलोग बड़े आराम से पुलिस को दोषी ठहरा देते हैं लेकिन क्या हम कभी यह पता करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस की परेशानी क्या है ? They are suffering from acute man-power crisis. मैन-पावर की बहुत बड़ी क्राइसिस है और जो पदाधिकारी, दारोगा, थाना प्रभारी फिल्ड ड्यूटी में रहते हैं, they are over-worked, over-pressurised और अगर कभी मंत्री का दौरा हो गया तो सब चीज छोड़कर मंत्री के एस्कॉर्ट में इन्हें लगा दिया जाता है । अगर मैन-पावर की एक्यूट क्राइसिस है, क्राइम बढ़ा हुआ है तो मैन-पावर को बढ़ाया जाय, प्रोपर ट्रेनिंग दी जाय ताकि ये लोग इफेक्टिवली काम कर सकें । दूसरी बात, अगर क्राइम रेकॉर्ड देखा जाय तो बिहार पूरे स्टेट में काफी नीचे है । क्राइम बढ़ गया है, क्रिमिनल्स

बढ़ गये हैं । इसकी एक वजह है कि अभी तक हमारे पुलिस विभाग का मोडर्नाइजेशन नहीं हुआ है । CCTNS System जिसे Crime & Criminal Tracking Network & Systems कहते हैं, अभी तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लगाया गया है । अगर इसे लगा दिया जाय, ट्रेनिंग दे दी जाय तो क्राइम का प्रीवेंशन, डिटेक्शन और ट्रायल तेजी गति में हो सकेगा और क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा ।

तीसरी बात, मैं जेल पर चर्चा करना चाहूँगी । आज जेल की स्थिति क्या है ? It is over-crowded, over-populated, unhygienic और जो क्रिमिनल्स अन्दर जाते हैं अनहेल्दी सिचुएशन में रहते हैं । मैं यह बता दूँ कि जो क्रिमिनल्स होते हैं माँ की कोख से क्रिमिनल पैदा नहीं होते हैं, परिस्थितिवश वे क्रिमिनल बनते हैं और जब जेल की ऐसी स्थिति में वे जाते हैं तो उनका ऐग्रेशन और बढ़ जाता है । हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे जो मिसफिट एंटी सोशल एलीमेंट जब जेल जायं तो उन्हें सुधारने की कोशिश की जाय । कितने जेल में विद्यालय हैं जहाँ इन्हें पढ़ाया जाय ? कुछ हस्तकला सिखाया जाय, बॉस जो हमारे बिहार में इतना होता है, उससे बनाई जाने वाली चीजें सिखायी जायं । जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एग्रेसिवली जेल में सिखाया जाय । ये लोग मेंटली बहुत विचलित होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेज, योगा कराया जाय ताकि जब ये जेल से बाहर निकलें तो ये कम से कम अपने परिवार के पालन-पोषण के बारे में सोचें, एक पोजिटीव तरीके से सोचें और जो मिसफिट होकर जेल में गये थे, कम से कम थोड़ा फिट होकर सोसायटी में फिट करने की कोशिश ये लोग करें । तो जो जेल में हैं, इन्हें भी संवेदनशीला से देखा जाय और इन्हें सुधारने के लिए ऐग्रेसिव स्टेप्स सरकार की तरफ लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया जाता है । इनलोगों में सरप्लस इनर्जी होता है, मैन्युअल वर्क करवाया जाय, खुले जिले का प्रावधान बढ़ा दिया जाय, बक्सर में एक खुला जेल है जो कि सफिसियेंट नहीं है । हर प्रमंडल में अगर खुला जेल बना दिया जाय, मैन्युअल वर्क में इनको इन्गेज कर दिया जाय तो सरप्लस इनर्जी इनका निकलेगा और जो बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण जेल के अन्दर हो जाता है, जो दबा दिया जाता है, जो बाहर निकलकर नहीं आता है, यह समाप्त तो नहीं लेकिन कम जरूर हो जायेगा ।

तीसरा, आजकल अपार्टमेंट में हमलोग प्राइवेट सेक्योरिटीज को रखते हैं । इन प्राइवेट सेक्योरिटीज को लाइसेंस मिला है ? क्या जॉच करके इन्हें लाइसेंस दिया जाता है ? जब चोरी हो जाती है, डकैती हो जाता है, बिल्डिंग के

अन्दर क्राइम, मर्डर, रेप हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि गेट पर जो सेक्योरिटी गार्ड थे इन्हें तो लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ है । जबतक जॉच प्रोपरली नहीं हो, एजेंसी की जॉच जबतक न हो जाय तबतक इन्हें लाइसेंस नहीं दी जानी चाहिए । ये कुछ मुद्दे हैं गृह विभाग के जिसपर विथ इमीडियेट इफेक्ट सुधार करने की जरूरत है ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - महागठबंधन सरकार के द्वारा बड़े जोश के साथ नल-जल योजना शुरू की गई थी । उम्मीद की गई थी कि हर घर में नल का पानी पहुँचे, स्वच्छ पानी बच्चे पी सकें, घर के लोग पी सकें । जो समय बरबाद हो जाता है चापाकल और कुआॅ से जाकर पानी लाने में, उस समय की बचत होगी । लेकिन अब यह सिर्फ लूट-खसोट का मामला हो गया है । This programme, this scheme is one big fiasco बोलने में मुझे शर्म नहीं आयेगी लेकिन मैं चाहूँगी कि सरकार की आँख खुले, यह लूट-खसोट और एक फेल प्रोजेक्ट रहा है । क्या कभी जॉच हुई है कि पाईप की गहराई कहाॅ तक जाती है, पानी आना क्यों बंद हो गया ? अगर पानी आ रहा है तो टिप-टिप पानी इतना धीरे आता है कि उससे काम नहीं किया जाता है । यह जॉच का विषय है कि पाईप की गहराई कितनी है, टंकी सूख क्यों रहा है और पानी आखिर पहुँच क्यों नहीं रहा है ।

दूसरा, इसी तरह का शौचालय का विषय भी है । शौचालय बनता तो नहीं है लेकिन पता नहीं कौन सर्वे करते हैं कि ओ0डी0एफ0 उस वार्ड को, उस पंचायत को मिल जाता है ? यह भी जॉच का विषय है । पैसा मिला नहीं है 12-12.5 हजार लेकिन ओ0डी0एफ0 हो गया । शौचालय मिला नहीं लेकिन ओ0डी0एफ0 हो गया है । अभी जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ है, मस्तिष्क रोग ए0ई0एस0 जिसको बोलते हैं, उसमें शौचालय का भी एक बड़ा योगदान है क्योंकि शौचालय नहीं होने से अनहाइजिनिक कंडीशन से बच्चे को यह बीमारी हुई है और ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर में देखा जाय तो 60 परसेंट जो बच्चे एडमीट हुये हैं हॉस्पीटल में, उनके घर में शौचालय नहीं थी । यह जॉच का विषय है कि जब शौचालय 60 परसेंट का नहीं था तो क्या उस जगह को ओ0डी0एफ0 कर दिया गया है ? अगर किया है तो किस दबाव में किया गया है और क्यों किया गया है ? शौचालय दूसरा लूट-खसोट का एक मामला है।

टर्न-17/आजाद/01.07.2019

...... क्रमशः ....

श्रीमती एज्या यादव : सात निश्चय में जो भी चीज हुआ नली, गली, रोड ईट वाज द कम्पलीटली डिसऑरगाईनाइज्ड सिस्टम के तरीके से हुआ । रोड बन गया तब ध्यान आया कि यहां नली बनाना चाहिए तो फिर रोड को तोड़ा जा रहा है और नली को बनाया जा रहा है । पैसे की बर्बादी सरकार की हो रही है और यह पैसा सरकार का नहीं है, यह हम जो टैक्स में पैसा देते हैं, यह वह पैसा है । कहा जाय कि डायरेक्टली हमलोगों का पैसा जो हम सरकार को दे रहे हैं विकास के लिए, इस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लूट-खसोट करने के चलते कभी रोड बनाते हैं तो कभी तोड़ते हैं तो फिर नली-गली बनाते हैं और सरकार की पैसे की, राशि की काफी बर्बादी हो रही है ।

कुपोषण दूर करने के लिए आई रियली अपलोड द कांग्रेस गवर्नमेंट, वे लोग आंगनबाड़ी का सिस्टम शुरू किये ताकि जो गर्भवती महिलायें हों, बच्चे हों, उनको प्रोपर भोजन मिले, माल न्यूट्रीशन नहीं हो लेकिन आज जब मुजफ्फरपुर में बच्चे भर्त्ती हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि कुपोषण तो हटा ही नहीं । 15 साल से सरकार क्या कर रही थी कि कुपोषण नहीं हटा ? आज बच्चे 15 वर्ष के हो गये और कुपोषित हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,स0वि0स0 ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

माँ 15 साल में बच्चा पैदा कर रही है और एक माँ एक बिता, 6 ईंच का बच्चा पैदा करता है, समझ में नहीं आता है कि ये इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है । आप किसी दिन हॉस्पीटल पहुँच जाय, दुबली-पतली 16 वर्ष की महिलायें छोटे-छोटे, 6 ईंच के बच्चा के साथ पड़ी रहती हैं । क्या इज इट नॉट एन एक्जामपुल ऑफ माल न्यूट्रीशन । 15 साल से यह सरकार क्या कर रही थी और 6 साल से केन्द्र में बैठी हुई बी0जे0पी0 की सरकार जो अपने आप ही अपना पीठ थपथपाती है, यह क्या कर रही है कि अभी तक माल न्यूट्रीशन इंडिया से खतम नहीं हुई है ।

अगर शिक्षा विभाग की बात की जाय तो सब जानते हैं लेकिन मुँह सिया हुआ है और आँख सबका बन्द है । यहां कोई विधायक नहीं है, कोई सिनियर प्रभावी पदाधिकारी इनके अन्दर नहीं हैं जो अपने विधान सभा क्षेत्र में जहां वे पोस्टेड हैं, वहां के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने ले जायेंगे । वहां पर कभी नहीं पढ़ायेंगे, वे चाहेंगे कि पटना के नोट्रेडम में पढ़ाये, वे चाहेंगे कि देहरादून के

विलियम्स स्कूल में पढ़ाये आखिर क्यों ? विधायक हैं, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल का विकास हुआ है, यहां भी स्कूल का विकास होना चाहिए । एक सेल्फ सफिसियेन्ट व्यक्ति कैसे बनेगा, आप शिक्षित कर दीजिए, आपको स्वास्थ्य पर लेक्चरर देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ एंड हाईजिन पर आपको लेक्चरर देने की जरूरत नहीं है । आप शिक्षित बनाईए, हेल्थ, हाईजिन, स्वास्थ्य अपने आप ही सुधर जायेगा । आज आप स्वच्छता अभियान शुरू कर रहे हैं । कोई इसकी जरूरत नहीं है । आप शिक्षित कर दीजिए, नौकरी करेंगे, लोग स्वस्थ्य रहेंगे, लोग हेल्थ कांसेस होंगे और स्वच्छता के प्रति इनका झुकाव बढ़ेगा । स्कूल है, लेकिन छत चूता है, बरसात में बच्चे नहीं पढ़ते हैं । टीचर्स हैं लेकिन वे पशु गणना में बीजी रहते हैं, खिचड़ी के आंकड़े जोड़ने में बीजी रहते हैं, अंडा खरीदा कर आया, उसका हिसाब करने में लगे रहते हैं । पढ़ाते कम हैं लेकिन इन कामों में ज्यादा लगे रहते हैं, लगता है कि जो टीचर्स हैं, उनकी गरिमा ही खतम हो गई है । मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं समय रहते अपने प्रोफेसरी को छोड़ दिया । नहीं तो पता नहीं मैं भी अंडा ही गिनती रहती या खिचड़ी का चावल ही देखती रहती । इसलिए आज एक टीचर्स की गरिमा को खतम कर दिया गया है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । शिक्षक को शिक्षा तक ही सीमित रहने दें, मोटिवेट करें, वे भी मोटिवेटेड हो रहे हैं ।

राईट टू एजुकेशन की बात बहुत जोर-शोर से हुआ है और जब पिछले साल बजट आया तो शिक्षा में 2हजार करोड़ रू0 की बढ़ोतरी हुई । बड़ी आशा थी, बड़ी हमलोगों की उम्मीद थी कि शिक्षा में कोई नया विकास होगा । लेकिन यह सिर्फ बोलने के लिए रह गया कि एजुकेशन पर बहुत बड़ा बजट दिया गया है, लेकिन रियल्टी क्या है ? मैं पूछती हूँ कंस्टीच्यूशन हेज गीवेन द राईट टू एजुकेशन टू ऐवरी सिटिजेन ऑफ दीस कन्ट्री, लेकिन वोट ईज राईट टू एजुकेशन यह मालूम है । राईट टू एजुकेशन किन पारामीटर को इंकम्पास करता है, यह मालूम है । राईट टू एजुकेशन मिन्स कि एक अच्छा ब्लिडिंग होना चाहिए, स्कूल में ड्रिकिंग वाटर फैसिलीटीज होनी चाहिए, टॉयलट होना चाहिए, क्वालिफायड टीचर्स होना चाहिए एंड टीचर्स-पीपुल्स रेसिया इज द मेनटेन । टीचर्स-पिपुल्स रेसिया कहीं पर मेनटेन नहीं है, कहीं पर 80 बच्चे हैं तो कहीं 120 बच्चे हैं तो उसपर एक ही टीचर हैं । टॉयलेट कितने स्कूल में हैं, आप गिनकर बता देंगे । टॉयलेट स्कूल में है नहीं, ड्रिकिंग वाटर तो छोड़ ही दीजिए, ड्रिकिंग वाटर तो है ही नहीं । जब यह सब मेनटेन ही नहीं है तो राईट टू एजुकेशन की चर्चा क्यों होती है, एजुकेशन पर बजट बढ़ा देने से फायदा क्या है जब राईट टू एजुकेशन की परिभाषा का पारामीटर ही

नहीं मालूम है । मध्य विद्यालय जो है, उनको तो उत्क्रमित कर दिया जाता है, लेकिन क्या स्पेशलाईज्ड टीचर्स भेजे जाते हैं, वही टीचर्स हिन्दी पढ़ाता है, वही टीचर्स इंगलीश भी पढ़ा देता है, आई एम सो सौरी, इंगलीश का टीचर्स हिन्दी कैसे पढ़ा देता है और मैथ का टीचर्स हिस्ट्री कैसी पढ़ा देता है, फैक्ट ईज दीस आँखे खोले, हर विधान सभा क्षेत्र में यही हो रहा है कि हिस्ट्री का टीचर्स हिन्दी, इंगलीश, मैथ सब पढ़ा दे रहे हैं । टीचर्स की भारी कमी है । आखिर जो 2हजार करोड़ रू0 का बजट बढ़ाया गया, वह किस चीज पर बढ़ाया गया जब अभी भी टीचर्स की कमी है । ऐसे बच्चे मैट्रिक में फेल नहीं करेंगे तो पास करेंगे ? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेवारी कौन लेंगे, आखिर टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं कंट्रेक्टचुअल पर हैं तो कहीं हाई सैलरी है, एक ही काम के लिए किसी को इकुअल वेज नहीं मिल रहा है, कंन्स्टीच्यूशंस की तो धज्जी उड़ा दी गयी है । इकुअल वर्क करते हैं लेकिन इकुअल पेमेन्ट नहीं मिलता है । इस तरह से शिक्षा का जो सिस्टम है, वह कभी सुधर नहीं पायेगा। जिस दिन हम विधायक, जिस दिन हम बड़े-बड़े पदाधिकारी यह सोच लें कि अपने विधान सभा के सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ायेंगे, सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करवायेंगे तो यह अपने आप ही ठीक हो जायेगा । लेकिन हम काँप जाते हैं, हम कलप जाते हैं यह सोचकर कि इसमें हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे तो शिक्षा की स्थिति काफी बदतर है। हाईयर एजुकेशन में फीस बढ़ा दिया गया है । जबकि फ्री एजुकेशन की चर्चा महात्मा गाँधी जी किया करते थे । उस हिसाब से ग्रेजुयेशन तक फीस माफ कर देना चाहिए ताकि गरीब बच्चे जो हैं, ये ग्रेजुयेशन तक पढ़ाई कर सकें । अगर एक बच्चे ग्रेजुयेट हो जायेंगे, एक सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी नहीं भी मिले तो कुछ न कुछ करके कमाना शुरू कर देंगे । तो एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें भारी सुधार की जरूरत है ।

अगर स्वास्थ्य की बात की जाय तो हॉस्पीटल में डॉक्टर बहुत कम हैं । गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें तो डॉक्टर भी नहीं हैं, उसमें खेत-खलिहान बना रहता है । जनता कहती है कि हमें इतना दूर जाना पड़ता है, यहां डॉक्टर को बुलाया जाय और डॉक्टर का एक अलग लॉबी रहता है, आप एक पर कमप्लेन कीजिए तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है । लेकिन रिजल्ट ईज जीरो, काम कुछ नहीं हो रहा है । जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं हैं, लैब टेकनिसियन की भारी कमी है । बाहर से डॉक्टर को बुलाकर लाया जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, लेकिन बिहार के डॉक्टर को उस लायक नहीं समझा जा रहा है कि यहां पर भर्त्ती किया जाय । टीचर्स और डॉक्टर कंट्रेक्ट

पर काम नहीं कर सकते हैं । यह इनोवेटिव वर्क है, इनको जब तक मोटिवेट नहीं किया जायेगा, जब तक ये सौ प्रतिशत वर्क नहीं कर पायेंगे । Teachers and doctors should never be eployed on the basis of contract. स्वास्थ्य में कम से कम हरेक जिला में एक-एक मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है । पेसेंट बहुत है, पेंसेट-डॉक्टर रेसियो इतना ज्यादा है कि गैप ईज सो बीग कैन नॉट ब्लेम द डॉक्टर । आप पी0एम0सी0एच0 में मरीज को देखने के लिए जाईए, आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलता है । जमीन पर पेसेंट सोये रहते हैं और उसी में कुत्ते भी घुमते रहते हैं । कुत्ते से बच-बचाकर अन्दर जाना पड़ता है, जानवर, चूहे सब ऑपरेशन थियेटर के अन्दर रहते हैं । स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, गंदगी का अम्बार आपको सरकारी अस्पताल में मिल जायेगा, यह मौत का पर्याय बन चुका है सरकारी हॉस्पीटल । जब आई0जी0आई0एम0एस0 का निर्माण हुआ था तो ये एम्स के पैटर्न पर बनाया गया था कि एम्स वाला फैसिलीटीज हमारे आई0जी0आई0एम0एस0 में हो, फिर क्या ऐसा हो पाया ? एम्स में जहां 5 हजार रू0 बच्चे को पढ़ाई में देना पड़ता हैं, जहां आई0जी0आई0एम0एस0 में 20 गुना ज्यादा फीस देना पड़ता है और एक लाख रू0 ऑलमोस्ट आई0जी0आई0एम0एस0 में लग जाता है । जब एम्स के पैटर्न पर बनाया गया तो यहां का फीस क्यों बढ़ा दिया गया ? ये गरीब बच्चे हैं, ये अच्छे अंक लाकर भी इसमें पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं । आई0जी0आई0एम0एस0 का जो प्राइवेट वार्ड है, नोट किया जाय, इसका रेट बहुत महंगा है और एक साधारण परिवार के लोग प्राइवेट वार्ड को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं । बेड्स की कमी है, बेड को नहीं बढ़ाया जा रहा है और अभी जो इनसेफलाइटीस मुजफ्फरपुर में हुआ है, इसमें डॉक्टर का मानना है कि अगर बच्चों को दो दिन वेन्टीलेटर पर रखा जाता तो बच्चे बच जाते । 5 साल, 6 साल से सुन रहे हैं कि गर्मी में बच्चे मुजफ्फरपुर में मर रहे हैं और रिसर्च बताता है कि वेन्टीलेटर लाईफ सपोट में अगर बच्चों को रखा जाता तो बच्चे बच जाते । यह 15 साल से सरकार है, इस सरकार से इन 15 सालों का हिसाब मांगो तो पिछले 15 सालों का ये बात करते हैं और अपने 15 साल में ये काम किये, ये बताना नहीं चाहते हैं । 15 साल में इस सरकार ने क्या काम किया कि अभी तक वहां पर वेन्टीलेटर नहीं है । अगर वेन्टीलेटर बच्चों को मिलता तो कुछ बच्चे बच जाते । 15 साल तो डेढ युग होता है, 10 साल का एक युग होता है । डेढ़ युग बीत गया यह सरकार क्या कर रही है ? अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में भी इतनी ताकत क्यों नहीं है । जब इन 15 सालों की मैं बात करता हूँ तो मैटर को डायवर्ट किया जाता है सर

और पिछले 15 साल की बात की जाती है, प्लीज डु नौट डायवर्ट द मैटर, प्लीज स्टीक टू दी प्रेजेन्ट मैटर , टौक एबाउट दी हैपनिंग इन दी प्रेजेन्ट । आज जो प्रेजेन्ट सिनेरियो है वह ईट इज वैरी बैड वह मैटर है , आज शिक्षा त्रस्त है, स्वास्थ्य त्रस्त है, बच्चे मारे जा रहे हैं ...क्रमशः....

टर्न-18/शंभु/01.07.19

श्रीमती एज्या यादव : क्रमशः..Sir, we don't live in the past we live in the present and think about the future. Present क्या है 300 बच्चे मर चुके हैं। टी0वी0 बता रहा है 150 बच्चे मरे हैं । कोई क्रिकेट स्कोर में बिजी है, कोई सोने में बिजी है, लेकिन 300 बच्चे मरे हैं कोई नहीं बोल रहा है 160 के आगे-मंत्री जी को मालूम ही नहीं है कि 160 बच्चे से ज्यादा मरे हैं । विपक्ष में रहते हुए Sir please under estimate and under mind the विपक्ष अगर सरकार चलती है तो विपक्ष के साथ चलती है और विपक्ष ग्रेटर ऑल टू प्ले पक्ष वाले तो सिर्फ सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जो विपक्ष होता है उसका काम होता है सरकार की आंखें खोलना । आपका greatness होगा अगर हमारी बात सुनें और इस हिसाब से आप सुधार लायें । बिहार सिर्फ आपका नहीं है बिहार हमारा भी है और बिहार की तरक्की हम भी चाहते हैं। This is the Temple of development. विधान सभा में हमलोग बैठे हैं । इसे Temple of Development कहते हैं लेकिन Is it temple of development. क्या यहां विकास की बातें होती है ? या सेल्फ पीठ थपथपाने की बातें ज्यादा होती है । विपक्ष को दबाने की बात होती है । हाउस चले नहीं चले विपक्ष रहे नहीं रहे बजट पास कर दिया जाता है । विपक्ष को दबाया जा रहा है, कन्सटीच्वेशन की धज्जी उड़ाई जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेज तो गुलाम बनाते थे और हमलोग अपनो के हाथों गुलाम बन जायेंगे । इस बजट में बहुत कमी है गरीबों को ध्यान में रखना चाहिए था, माइनोरिटी को ध्यान में रखकर यह बजट बनाना चाहिए था । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ । थैंक्यू।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी ।

(माननीय सदस्य श्री ललन पासवान सदन में अनुपस्थित।)

सभापति(श्री विरेन्द्र कुमार सिंह) माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, आज बिहार सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा सदन में पेश किये गये बजट के उपर चर्चा हो रही है और माननीय सभापति महोदय जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं शायद वे दिल से इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं । चूंकि विरोध करने का उनका दायित्व है इसलिए विरोध करना उनके लिए भी आवश्यक है इसलिए वे विरोध कर रहे हैं । लेकिन मुझे मालूम है कि जब बिहार के गांव में जाते हैं और इस सरकार के यशस्वी कार्य जिसको देखकर जनता भी मुस्कुराती है तो ये भी उनके साथ मुस्कुराने का काम करते हैं । अभी हाल में संपन्न लोक सभा के चुनाव और यह जो लोक सभा का चुनाव हुआ है महोदय - सबसे बड़ी अदालत ने भी इस सरकार के पक्ष में फैसला दिया है और 53 परसेंट वोट लेकर के हमलोगों ने जीत हासिल की है बिहार की महान जनता के आशीर्वाद से । यह सब काम के आधार पर हुआ है, अगर इस सरकार के यशस्वी कार्य ने एक-एक गरीब के झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का कार्य किया है तो इस सरकार के बजट के कारण किया है क्योंकि हमको भी यह मालूम है और इनको भी मालूम है- 2005 में इस सरकार का बजट क्या था ? 2005 में जब सत्ता हमलोगों को मिली थी तो 24 हजार करोड़ के आसपास का बजट हुआ करता था और इस बार जो फरवरी में हमने बजट पेश किया है वह 2 लाख हजार करोड़ का बजट है । यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । महोदय, विपक्ष के मित्र जब विरोध करते हैं तो भूल जाते हैं कि जब इनका राजपाट चलता था बिहार में तो एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो गांव में सत्यनारायण भगवान का कथा लोग करते थे और 6 महीना तक वह ट्रांसफार्मर नहीं लगता था । कई बार गांव के लोग आपस में चन्दा इकट्ठा किया करते थे, ट्रैक्टर भाड़ा पर करते थे और तब जाकर ट्रांसफार्मर का स्थापना होता था । आज हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं वह जब टेलीफोन करते हैं तो कार्यपालक अभियंता अपने स्टाफ के माध्यम से 72 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है । महोदय, यह इस सरकार की उपलब्धि है । महोदय, मैं केवल बिजली विभाग की बात करता हूँ कि अगर 39 हजार 73 गांव में विद्युतीकरण करके और 1 लाख 6 हजार 239 टोलों और 32.49 इच्छुक परिवारों को नि:शुल्क

कनेक्शन दिया है तो क्या सरकार को इसके लिए वाहवाही नहीं मिलनी चाहिए । लेकिन विपक्ष के जो मित्र हैं वे केवल विरोधात्मक बात करने के लिए सदन में आते हैं । महोदय, आज पूरे बिहार में 23 से 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है और आज यही कारण है कि इस देश में और देश के साथ बिहार में ऐसा वातावरण बना है कि चाहे दिल्ली में बैठी कोई सरकार काम करती है या पटना में बैठी सरकार काम करती है तो गांव के एक गरीब झोपड़ी में टेलीविजन के माध्यम से भी उस विषय को जान जाता है यह हमारे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । महोदय, आज 71 हजार 672 सर्किट कि0मी0 बिजली के जो खराब तार हैं उनको बदलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हमने तो घरों में ही बिजली नहीं पहुंचायी, हम तो अब खेतों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है और हमारे बिहार के किसानों के लिए एक अमृत योजना के रूप में यह काम शुरू हो रहा है । दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना के माध्यम से हमने अगर घरों में बिजली पहुंचाई तो हम किसानों के खेत में भी बिजली पहुंचाने का काम हमारा युद्ध स्तर पर जारी है और हमारे विपक्ष के मित्र भी गांव में जाते हैं तो अपने वोटर को कहते हैं कि हमारे प्रयास से यह हो रहा है, लेकिन सदन में कहने के लिए ये साहस नहीं जुटा पाते हैं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर बिहार के गरीबों की चिंता इस सरकार ने की तो बिहार के किसानों की भी चिंता इस सरकार ने की और जिस दिन विद्युत् से सिंचाई शुरू होगी, जब विद्युत् से सिंचाई शुरू होगा तो जहां 100 रू0 के खर्च लगता था वहां 5 रू0 में सिंचाई हो जायेगा । यह इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है । महोदय, इसी सदन में जी0एस0टी0 पर बड़े प्रश्न उठाये जाते थे और मैं तो विपक्ष के साथियों को कहूंगा आर0एस0 नाम की जो संस्था है जिसने उसका विश्लेषण किया उसको भी ठीक से पढ़िये । इसने कहा है कि जी0एस0टी0 लागू होने से 78 परसेंट जो राज्य सरकार को आज कर मिल रहा है, जो उसकी हिस्सेदारी हुई है, जो केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी हो रही है वह इसके कारण हुई है महोदय और आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में बढ़कर के काम कर रही है । इसलिए कर रही है कि सरकार का खजाना सरकार जैसा करना चाहती है वैसा सरकार का खजाना हमारी इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन के कारण हुआ है । इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद जी0एस0डी0पी0 मौजूदा मूल्यों पर 5 लाख 72 हजार 827 करोड़ रूपया अनुमानित है और यह 2018-19 के संशोधित अनुमान से 5 परसेंट अधिक है ।

यह सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है । महोदय, कहा जाता है और मुझे तो कभी-कभी लगता है महात्मा गांधी जी को आदर्श मानने वाले लोग जब स्वच्छता की बात करते हैं यह भूल जाते हैं कि आजादी के इतने दिनों के पश्चात् अगर एक गरीब के घर में शौचालय नहीं बना था तो सबसे बड़ी विफलता थी और अगर इस काम को किसी ने किया है तो हमारी केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार और राज्य में एन0डी0ए0 की सरकार ने करके दिखाया है । यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सतत् इस बात को कहते हैं कि आगामी बापू की जयंती पर हम बिहार के एक भी किसी स्थान को एक भी घर को खुले में शौच नहीं जाने देंगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बापू को भी सम्मान है। महोदय, अपने इसी काम के आधार पर बिहार की सरकार ने 11 पुरस्कार प्राप्त किया है और अगर 11 पुरस्कार इस राज्य सरकार को मिला है इसके लिए सत्तापक्ष को तो गौरवान्वित होना ही चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी इसके लिए गौरव का अनुभव करना चाहिए क्योंकि अगर राज्य की खुशहाली सत्तापक्ष का दायित्व है तो विपक्ष का भी दायित्व है कि राज्य की खुशहाली होनी चाहिए । हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे सामाजिक निर्णय लिये हैं और उसमें सबसे बड़ा निर्णय है शराबबन्दी का निर्णय जो सीधे-सीधे एक सामाजिक बदलाव की ओर इस राज्य को ले जा रहा है और शराबबन्दी के माध्यम से हमारी सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है । जिन लोगों ने भी इसको चुनौती दिया है, जिन लोगों ने भी इसमें खलल डालने का प्रयास किया है वैसे लोगों को भी सरकार ने बख्शा नहीं है और वैसे लोगों को भी सरकार ने जेल में डालने का काम किया है । जिन परिवारों ने भी शराबबन्दी को अपनाया है उन परिवारों के परिवार में भी खुशहाली पहुंची है । यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि अगर सकल घरेलू उत्पाद जी0एस0डी0पी0 में अगर 17.9 परसेंट ग्रोथ हुआ है तो यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । इसपर सरकार को विपक्ष को धन्यवाद भी देना चाहिए । महोदय, आज सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे मित्र सदन में बैठते हैं तो सदन में यह भूल जाते हैं कि जनता मालिक है ।

क्रमशः

टर्न-19/ज्योति/01-07-2019

क्रमश:

श्री मिथिलेश तिवारी : हम सभी लोग, जो लोग भी इस सदन में चुन कर आते हैं, जनता के माध्यम से चुन कर आते हैं और जब जनता हमको भेजती है तो जनता इस बात का भी इंतजार करती है कि जो लोग भी सदन में जाते हैं तो सदन में कुछ सही बात बोल कर आंवे ताकि जनता को उन पर गर्व हो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देश में जो तीन सरकार की कल्पना साकार हुई है - केन्द्र की सरकार पूरे देश के विकास का खाका खींच रही है और दिन रात मेहनत कर रही है उसके बाद अगर राज्य की सरकार दो सरकार तो पहले दिखती थी महोदय, लेकिन यह पंचायत की सरकार है वो नहीं दिखती थी लेकिन आज सबसे बड़ा गौरव का अनुभव इस देश का हर एक व्यक्ति कर रहा है जो तीन सरकारों में सबसे सशक्त केन्द्र है वह है पंचायत सरकार तो आज पंचायत ग्राम पंचायतों में, मुखिया के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से, बी.डी.सी. के माध्यम से आज जो ग्राम पंचायत से चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं वो अपने पंचायतों का अगर विकास कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कारण हो रहा है और आज बिहार का एक एक गांव आज विकसित हो रहा है और उसी के कारण चाहें जितने भी बदलाव आपको दिख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को यह सरकार मजबूत कर रही है । उनका हर प्रकार का वित्तीय प्रबंधन कर रही है और उस वित्तीय प्रबंधन के कारण आज समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है । जीविका के माध्यम से जो हमारी गरीब महिलाएं थीं जो समाज में उपेक्षित थीं जो घर के अंदर रहती थी । पर्दा प्रथा के कारण उनके जीवन में बहुत प्रकार के संकट आते थे वैसी महिलाओं को भी समाज के बीच में लाकर के हमारी सरकार ने जीविका के माध्यम से उनके द्वारा कई प्रकार के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 96.50 लाख से भी अधिक परिवारों को इससे जोड़ा गया और 52 हजार ग्राम संगठन और 878 संकुल स्तरीय संघों का गठन करके सरकार ने एक बहुत बड़ा बिहार में एक रेखा खींचने का काम किया है जो विकास के लिए बहुत बड़ा है और आज हम सब लोगों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो रहा है । सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से और हमको तो लगता है चाहे वह सड़क दुर्घटना हो जाय या वह किसी प्रकार की आपदा हो जाय, आपदा के समय हमारी सरकार बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी मिलती है और पहले एक समय था छ: छ: महीने तक कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था, आपदा

का शिकार हो जाता था छः छः महीने तक उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता था लेकिन चाहे वह बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, ओलावृष्टि का मामला हो इस सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है और यह सरकार किसानों के साथ भी खड़ी रही है और यह सरकार एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी रही है और किसी भी किसान को किसी भी नागरिक को अब जाकर कलक्टर के यहाँ और राज्य सरकार के दफ्‌त्तर में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 में आयी गण्डक नदी में बाढ़ है महोदय, केवल मेरे एक विधान सभा में 52 हजार लोगों को छः छः हजार रुपया सरकार ने देकर उनकी जिन्दगी को बदलने का काम किया है । जब प्रधानमंत्री आवास की बात हम करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि अमीरों के लिए घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन गरीबों के लिए घर का सपना एक चांद देखने जैसा सपना है लेकिन आज जब गरीबों को 1 लाख 30 हजार रुपया प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से और बाकी पैसे जो हमारे मनरेगा के माध्यम से लगभग एक लाख 50 हजार का घर एक गरीब को जब मिलता है और जब पहला नारियल वह अपने घर के सामने फोड़ता है तो वहाँ एक तरफ जहाँ भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का जिन्दाबाद करता है तब 53 परसेंट वोट देकर एन.डी.ए. को फिर से सत्ता में जनता वापसी करती है । यह बिहार में बदलाव हुआ है और हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण, हमारे बजटीय उपबंध के कारण हुआ है । एक तरफ जहा हमं घर में बिजली पहुंचा रहे हैं वहीं हम घर में एक एक गरीब को घर की सुविधा दे रहे हैं। एक एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं । गांव की सड़कों का निर्माण हम बड़े पैमान पर कर रहे हैं । हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़के योजना के माध्यम से जो पी.एम.जी.एस.वाय. के रोड थे उनका भी बिहार में अब कोई आने वाले दिनों में कोई सड़क नहीं बच जायेगी । इसप्रकार से एक एक विषय पर यह सरकार जबर्दस्त काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि देश का एक एक व्यक्ति राज्य का एक एक व्यक्ति एन.डी.ए. के साथ खड़ा है और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं । शिक्षा की बात करते हैं । कौशल विकास की बात करते हैं तो हमको पुराने दिनों की भी याद आ जाती है महोदय, जब कभी इसी बिहार की चर्चा हुआ करती थी, चरवाहा विद्यालय के नाम पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन यह राजेन्द्र बाबू का बिहार है और राजेन्द्र बाबू के बिहार में चरवाहा विद्यालय नहीं खुलना चाहिए, राजेन्द्र बाबू के बिहार में अगर खुलना चाहिए तो आई.आई.एम. खुलना चाहिए और वह हमारी सरकार ने खोल कर दिखाया है । हमारे बिहार के तमाम हाई स्कूलों में प्रयोगशाला के लिए पाँच

पॉच लाख रुपया दिया गया है और तमाम स्कूलों में बेंच खरीदने के लिए अगर हमने तीन तीन लाख रुपया भेजने का काम किया है तो स्कूलों की स्थिति भी बदल रही है । हमारी बच्चियां साईकिल पर चढ़कर विद्यालय में आती है और बच्चियॉ जब साईकिल की घंटी बजाती है तो साईकिल की घंटी बजाने वाली बच्चियॉ इस बात के लिए प्रेरणा दे कर जाती है कि यह वैसी सरकार है जो एक गरीब की बेटी को जिसने कभी साईकिल का सपना नहीं देखा होगा उसको स्कूल भेजने के लिए साईकिल देती है । यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । उनको इसमें हर प्रकार का - चाहे उनको पोशाक का मामला हो, छात्रवृति का मामला हो हमारी सरकार हर गरीब की बेटियों को पढ़ाने के लिए, हर गरीब के बच्चे को उन्नत शिक्षा देने के लिए चाहे चार लाख रुपये का लोन की बात हो, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय में जो प्रावधान किया है, यह पूरे बिहार को बदलने का अभियान है और बिहार बदल रहा है । बिहार आगे बढ़ रहा है और जिनको यह दिखायी नहीं देता है वह जीरो पर आउट होते हैं चुनाव में, यह बात इस बिहार में स्थापित हुआ है । सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कहने वाले तो आज कहते हैं कि हौस्पिटल में कुत्ते बिल्ली घूमते हैं और उनको पता नहीं है पहले हौस्पिटल में लोग डर के मारे नहीं जातें थे और आज हौस्पिटल में इसलिए भीड़ होती है कि आज हौस्पिटल में इलाज होता है और हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है चाहे पी.एम.सी.एच. चले जाईये, जयप्रकाश नारायण हौस्पिटल में चले जाईये या राज्य के किसी पी.एच. सी. में चले जाईये अब हर जगह चिकित्सा होती है और पहले जो खून का टेस्ट खटमल किया करते थे, खून का टेस्ट जो मच्छर किया करते थे उसके लिए आज अलग व्यवस्था बनी है और आज बिहार की जनता इस बात को जानती है और इस बात को विपक्ष हमारा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । आज हालात बदल गए हैं । ठीक है बीमारियॉ बढ़ी हैं, सरकार के लिए चुनौती हैं सरकार उस चुनौती का सामना मजबूती से कर रही है और हम ठोक कर बोलते हैं कि किसी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए एन.डी.ए. सरकार हमारी तैयार है । हम किसी चुनौती से भागने वाले लोग नहीं हैं । इसलिए हमारी सरकार ने चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो उल्लेखनीय योगदान किया है । कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार में आई.आई.एम. खुलेगा लेकिन जिनको नहीं पता वह जान लें जिनकी आंखें गड़बड़ हैं वे मंगल पाण्डे जी की अस्पताल में जाकर जॉच करा लें और गया चले जांय उनको पता चलेगा कि वहॉ आई.आई.एम. बन रहा है लेकिन आप बताईये आखिर पहले क्यों नहीं खुला । अब लगभग दो

जिला पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है । सरकार दूसरे एम्स के लिए काम कर रही है । पहला एम्स बिहार में खुला तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय खुला । सुषमा स्वराज जी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी तब खुला दूसरा अगर आज एम्स खुलने की बात हो रही है, आज भी एन.डी.ए. की सरकार है । अगर बिहार में एक एम्स खुला और दूसरा खुलनें की बात है तो एन.डी.ए. कर रही है । पहले कभी किसी को किसी ने रोका नहीं था और इसालिए आज मैं कहना चाहूंगा कि आज बिहार सरकार की आलोचना करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जब कोई परेशानी होती है वहीं जाते हैं वहीं सब सुख सुविधाा पाते हैं और बाहर निकलते हैं तो आलोचना करते हुए चले जाते हैं, यह जनता देख रही है और जनता देखती है तो जनता पॉच साल पर जब वोट का समय आता है तो जनता उस समय इस विषय यपर अपना रिऐक्शन देती है और जब रिऐक्शन देती है तो खूब देती है जो इस बात 53 परसेंट के माध्यम से मिला है । महोदय, सबसे बड़ी बात है कि कहा तो जाता है कि बिहार में अपराध बहुत बढ़ रहा है लेकिन अब कोई ऐसा भी कोई विषय आता है क्या कि कोई अपराधी किसी मंत्री के आवास से पकड़ा जाता हो । क्या ऐसी भी कोई बात आती है कि किसी अपराधी को छोड़ने के लिए कोई मंत्री या विधायक के यहॉ से टेलीफोन जाता हो। हमारी सरकार पूरी तरह अपराधियों के खिलाफ है और हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि अपराधी बिल में धुसते जा रहे हैं । हमारे राज्य का डी.जी.पी. दिन रात लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं । ये बदलाव हुआ है और हमने बिहार में अमन चैन के राज की स्थापना की है । हर प्रकार का मामला चाहे आज अनुदान के मामले में आप देख लीजिये । अनुदान के मामले में जो बहुत सारे ऐसे बोर्ड निगम बंद हो गए थे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था महोदय, बिहारा राज्य पुल निर्माण निगम इसके हालात क्या थे महोदय, 2005 के पहले और आज बिहार का सबसे ज्यादा प्रौफिट वाला निगम बन गया है । यह इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन और इस सरकार के सफल संचालन का नतीजा है ।

क्रमशः

टर्न-20/01.07.2019/बिपिन

श्री मिथिलेश तिवारी : क्रमशः महोदय आज हर घर में नल से जल देने की बात हो रही है, कभी किसी ने सोचा था कि हर गरीब के घर पर 350 फीट नीचे से पानी आएगा और उसको पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी ? यह इसी सरकार ने करके दिखाया है

जो बहुत जगह चालू हो गया और बाकी एक साल के अंदर लगभग हर परिवार को हर घर नल के जल के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने वाला है चाहे हमारे पी.एच.ई.डी. विभाग के द्वारा हो, चाहे अन्य प्रकार के योजनाओं से लोगों ने बनाया था हर प्रकार के जो पेयजल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है । महोदय, मौनसून जब आता है वर्षा कम होती है सूखा पड़ता है उसके लिए भी सरकार ने हर प्रकार की तैयारी की है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार में मिट्टी का नमूना लेकर अगर उसकी जांच हो रही थी, बहुत सारे लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते थे लेकिन जब इसकी जांच हुई और उस जांच को जिस किसान ने पहचाना, महोदय, उसके हिसाब से जब उन्होंने खेती शुरू की तो उसने अलग-अलग प्रकार के किसानों के अनुभव आए हैं और उस के आधार पर हमारे किसानों की आमदनी दुगुनी होती जा रही है । महोदय, किसी ने सोचा था कि बिहार में भी इथनॉल का उत्पादन होगा लेकिन अगर इसी बिहार में पहले गन्ना की खेती करने वाले किसान केवल चीनी का उत्पादन जानते थे कि गन्ना की खेती से केवल चीनी का उत्पादन होगा लेकिन आज हमारी सरकार ने इथनॉल का उत्पादन करने के लिए क्रांति का जो निर्णय लिया है उससे हमारा जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें एक आन्दोलनात्मक रास्ता दिखाई दे रहा है । हम बिहार के किसानों के द्वारा उपजाए हुए जो गन्ना है उसके माध्यम से हम पेट्रोलियम पदार्थों का कीमत कम करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे । जो किसान गन्ना लगाकर आत्महत्या करने का प्लान किया करते थे आज से 10 साल पहले, वह किसान आज खुशहाल हो रहे हैं । इस प्रकार की वित्तीय प्रबंधन हमारी सरकार ने किया है । इसलिए महोदय, मैं तो इतना चाहूंगा कि पशुपालन का क्षेत्र, आप कहते हैं पशुपालन के क्षेत्र का जब नाम आता है तो इसी बिहार ने गोल्ड मेडल लिया था महोदय । पशुपालन विभाग के नाम पर तो गोल्ड मेडल मिला था बिहार को और आज यही बिहार पशुपालन के मामले में जहां हॉस्पिटल का अता-पता नहीं था, वहां भवन बनाए जा रहे हैं, अच्छे-अच्छे भवन बनाए जा रहे हैं, वहां चिकित्सकों की व्यवस्था हो रही है, जानवरों का टीकाकरण हो रहा है और इसके लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है महोदय । सूखे में उनके पीने के पानी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है । यह पहले कभी नहीं हुआ था महोदय और यही हमारी सरकार का सबसे बड़ा, अगर उसका मार्ग प्रशस्त होता है तो सबसे बड़ा हमारा यह आधार है महोदय । महोदय, मछली पालन होते थे बिहार में, आपको मालूम है बिहार का सबसे बड़ा भू-भाग सालों भर पानी में डूबा रहता था । बहुत सारे मछुआरे ऐसे थे कि जो अगर मछली बहुत मुश्किल से निकाल लेते थे तो उनके माथे पर से मछली का टोकरी लोग छीन करके चले जाते थे। उनका

कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि जो मछली पालने वाले लोग थे, एक बड़े उद्योग के रूप में बिहार में मत्स्यपालन का उद्योग स्थापित हो रहा है और उसके लिए के.सी.सी. द्वारा उनको लोन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है । चाहे डेयरी उत्पादन करने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादन करने वाला हो या मछली उत्पादन करने वाला हो, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है महोदय ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, सबसे बड़ी बात बार-बार विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि आरा में प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार की बोली लगाकर चले गए और जो लोग यह बात कहते हैं वह भूल जाते हैं कि हाथ में लेटर पैड और कलम लेकर जब घर से निकलते हैं तो उसी प्रधानमंत्री पैकेज के नाम पर सड़क निर्माण की बात करते हैं।

महोदय, आज बिहार में एक समय था जब खराब रास्ता में लोग घुसते थे तो लोग कहते थे कि बिहार आ गया । एक वह भी समय था महोदय जो बिहार के सड़कों पर चलने वाली गाड़ी का हॉर्न छोड़ कर बाकी सारा डिपार्टमेंट उसका आवाज करता था महोदय और आज बिहार में चले जाइए, चाहे पूर्णिया से हमारे माननीय विधायक आते हों या किशनगंज से या कैमूर से आते हों, चाहे गोपालगंज से आते हों, हमारे सभी माननीय सदस्यों को चार घंटा और पांच घंटा से ज्यादा समय नहीं लगता है और आज बिहार के सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है तो हमारे बजटीय प्रबंधन के कारण हुई है, हमारे सरकार की निष्ठा और सरकार के काम के माध्यम से हुई है । आज हमलोगों ने हर सेक्टर में बड़े बदलाव किए हैं । क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है । इसलिए मैं तो चाहूंगा कि सदन को पूरा विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के जो माननीय सदस्य हैं सब लोगों को हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके देना चाहिए कि आज दो लाख करोड़ का बजट इस सदन में आया है और सरकार कह रही है कि आवश्यकता होगी तो अलग से भी हम फिर से सप्लीमेंट्री लाएंगे । ऐसी सरकार पर गर्व करना चाहिए महोदय । इसलिए हम अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्य और बजट जो पेश हुआ है उसके समर्थन में अपनी बात कह कर और महोदय आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री बजट के पक्ष में और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

महोदय, आजादी के 70 साल हो गए । कई सरकारें इस सदन में आई और गई । 50 साल, 55 साल कांग्रेस रही है । 15 साल माननीय लालू प्रसाद जी की सरकार रही है । बिहार में दल और पार्टी से उपर उठकर हम यहां बैठे हुए लोग हैं । जब हम आते हैं तो शपथ लेते हैं, भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन जब बात विकास की आती है, जब बात विचारों की आती है तो पार्टी और दलों में बँट जाया करते हैं । हम बिहार को अलग कर देते हैं और दल को कपार पर रख लेते हैं और माथे पर रखते हैं दलों के विचारों को । हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि निश्चित तौर से हम नहीं करते हैं लेकिन दक्षिणी भारत के राज्य विकास के सवाल पर पूरा राज्य चाहे पालिर्यामेंट की बात हो, चाहे विधान सभा की बात हो, एक साथ खड़ा होता है लेकिन हम इससे विचलित हो जाते हैं । यही कारण रहा है कि हम जब विकास के चर्चा करने की बात करते हैं तो हम आरोप-प्रत्यारोप से एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं और सही बातों को दबा देने का काम करते हैं लेकिन बात कहना पड़ेगा और आज नहीं, कल लोग तो बताएंगे कि यह सदन बिहार का सर्वोच्च सदन है । महोदय, विकास की अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पर हमें आइने में पहले की सरकार को भी देखनी चाहिए । कई लोग हैं भी । कल का बिहार, वर्त्तमान का बिहार और आने वाला बिहार कैसा होगा, इसपर हमको निश्चित रूप से चर्चा करना चाहिए क्योंकि सबका हक है । सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं।

महोदय, हमको एक बात याद आ रहा है । हमलोगों ने पढ़ा है, देखा नहीं । 1540 में शेरशाह इसी भारत का एक बादशाह हुआ करता था जिस जगह से मैं आता हूं । उस समय वह कल्पना करता था कि कन्याकुमारी और दिल्ली से बंगाल की खाड़ी, बंगाल तक जी.टी. रोड का निर्माण कराया था और पर्यावरण के लिए दोनों तरफ पेंड़ लगवाया था । चार-पांच काम किया था विकास का साढ़े चार सालों में और बाद में बारूद के ढेर में आग लग गई और मर गया, कोई मारा नहीं लेकिन मृत्यु हो गई थी । सिक्के का प्रचलन किया, जमीन का पैमाइश किया । कुंए खुदवाए, सराय बनवाए । डाक सेवा बहाल किया । साथी चर्चा करते हैं कि क्या हुआ ? हमलोगों ने देखा है, पटना में हमलोग पढ़ते थे और ...

(व्यवधान)

महोदय, शक्ति जी को चिंता इस बात की है कि जो मैं बोलने वाला हूं वह पहले से इनको सूचित है कि मैं क्या बोलने वाला हूं । तो महोदय, मैं चर्चा कर रहा था- 80 देखिए, 85 देखिए, 67 देखिए, जो बिहार था .... क्रमशः

टर्न : 21/कृष्ण/01.07.2019/

श्री ललन पासवान (क्रमश :) और उसके बाद 1990 से लेकर 2000 तक का जो बिहार था, हमलोग सासाराम से बस में यहां आते थे, 9 घंटे लगते थे तो इस सवाल पर चर्चा करें । सड़कों पर चर्चा करें, बिजली पर चर्चा करें । पटना में कई बार छात्रों से गोली चल जाया करती थी, बिजली के सवाल पर सैदपुर कैम्पस में, पत्थर चला करते थे । चेहरा पसंद न हो तो कम से कम बिहार पसंद है तो उसका सच कहने की जरूरत है शक्ति बाबू । यह बात तो कहिये । अब तो यह बात नहीं है । उस समय पत्थर चलते थे । 9 घंटे लगते थे सासाराम से यहां आने में । चाहे सदानन्द बाबू की सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो । मैं यह नहीं कह रहा हूं । लेकिन विचारों की बात हो, सामाजिक परिवर्त्तन की बात हो । डा0 राम मनोहर लोहिया की बात करें, स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, चाहे राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे बाल-विवाह की बात करें । जो श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, जो श्री सुशील कुमार मोदी जी ने किया है, वह सच तो कहना ही पड़ेगा । हम नहीं कहेंगे तो आनेवाली पीढ़ी कहेगी । यह तो बताना ही पड़ेगा कि सड़कों का जाल बिछा है । पहले 9 घंटे में सासाराम पहुंचते थे । कितने स्टेट हाई-वे और कितने राष्ट्रीय राज मार्ग बने, इसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी । महोदय, राजा राम मोहन राय जी के बाद ज्योति राव फूले के बाद, सावित्री फूले के बाद, लोक नायक जयप्रकाश जी के बाद बिहार में सामाजिक परिवर्त्तन और रचनात्मक कार्यों की शुरूआत माननीय श्री नीतीश कुमार और श्री सुशील कुमार मोदी जी ने किया है । यह तो कहना ही पड़ेगा । शक्ति बाबू चाहे आप जितना भी चुटकी लगा लीजिये । लेकिन सच्चाई पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं । इसीलिए बाल-विवाह की चर्चा की। हमलोगों के गांव में 8 साल, 9 साल की बच्चियों की शादी हुआ करती थी और 9 साल, 10 साल और 11 साल के बच्चे जाकर शादी किया करते थे । महोदय, सारी चीजे शराबबंदी से लेकर आप चर्चा करें । आज कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, जहां 18 घंटे, 20 घंटे और 22 घंटे बिजली नहीं रहती है । हमारे यहां नवहट्टा, रोहतास, जिसकी चर्चा कर रहे थे, कहां चले गये माननीय सदस्य, जो चुआड़ी की पानी की बात कह रहे हैं, कैमूर की पहाड़ी पर आजादी

के 70 साल नहीं और 10 साल पहले तक आदिमानव का जो इलाका रहा है, वहां भी आज सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली श्री नीतीश कुमार, श्री सुशील कुमारी मोदी और श्री बिजेन्द्र बाबू की कृपा से मिल रही है और वहां के वनवासी और आदिवासी उसका लाभ उठा रहे हैं । आप से कम सुन्दर वहां यादव नहीं रहता है और वहां की लड़कियां भी आपसे कम लंबी नहीं होती है शक्ति भाई, वे भी आज बिजली के बल्ब में रहते हैं । अब वह जमाना बदल गया है, जिस जमाने में ढिबरी और लालटेन जला करता था । इसलिए सच बात तो हमलोगों का कहना ही पड़ेगा । महोदय, परिस्थितियां बदली हैं इस राज्य में और बदल रही है । यह ठीक बात है कि शेरशाह ने जिस पैमाने पर देश में विकास का कार्य किया तो आपको भी मौका मिला, माननीय श्री सदानन्द बाबू को तो 55 साल मिला ।

श्री सदानन्द सिंह : दो वर्ष में इनका जो परिवर्त्तित स्वरूप में देख रहे हैं और भाषण का जो ट्रेंड चेंज कर रखे हैं, देख रहे हैं कहां से कहां धरती ऊपर से नीचे चली गयी। वाह हो ललन पासवान जी ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, जब विपक्ष में एक मत नहीं है, किसी ईसू पर विपक्ष कई भागों में बंट जाते हैं तो माननीय सदस्य जो बगल में बैठते थे और सदानन्द बाबू का आज राग बदला हुआ था और इधर आर0जे0डी0 का राग अलग था और इधर दूसरी पार्टियां जो हमारे विरोधी दल के लोग थे, उनका राग अलग था । एक साथ बैठे लोगों में राग बदल सकता है । तो माननीय सदस्य ललन बाबू काफी संवेदनशील सदस्य हैं और पुराने सदस्य हैं तो इन्होंने पूरी चीजों की समीक्षा की, जानने की कोशिश की और जब इनको सही जानकारी मिल गयी तो इससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं तो माननीय सदस्य को प्रसन्न होना चाहिए महोदय ।

श्री ललन पासवान : महोदय, एन0 डी0 ए0 में मैं उस समय था और उस समय भी मैंने माननीय सदानन्द बाबू को अगाह किया था, 55 साल रहे हैं आप और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इधर चला आया हूं । ये भी इधर ही थे आज से दो साल पहले, जो सदानन्द बाबू हमारी चर्चा कर रहे हैं । हमारे बदलाव से

पहले इनको भी चिंतन करना चाहिए कि ये कहां थे इसके पहले । हम तो उस समय भी एन0डी0ए0 में थे और आज भी एन0डी0ए0 में हैं । हम कोई बदलाव नहीं किये हैं । हम एन0डी0ए0 में है । महोदय, सामाजिक परिवर्त्तन खासकर बिहार में हुआ है । अवसर सबको मिला है और आज सबको चिन्ता करने की जरूरत है । हमने कहा कि मेरे पहाड़ पर आजादी के 70 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी ने पहली बार गये, मैं इन वनवासियों, आदिवासियों की बात कह रहा हूं, माननीय शक्ति यादव जी छड़प-छड़प रहे हैं । तो मैंने कहा कि इनसे कम सुंदर पुरूष और महिलायें वहां नहीं है, जो वहां यादव समाज के लोग रहते हैं । आजादी के बाद भी वे चुआड़ी का पानी पीया करते थे । सड़ी हुई चुआड़ी का पानी जिसमें सांप, बिच्छु और मरे हुये पशु बह कर जाते थे, वहां आदिवासियों की 70 प्रतिशत आबादी है । वहां पहली बार श्री नीतीश कुमार गये, रेहन्द में जहां डी0एफ0ओ0 संजय सिंह की हत्या हुई थी, पहली बार कार्यक्रम हुआ, वह पहाड़ उग्रवाद मुक्त हुआ, पुरा पहाड़ उग्रवाद से प्रभावित था, जो चार राज्यों - छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उग्रवादियों की शरण स्थली थी, जो अभी मुक्त हुआ है और एन0डी0ए0 की सरकार ने मुक्त करायी है, अब तो हमलोग भी चले जाते हैं, पहले तो अगर पुलिस भी जाती थी तो दो-चार मरा कर ही आती थी, डी0एफ0ओ0 मारे गये, रेंजर मारे गये । आज मैंने चर्चा भी किया कि वहां एक मोडल थाना बनना चाहिए । इससे संबंधित हमारा सवाल भी था और पहली बार वहां के वनवासी,आदिवासी सोलर एनर्जी से पानी पी रहे हैं और यह भी कहूंगा कि 22 गांवों की निविदा निकली थी, अभी काम पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि अधौरा, नवहट्टा, रोहतास के 70 गांव और उधर 108 गांव जल्दी से काम शुरू करवा दें ताकि वहां के लोग जो चुआड़ी का पानी पीते थे, उससे उन्हें मुक्ति मिले । आप याद दिला दिये, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, मैं इस सदन में 2005 में था, उधर सरकार थी और शकुनी चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे । माननीय नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी थे । हम पहली बार जीत कर सदन में आये थे । हुजूर, किसी

अस्पताल में रूई और सूई नहीं मिलता था और हम स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं । कम से कम यह तो चर्चा करें कि पी0एम0सी0एच0 में या अन्य जगहों पर इलाज तो हो रहा है । चेनारी या हर जगह एक-दो डाक्टर रहते हैं, ठीक बात है, डाक्टरों का अभाव हो सकता है, कमी हो सकती है । इसके लिये जिम्मेवार एक व्यक्ति या एक सरकार नहीं है । यहां 1990 में एक बार 25 हजार शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद परमानेंट शिक्षकों की बहाली और शिक्षा मित्रों की बहाली हुई । महोदय, इसके लिये जो लोग जिम्मेवार हैं, उनको भी अपने चेहरे को, अपनी व्यवस्था को दर्पण में देखना चाहिए कि हमको जब जिम्मेवारी मिली थी तो हमने क्या किया ।

महोदय, हमारे यहां कई नदियां थी, लेकिन पुल नहीं थे । दुर्गावती नदी थी, दुर्गावती जलाशय परियोजना और 386 गांव । 14 जनवरी,1976 को इसका शिलान्यास हुआ था । स्व0 जगजीवन राम, सदानन्द बाबू के समय का ही मामला होगा, उस समय स्व0 रामाश्रय बाबू मंत्री हुआ करते थे । पहली बार 386 गांव को पानी, कम हो या ज्यादा, मिल रहा है, सुखाड़ था, वहां कम से कम लोगों को राहत मिलने का काम शुरू हुआ है । इसलिये महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य में काम तो निश्चित तौर पर हुआ है, बड़ी रेखा खींची गयी है और इस रेखा का असर है कि आनेवाले समय में चाहे हम एम0एल0ए0 हो, चाहे इधर के हों या उधर को हों या सरकार किसी की भी रहे, जो साथी काम नहीं करेगा, अब जनता उन्हें बदलना शुरू कर दिया है । आज लोगों में जागरूकता आयी है कि सत्ता में वही रहेगा जो काम करेगा, उसी को मजदूरी मिलेगी वरना उसको जनता निष्कासित करने का काम कर रही है । यह बताने की बात नहीं है । हम निश्चित तौर से कहेंगे कि इस राज्य में विकास तो हो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभियान चलाना चाहिए । आज विचार मर रहा है । राज्यों में ही नहीं, गांवों, खेतों और खलिहानों में रिश्ते तार-तार हो रहे हैं और हमलोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, लोहिया, कर्पूरी के विचारों से पीछे चले गये हैं । हम सिर्फ सड़क और विकास की बात करते हैं । लेकिन विचार जबतक नहीं रहेगा, तबतक गांवों में, खेतों

में और खलिहानों में अनुशासन नहीं रहेगी, मर्यादायें नहीं रहेगी और मर्यादा और अनुशासन नहीं होने के कारण आज सारी स्थिति बिगड़ी हुई है । (क्रमशः)

टर्न-22/अंजनी/दि0 01.07.2019

श्री ललन पासवान...क्रमशः...: कोई तालाब या कुआं नहीं बचा है, जिस कुएं की बात हम कर रहे थे कि शेरशाह ने कुआं खुदवाया, सारा कुआं गांव, खेतों एवं खलिहानों में भर दिया गया। पानी का लेयर नीचे जा रहा है । मेरे यहां नोहट्टा, रोहतास में 300 फीट नीचे से पहले पानी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है । बालू खनन के सवाल पर, बालू एक तरफ कैमूर पहाड़ी और दूसरी तरफ सोन नदी बहती है । बगल के जितने भी गांव हैं, जब नदियां आती हैं, वाणसागर, रेहनडैम से जब पानी आता है तो उसके कारण सैकड़ों गांव कटाव के तट पर बसे हुए हैं । कभी अगर रफ्तार बढ़ जाय, चार लाख, तीन लाख क्यूसेक पानी आया तब हमको लगता है कि सैकड़ों गांव बह जायेंगे । आज वहां पीने के पानी का संकट है । पानी के रख-रखाव की स्थिति बहुत खराब है, अगर हम पहाड़ की नदियों को बांधे तो इसका निदान हो सकता है, इसके लिए हम सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं। पहाड़ पर कई नदियां हैं, जिसका पानी नीचे आकर गिरता है, इसके लिए वहां पर चैक डैम बने, जिससे कि पहाड़ पर पीने का पानी का लेयर बचे । सोन नदी जहां बहती है हमारे इलाके में, पहले सिंचाई हेतु लिफ्ट एरिगेशन था, उसके चलते हमारे यहां 21 पंचायत नोहट्टा, रोहतास दोनों मिलाकर और तिलौथी का 17-18 पंचायत और डेहरी का पूरा-का-पूरा इलाका सिंचाई से वंचित रह जाता है, सिर्फ बिजली पर ही आधारित है । मैं माननीय नीतीश कुमार जी, विजेन्द्र यादव जी एवं सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं । मैं जब पहली बार गया था तो हमारे यहां एक-एक लाख रूपया में ट्रांसफार्मर बिक रहा था । गांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी पैसा ले लीजिए और हमलोगों को ट्रांसफार्मर दिलवा दीजिए और आज हालत यह है कि पांच रूपया अगर कोई लेगा तो इंजीनियर सस्पेंड हो जायेगा और 12 से 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का काम होता है नोहट्टा एवं रोहतास में । वहां के लोगों का रोटी का इन्तजाम सिर्फ बिजली है । तो जो सत्य बात है, वह तो मुझे कहना ही पड़ेगा । हम सरकार से एक और आग्रह करना चाहते हैं, हम राय के रूप में, माननीय वित्त मंत्री एवं वन मंत्री सदन में बैठे हुए हैं, हमारे यहां 94 वर्ग किलोमीटर में कैमूर पहाड़ी फैला हुआ है, जिसको हम विंद पर्वत कहते हैं । विन्धवासिनी मां को जाकर स्पर्श करता है, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश को छूता है, पूरे पहाड़ में बड़ी संख्या में पेड़-पौधे काट लिये गये हैं । वहां

काफी जमीन है, सागवान के पेड़ आपके द्वारा लगाये जा रहे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर वहां पर जितनी जिम्मेवारी के साथ लगनी चाहिए, वह लग नहीं रहा है। मेरा मानना है कि सरकार वहां पर अगर फलदार वृक्ष लगाये, आम, अमरूद आदि फलदार वृक्ष लगाये और पहाड़ पर यदि नदियों को बांध दिया जाय तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा । इसपर सरकार बड़े पैमाने पर संज्ञान ले । जैसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहां गये तो अधौरा-सरहल होते अकबरपुर तक एन0एच0 टू सी को आपने जोड़ दिया 55 किलोमीटर तक, एक बड़ा उत्तराखंड, आप कहिए छत्तीसगढ़ के बाद एक बड़ा पर्यटक स्थल होगा कैमूर पहाड़ी, जहां पर रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला, गुप्ता धाम, उसको चाहे तो सरकार केदारनाथ धाम में तब्दील कर सकती है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : एक तरफ से आपने पैसा भी दिया है, इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि गुप्ता धाम को केदार धाम की तरह, माननीय वित्त मंत्री वन मंत्री भी हैं, इसलिए गुप्ता धाम केदार धाम में तब्दील हो जाय, तीनों तरफ से रोड जाये और जो अभी रोड आपने सम्मिलित किया है, वह सड़क बन जाय तो मुझको लगता है कि हम देहरादून और उत्तराखंड, हरिद्वार और केदार धाम से कमजोर स्थिति में नहीं रहेंगे । झारखंड बिहार से अलग होने के बाद देवघर के बाद गुप्ता धाम, जो भगवान शिव की नगरी है, जहां भष्मासुर को भगवान शिव ने वरदान भी दिया और श्राप भी दिया था, इसलिए उस स्थल को विकसित करने की जरूरत है । मां मुण्डेश्वरी से लेकर चार-पांच धाम जुटती है नीचे से, जिसपर स्टेट हाई-वे, माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी ने स्टेट हाई-वे का घोषणा भी किया था, इसलिए हम सरकार से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि अगर वहां फलदार वृक्ष लगे तो पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी । सखुआ, सागवान, खैर तो आप लगाइए ही , महुआ का पेड़ वहां पर पांच से दस लाख का पेड़ होगा तो उससे वहां पर सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और बिहार को विकसित करने में बड़ा सहयोग मिलेगा । सभापति महोदय जी, इसलिए हम विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि विकास के सवाल पर सारी बात एक तरफ, आज आप चमकी बुखार पर चर्चा कर रहे थे तो आपको चर्चा करना चाहिए था साकारात्मक तरीके से । सदन एक बार गंभीर होकर और माननीय प्रधानमंत्री जी से पैकेज मांगना हो तो सर्वसम्मत से तय करके पैकेज मांगना चाहिए, तो यह साकारात्मक बात हुई लेकिन आलोचनाओं से नहीं । समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने से होगा । इसलिए सभापति महोदय, विचारों की जरूरत है और विचार जबतक नहीं होगा तो पुन: हमको पुराने विचारों

पर कर्पूरी, लोहिया, अम्बेदकर, संत रविदास के विचारों पर ही इस राज्य को विकसित किया जा सकता है । लोहिया, कर्पूरी के विचार नहीं होंगे और अपनी बात साकारात्मक तरीके से रखकर बिहार को बनाने में भूमिका अगर नहीं होती है तो हम पार्टी और दलों को सिर पर धोकर इस बिहार को सर्वनाश करने का काम करेंगे । माननीय नीतीश कुमार जी, जिन विचारों की बात कह रहे हैं, जिस पर्यावरण की बात कह रहे हैं, नदियों एवं पहाड़ों की बात कह रहे है, जिस विकास की बात कह रहे हैं तो सहयोग करके बिहार को इस देश में अगली कतार में खड़ा करने की जरूरत है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह ।

श्री आनंद शंकर सिंह : सभापति महोदय, जब हम बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं तो इस सदन में बैठकर चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन यथार्थ क्या है ? आज जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत हो गयी । औरंगाबाद, गया में लू लगने से 150 से उपर व्यक्तियों की मौत हो गयी। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं लेकिन वास्तविकता यही है कि 150 से उपर लोग मरे हैं औरंगावाद में । महोदय, जब बात यह होती है कि साकारात्मक विचारों के साथ लोगों को आना चाहिए, उस समय में हम कैसे बात करें कि जब हम तीन वर्षों से लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं कि सदर अस्पताल जिसमें 57 डाक्टरों की जगह है तो वहां आठ-दस डाक्टरों से चल रहा है सदर अस्पताल और आज स्थिति यह हो गयी है कि आज के डेट में सदर अस्पताल जो कि मॉडल अस्पताल घोषित है औरंगाबाद, वहां तीन डाक्टर हैं । डी0एस0 रिटायर हो गये 30 को, तीन डाक्टरों के सहारे आपका सदर अस्पताल चल रहा है और वह भी वैसी जगह पर जहां पर 150 मौतें हुई हो तो आप कैसे समृद्ध बिहार की बात बैठकर करते हैं। क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं, जिसकी चर्चा नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरे विश्व में धूम मचाता है और वहां आपके विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है। जहां शिक्षकों की भर्त्ती नहीं हो पा रही है, बच्चों के रेशियो के अनुसार शिक्षक नहीं हैं तो क्या आप उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं ? क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं, जहां अस्पतालों में डाक्टर नहीं है ? क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं जहां पैसे लगाकर भवन तो अच्छे-अच्छे बना दिये गये लेकिन डाक्टरों की कमी के अभाव में आई0सी0यू0 तक चालू नहीं हुआ । जब लोग मरने लगते हैं, तब आप उपाय करते हैं । यह उपाय पहले क्यों नहीं होता है ? जब आप साकारात्मक विचार की बात करते हैं तो इसका उपाय पहले से होना चाहिए । जिस

तरीके से जलवायु में परिवर्त्तन हुआ है, यह विदित है कि गर्मी पड़ेगी, जिस प्रकार से वर्षा में कमी आयी है तो यह तय है कि गर्मी पड़नी है । अगर तय है कि गर्मी पड़ेगी तो प्रीकॉशन क्यों नहीं पहले लेते हैं । जब 40-50 लोग मर गये तो अस्पतालों में ए0सी0 मंगाया जा रहा है, कुलर मंगाया जा रहा है, जबकि उनके पास उतना फंड वहां उपलब्ध रहता है तो इसको कर सकते हैं पहले से लेकिन उसके बावजूद कितनी शिथिलता, बार-बार कहने के बावजूद 9वीं, 10वीं कक्षा के छात्र स्कूल जा रहे थे, स्कूल को बंद करने के लिए आग्रह भी किया गया लेकिन दो दिनों बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जब मैंने सूचना दी तो तब जाकर 9वीं, 10वीं का स्कूल बंद हुआ । लेबर क्लास के जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं लेकिन सरकार की उसपर कोई नजर नहीं है और उन मजदूरों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए देखभाल का कोई साधन उपलब्ध नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न-23/राजेश/1.7.19

श्री आनंद शंकर सिंह : ... क्रमशः... जब इतनी असंवेदनशील सरकार हो जायेगी, तो आप किस समृद्ध बिहार की बात करते हैं । महोदय, जिस प्रकार से कानून-व्यवस्था आप आये दिन सुनते होंगे, कल भी एक औरंगाबाद का लड़का की हत्या कर दी गयी है सैदपुर होस्टल के आस-पास में, किसलिए तो कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए कमीशन मांग रहे थे लोग और उसके लिए लड़के की हत्या कर दी गयी है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह की कानून-व्यवस्था बिहार में व्याप्त है । अभी आभूषण दूकान में आभूषण लूट लिया गया अभी हाल ही में, कितने व्यापारियों की हत्या कर दी गयी, बड़े-बड़े व्यापारियों की हत्या कर दी गयी, तो आप किस समृद्ध बिहार की बात करते हैं, आप ओ0डी0एस0 योजना की बात करते है, हमारे माननीय सदस्यगण, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, इतने सारे शौचालय बनाये गये, तो क्या यह बात सही नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने शौचालय बना लिया, जिन गरीबों ने शौचालय बना लिया, आज वे अपने पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं, हर तरफ लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार है, अपने निर्माण किये गये शौचालय के पैसे लेने के लिए उन्हें घूस देना पड़ रहा है, क्या यह बात सच्ची नहीं है, तो आप किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं ? महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितने लोगों को लगाया गया, चाहे वह सहायक हो या कोई हो,

हर का कमीशन बढ़ता गया, तो आज गरीब के हक में क्या आ रहा है, गरीब आज भी उसी तरीके से त्रस्त है भ्रष्टाचार में और जितनी बार वे आवास को चेक करने जाते हैं उतना बार उनका कमीशन बढ़ता है, नहीं तो नहीं जाता है पैसा उनके खाते में, यह स्थिति है, तो आप किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं, आप यहॉं पर समझ सकते हैं कि हमारा पूरा जो यह बिहार है कृषको, किसानों पर आधारित है लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार से भीषण पेयजल संकट का सामना हमलोगों को करना पड़ रहा है औरंगाबाद क्षेत्र में या और भी क्षेत्र में चाहे वह गया का क्षेत्र हो, यह पूरे बिहार की ही समस्या है लेकिन मैं अपने क्षेत्र से आपको कराना चाहता हूॅं अवगत कि स्थिति यह बनी हुई है कि पॉच-पॉच, छः-छः बार बोरिंग कराने के बाद भी वह सक्सेस होगा कि नहीं, इसमें भी आपको उपर वाले पर आश्रित रहना पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है, आहर, पैन की बात करते है, पोखर की बात करते हैं, तो क्या इसकी वास्तविकता बची हुई है जमीन पर, आहर, पैन, पोखर सब पर अतिक्रमण कर लिया गया, इनकी वास्तविकता नहीं बची हुई है, सरकार द्वारा संचालित जल संरक्षण विभाग है,अगर आप पढ़ियेगा तो ऑकड़ों में आपको समझ में आयेगा कि कितने पैन, पोखर खुदवा दिये गये,कितने जगह वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है लेकिन उसका किसको फायदा मिला, अगर यह विभाग बता दें तो हमलोगों को समझ में आता है, बार-बार क्वेशचन उठाने के बावजूद जल संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही औरंगाबाद में जितनी है, आप दिखवायेंगे तो उसी में जो काम कर रहे हैं, भाई के नाम पर, भतीजे के नाम पर, उसके रिश्तेदार के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, इसको कोई देखने वाला नहीं है, तो किस समृद्व बिहार की बात कर रहे हैं आप, मैं यह जानना चाहता हूॅं, अगर अभी भी हमलोग नहीं चेते, वाटर हार्वेस्टिंग के काम को फूल प्रूभ नहीं किया गया, तो आने वाले समय में, अभी तो भूख से मरने की बात हमलोग सुन रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुपोषण के चलते इतनी बड़ी घटना घटी, तो कुछ दिनों में सुनने को मिलेगा कि पानी के बिना लोग मरने लगे, क्या हम इसी समृद्व बिहार की बात करते हैं महोदय, जगह-जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम अगर आप सरकारी भवनों में भी करायेंगे, तब भी उतने दूर का लेयर मेनटेन रहेगा, चाहे वह बी0डी0ओ0 कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, कलेक्ट्रिएट हो, आम लोगों को भी अपने जीवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उतारना चाहिए, तब ही आपको आगे आपका भविष्य सुनिश्चित होगा, नहीं तो पेयजल के बिना स्थिति गंभीर होने वाली है, मैं आग्रह करुंगा सदन के माध्यम से कि औरंगाबाद जिले में नदियॉं है, हमारे यहॉं बटाने है, अदरी है, सब

जगह चेक डैम बना–बना करके कुछ पानी को स्टोर कीजिये ताकि वाटर लेवेल मेनटेन रह सके, जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुला है, अगर आप शाम के समय में 7, 8 बजे जायेंगे, तो आप पायेंगे कि एक परत दिखाई पड़ेगा आपको आसमान में, धूल का परत दिखाई देगा आसमान में, आस–पास रहने वाले लोगों को कुछ दिनों में आप देखियेगा, आपको सुनने को मिलेगा कि वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की बिमारियों से ग्रसित हो गये हैं, लोगों के छतों पर धूल जम जा रहा है, तो क्या आप इसी समृद्ध बिहार की बात करते हैं, आपने शहर से सटे हुए सीमेंट फैक्ट्री को बनवा दिया और वह सीमेंट फैक्ट्री यह है कि शाम में आपको धूल की परत वहाँ दिखाई देगी, जब भी आप गुजरियेगा तो स्थिति यही है, तो किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं आप, दूसरी ओर ग्रामीण टोला संर्पक योजना, जो सात निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सड़क बनने के दो महीने बाद ही उसमें दरारें खुलने लग रही है, न तो उसका फ्लैंग भड़ा जा रहा है, सरकार के अफसरों को इतना भी फुर्सत नहीं है कि वे जाकर इसको देख ले, उनको धूप दिखता है, उनको बारिश दिखता है लेकिन स्थल पर जाकर ये लोग कभी भी चेक नहीं कर सकते हैं कि सड़क वह फटी है कि नहीं फटी है, जब हमलोग सूचना देते हैं, तब इनकी निद्रा भंग होती है, तब जा करके ये चेक करते हैं और तब ठीकेदार को भेजते हैं समझाने के लिए, तो स्थिति यही है कमोवेश, न तो कहीं भी उद्घाटन का बोर्ड लगा है, न कुछ, तो क्या इसी समृद्ध बिहार की बात करते हैं आप ? महोदय, इसके अलावे जो स्वास्थ्य विभाग का पी0एच0सी0 हैं, आप राज्य के किसी भी जिले में चले जाइये, मुझे नहीं लगता है कि 10 प्रतिशत से अधिक पूरे बिहार का कहीं भी पी0एच0सी0 खुलता होगा डेली और वहाँ पर जो डाक्टर पदस्थापित होंगे, वे वहाँ पर बैठते होंगे, इस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे डाक्टर हैं, जो सक्षम हैं, अच्छे हैं लेकिन पी0एच0सी0 में अपना तबादला कराकर अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ। महोदय, अभी भी सरकार को इसमें चेतने की आवश्यकता है, नहीं तो डाक्टरों की कमी का अभाव तो हमलोग झेल ही रहे हैं लेकिन जो डाक्टर हैं भी, वे भी निजी प्रैक्टिस में ही लगे हुए हैं और अपना माल बनाने में लगे हुए हैं, आम जनता से उनका कुछ भी लेना देना नहीं हैं, तो इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । महोदय, हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सड़कों की स्थिति सुधरी है, तो इसमें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हीं के समय में आपको

सड़कों का जाल मिला और इसी को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी पीठ जब आप थपथपाये, तो दूसरे लोगों को भी शाबाशी देना चाहिए, यही है स्वस्थ परंपरा, यही मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम जब नाम लें अपनी सरकार का, तो पिछली सरकार ने भी जो काम किये हैं, उसको भी तो कम से कम याद कर लिया कीजिये, यही मेरा कहना है । महोदय, इसके अलावे किसानों की सिंचाई की बात औरंगाबाद प्रखंड, देव प्रखंड, मदनपुर प्रखंड, रफीगंज प्रखंड इसके अलावे अगल बगल जो हमारे और प्रखंड है, जैसे आमस या और भी हैं, वहाँ आज भी सिंचाई के अभाव में किसानों की स्थिति दयनीय है और गया में आकर प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा कि अगले बार जब मैं आऊंगा तो किसानों के खेतों में पीला पानी होगा और वे दूसरी बार भी आ गये लेकिन आज तक किसानों के खेतों में पीला पानी नहीं पहुंचा और वे उद्घाटन भी करके चले गये और आज तक हमलोगों का जो कुटकुट डैम है, मंडल डैम है, उसका निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ और जब तक वह काम शुरु नहीं होगा, तब तक औरंगाबाद के आस-पास के सभी प्रखंडों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पायेगी, भूगर्भीय जल का जो स्तर है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके द्वारा जो कृषि वाला लग रहा है ट्रान्सफर्मर वगैरह वह तो लग रहा है लेकिन जब जल ही नहीं रहेगा, तो आप ट्रान्सफर्मर लगाकर क्या कर लेंगे, जब भूगर्भीय जल ही आपका नीचे चला गया है,वह इतना नीचे चला गया है और जब पानी मिल ही नहीं रहा है, तो हम ट्रान्सफर्मर लगा कर भी क्या कर लेंगे, मैं सदन के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मंडल डैम का निर्माण कराया जाय, तब जाकर औरंगाबाद के आस-पास के किसानों को राहत मिलेगी, किसानों के लिए यह जो प्रदेश जाना जाता है, खेती के लिए यह प्रदेश जो जाना जाता है, उनको राहत मिलेगी, तब मैं समझूंगा कि हाँ हम समृद्व बिहार की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं, नहीं तो सारी ये बातें जिनपर अभी चर्चा हो रही है, सदन में तो यह चर्चा अच्छी लगती है लेकिन धरातल पर ये सारी योजनाएँ विफल हैं । महोदय, मैं इन्हीं सब बातों को आज सदन में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । धन्यवाद ।

टर्न-24/सत्येन्द्र/1-7-19

श्री समीर कुमार महासेठ: सभापति महोदय, सामान्य विमर्श पर भाग लेने के लिए तथा सदन में बोलने के लिए जो समय दिया गया उसके लिए मैं अपने दल तथा आसन को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, इस सदन में मेरा पहला कार्यकाल है परन्तु इतने ही दिनों में मुझे यह अनुभव हुआ कि विषयवस्तु से बाहर जाकर यहां हमलोग सारे

लोग बोलते हैं । सत्ता पक्ष के लोग हमेशा 2005 का और 15 वर्षों की चर्चा करते रहते हैं । हमलोग की तरफ से जब वक्ता खड़े होते हैं तो विपक्ष हमेशा जो एक ओपोजिशन का आंख होता है, उसको सही मायने में दूसरे ढंग से लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए । बीच में ज्यादा टोका टोकी शुरू कर देते हैं और हमलोगों को इतना अवसर नहीं देते हैं कि तथ्यों के आधार पर सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कर सकें और यही कारण कि हमलोग विषयवस्तु से भी भटक जाते हैं । आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्तव्य में विषयवस्तु तक ही सीमित रहूं और राज्य में जो घटनाएं हो रही है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करूं । सभापति महोदय, विषयवस्तु और आज जो मुजफ्फरपुर की घटना है-चमकी बुखार से बिहार में बच्चों की हृदयविदारक मौत । महोदय, मुजफ्फरपुर में पिछले 10 वर्षों से चमकी बुखार के बारे में लगातार हरेक वर्ष ये बढ़ता चला गया और उनकी मौतों का कारण क्या बना, ये बच्चे कौन हैं, किस क्षेत्र से आते हैं अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि ये बच्चे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं और कहीं न कहीं निम्नतर जीवन स्तर पर जीवनयापन करने वाले जो लोगों के बच्चे हैं, ऐसी भीषण गर्मी में जहां ए0सी0, पंखा, कुलर की आवश्यकता बहुत लोगों को है लेकिन यहां जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे लोग ज्यादा उसमें विश्वास करते हैं लेकिन वैसे बच्चों को शायद यह नसीब नहीं है इसलिए सबसे ज्यादा वही आज के दिन में कहीं न कहीं होस्पीटल में पड़े हुए हैं । इन बच्चों को गर्मी से बचाने के साथ साथ आपने 10 वर्षों में उनके के लिए क्या किया, यह शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है । महोदय, हमलोग बच्चों की मौत पर दुखी है लेकिन लोक सभा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया और सरकार की विफलता को स्वीकार किया लेकिन राज्य सरकार अपनी विफलता नहीं मान रही है और यहां लोग अच्छे कामों का ढिंढोरा पीट पीट कर के कह रहे हैं तो इनके द्वारा जो गलत कार्य हुए हैं जिनको आज हम कहते हैं आजादी के बाद से लेकर आजतक लगातार 10 वर्षों में जो बच्चों को मौत हुई इस बीमारी से, इसका कारण अभी तक ये कुछ भी पता नहीं लगा पाये हैं साथ ही अगर 500 बच्चे 10 साल में मरे हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर में तो 5 हजार बच्चे 10 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक विकलांगता के शिकार हुए हैं, दिव्यांगता के शिकार हुए हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, जो बच्चे बच भी जाते हैं कुछ न कुछ प्रतिशत उसमें कमियां रह जाती हैं जो कमियां को किसी ने उद्धृत करने का काम नहीं किया और सरकार भी उन चीजों को अपने वक्तव्य में नहीं रखने का काम किया । मैं जानना चाहता हूं कि लगातार इन चीजों की चर्चा होती रही लेकिन सरकार के द्वारा इन बातों की चर्चा

नहीं हुई । माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चार लाख मरने वाले को देते हैं तो शायद वह विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को अगर दो लाख रू0 देने का एनाउंस करते दिव्यांगता में तो हम समझते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर कुछ करना चाहती है। वैसे गरीब बच्चा जो 80 प्रतिशत तक विकलांग हो गया, उसकी बीमारी को कौन देखेगा, उसको कौन सेवा करेगा ? आज वह एक परिवार पर बोझ हो गया है और पूरे बिहार में जहां जहां ये बीमारी हैं, कहीं न कहीं शुरू से हम देख रहे हैं उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि विशेष परिस्थिति में वैसे बच्चे, वैसे परिवार के बारे में आप सोचें अगर नहीं सोचते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जहां बिहार सेकेंड में आ गया है पूरे देश में विकलांगता में, कहीं न कहीं प्रदूषण, कहीं न कहीं इंडस्ट्रीयल प्रोब्बलम जो भी प्रोब्लम है, किसी चीज का एकाएक शुरूआत नहीं होता है, कई सालों के बाद एक विकृति होती है जिस विकृति के बाद हमारे बच्चे इसके शिकार होते हैं। मेरा मानना है कि जब आप ढिंढोरा पीट रहे हैं तो अपनी विफलताओं को भी आप स्वीकार करें और ये केवल प्रधानमंत्री जी की विफलता नहीं है जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की भूमिका होती है यह उसकी विफलता है । महोदय, 10 वर्षों से यह बीमारी पैर पसार रही थी तो अभी तक किस साल कहां पर, क्या रोकथाम किया गया सरकार के द्वारा, क्या इस पर किसी प्रेस प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा हुई और उस चर्चा में हमलोगों तक बात आयी, अगर कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ होता तो शायद विधान मंडल में विधान सभा, विधान परिषद के लोगों को प्रकाशित पुस्तक मिला होता । महोदय, वर्ष 2014 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर आये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इसके लिए विशेष अस्पताल बनाया जायेगा लेकिन पांच वर्ष में कुछ नहीं हुआ फिर 2019 में पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां आये और 10 वर्षों की अवधि में जो पुराना उनका था वही पुनः उन्होंने उसी बात को दोहराये । महोदय, 10 वर्षों की अवधि में सरकार प्रभावित क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जो उस क्षेत्र के बच्चे हैं, वे कहां कहां के पूरे बिहार में किन किन क्षेत्रों के थे, उन क्षेत्रों को अगर केन्द्र बिन्दु बनाकर के जो गांव प्रभावित थे उस पर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था होती तो मैं समझता हूँ कि यह नौबत नहीं आती साथ ही मैं कहना चाहता हूँ सरकारी अस्पतालों में ....

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री: माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यह 70 साल की विफलता है।

श्री समीर कुमार महासेठ: माननीय मंत्री जी, ये 10 साल में आप आकलन कर लें कि कितने परिवार ऐसे हैं और उसी के प्रति आप ज्यादा सोचें और उसी के प्रति आपका

डिपार्टमेंट जो है शोषण दोहन कर रहा है पानी का, इससे आगे 50 वर्षों तक पानी नहीं रहेगा और आप क्या कर पाईयेगा जो आपकी प्लानिंग है वह सही उतर नहीं रहा है, कहीं धरातल पर आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं और अगल बगल उससे को-रिलेटेड प्रोब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होगा? एक बार आप उसे प्री-प्लानिंग में ले लिया लेकिन उस सात निश्चय का क्या आपका साईड इफेक्ट होगा, आपके पास उसका कोई प्लानिंग नहीं है। अभी आनंद जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि आप अगर एक मकान के सरकारी मकान के चारों तरफ का ही पानी संरक्षण का अगर आप निर्णय कर लें तो कई वर्षों तक पानी का कमी नहीं होगा। यहां माननीय नगर विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे जो पूर्व नगर विकास मंत्री थे यहीं पर जो अभी सोते हुए पाये गये, नाम लेना उचित नहीं है पहले वह बिहार में नगर विकास मंत्री थे तो हमेशा कहते थे कि बिहार को सिंगापुर बना देंगे, पता नहीं सिंगापुर तो नहीं बना, मैनचेस्टर बनायेंगे और अभी जब वे मुजफ्फरपुर गये तो प्रेस के सामने सोते हुए पाये गये, पता नहीं क्या कारण है वह अपना बतलायेंगे लेकिन मेरा मानना है माननीय मंत्री जी, मैं विशेष परिस्थिति में कहना चाहूंगा कि अति सुधार की आवश्यकता है , चाहे हम हों या चाहे आप हों, आप मंथन करें सोचें कि कैसे विपक्ष से आपको क्या लेना है । यह आपकी प्री-प्लानिंग होनी चाहिए लेकिन आजतक शायद विपक्ष को आप कभी प्री-प्लानिंग में साथ नहीं लिया है। मेरा मानना है कि चूंकि कहीं न कहीं समय का अभाव है। हम अपने क्षेत्र की ओर कहना चाहूंगा और साथ ही पूरे बिहारवासी के लिए कि जो बिजली का मीटर होता है उसका चार्ज लिया जा रहा है । महोदय, जब टॉल टैक्स में रोड का खर्च पूरा समाप्त हो जाता है तो टॉल टैक्स समाप्त कर दिया जाता है लेकिन पूरे बिहार में बिजली मीटर के नाम पर, यह 50 वर्ष से हम देख रहे हैं, सैंकड़ों टाईम्स टैक्स लिया जाता है, एक बार पूरा पैसा समाप्त हो जाय तो बिजली मीटर से कम से कम वूसली बंद हो । महोदय, जहां तक पंचायती राज की बात है, 143 नगर निकाय और सारा चीज आप देख रहें होंगे, सभी जगह हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है हर दो साल पर, आप कहीं चले जाईए, कोई निगम हो, कहीं पर नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो 2-2 साल पर यह सब हो रहा है। लोग क्या विकास करेंगे, आज लोग लगे हुए हैं मेयर बनने के लिए और चेयरमैन बनने के लिए और हटाने पर, मुजफ्फरपुर उससे कोई छुटा हुआ नहीं है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि एक सही नियमावली बनाईए, ऐक्ट में परिवर्तन करिये, स्टाफ का नियमावली बनाईए। नये नये निगम में आपने एक्सक्यूटिव औफिसर को दिया है लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि क्या काम करना है ।

नगर निगम तक तो आई0एस0एस0 होता है, उसके नीचे जाकर देखें, किसी एक्सक्यूटिव औफिसर को कोई पावर नहीं है कि सही मायने में काम कर सके तो उनकी भी नियमावली बननी चाहिए, स्टाफ की भी नियमावली बननी चाहिए तब जाकर के इसमें सुधार हो सकेगा। शहर से सबसे ज्यादा आपलोग आते हैं, आपलोग अपने बारे में ज्यादा सोचें ताकि अगली बार कम से कम यह कह सकते हैं और साथ ही मधुबनी पेंटिंग का जितना विकास हुआ, माननीय उद्योग मंत्री यहां सामने बैठे हुए हैं, हस्तकरघा और हमारी हैंडलूम मधुबनी खादी उस पर ध्यान देकर के पुनः मधुबनी को स्थापित करने का और पूरे देश में मधुबनी को स्थापित करने का प्रयास करें । बहुत बहुत धन्यवाद।

टर्न-25/मधुप/01.07.19

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज 2019-20 बजट के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसपर मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, यह बिहार जो वर्त्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार का, आदरणीय सुशील कुमार मोदी का बिहार है, यह देश जो वर्त्तमान में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का देश है, सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है । काफी देर से सदन में चर्चाएँ हो रही हैं, कई प्रकार की बातें पक्ष-विपक्ष की आ रही हैं, सड़कों की चर्चा हो रही है । जी0टी0एस0एन0वाई0 के माध्यम से सड़कें बनी हों, एम0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से सड़कें बनी हों, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी हों लेकिन आज कम से कम सभी गाँव-टोलों तक सड़कों से सम्पर्क हुआ है और एक समय था, बहुत पहले का समय नहीं था, 12-14 साल पहले का समय था कि कई टोले ऐसे थे, कई बसावट ऐसे थे, कई गाँव ऐसे थे जहाँ से लोगों को बीमार पड़ने के बाद खाट पर अपने परिवार के लोगों को लादकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता था, सड़कों के अभाव में उसके दरवाजे तक गाड़ियाँ नहीं जाती थीं, सड़क नहीं होने से उचित साधन और उचित सवारी उसके दरवाजे और टोले तक नहीं पहुँचती थी, आज वह दिन समाप्त हो गया जब लोग खाट पर अपने मरीज को लादकर एक टोले से दूसरे गाँव तक ले जाते थे या अस्पताल तक ले जाते थे । इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा ।

महोदय, स्वास्थ्य की बात हो रही है, आज तो आदमी का इलाज हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जानवरों का भी इलाज हो रहा है लेकिन एक समय था कि स्वास्थ्य विभाग में सरकारी हॉस्पीटल में, सदर हॉस्पीटल में, पी0एम0सी0एच0 में, एन0एम0सी0एच0 में, आई0जी0आई0एम0एस0 जैसे हॉस्पीटल में भी पशु और आवारा जानवर दिखाई पड़ते थे, आदमी के इलाज की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय आदमी का इलाज भी नहीं होता था आज तो आदमी के इलाज के साथ-साथ पशु का भी इलाज हो रहा है, जानवर का भी इलाज हो रहा है, उनको उचित समय पर टीका भी मिल रहा है । कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, इन परिस्थितियों को सलटने के लिए, समझने के लिए, इससे निजात पाने के लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयासरत है और बिहार की सरकार जो पूरे भारत के साथ-साथ दुनिया में अपना एक मानक स्थापित कर रही है विकास के रूप में, विकास के प्रगति को स्थापित कर रही है, निश्चित रूप से ऐसा जो भी विषय सरकार के सामने आता है, सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उस विषय को, उस व्यवस्था को ठीक करके उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जिस प्रकार से प्रयासरत है, अगर कोई नया विषय आ जाता है तो उसको भी सरकार ठीक करेगी ।

महोदय, आज किसान की बात हो रही है, आज किसान के खेतों में पानी पहुँचाने के लिए बिजली का कितना बड़ा सहयोग है । एक समय था जब कम्पलीट ढिबरी युग था या लालटेन युग था । हमारे लालटेन के साथ वाले भाई-मित्रगण सभी सदन में बैठे हुए हैं, ये क्या इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं कि भले लालटेन के साथ हैं लेकिन ये लोग अपने घरों में नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार-सुशील मोदी की बिजली जला रहे हैं ? इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह लालटेन का युग नहीं है, ढिबरी का युग नहीं है । हम सब लोग जब गाँव में जाते हैं, गरीब की बस्तियों में जाते हैं, गरीब के घरों में जाते हैं, गर्मी का समय है, तापमान बढ़ा हुआ है, कहीं गरीब के परिवार में जाते हैं, जब उसके घर में बैठते हैं जहाँ पंखा चलता रहता है, उससे पूछते हैं कि तुम अपने शर्ट को, पैंट को बाहर क्यों नहीं सुखा रहे हो, यह पंखे के नीचे जो सुखा रहे हो तो वह कहता है कि नेता जी, विधायक जी, बाहर इस कपड़े को पसारेंगे तो इसका कलर खराब हो जायेगा इसलिये पंखे के नीचे इसको सुखा रहे हैं। आज गरीब में परिवर्तन हुआ है । बिजली में परिवर्तन हुआ

है, जहाँ 24 घंटे में 22-23 घंटे, 24-24 घंटे बिजली रह रही है, एक-एक झोपड़ियों तक बिजली पहुँची है, सबलोग इस गर्मी में भी पंखे की हवा से निजात पा रहे हैं, उनको रोशनी मिल रही है और ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि पहले हमलोग जब गाँव में जाते थे लोग अपना टिना और कार्ड लेकर आ जाते थे कि छः महीना हो गया, डीलर तेल नहीं दे रहा है, आज हमलोग किसी को नहीं देखते हैं, गाँव का बाजार हो या शहर का बाजार हो जो बोतल में रस्सी बाँधकर मटिया तेल के लिए उस बाजार में जाता हो और किसी से मटिया तेल का डिमांड करता हो । आज बिजली की प्रगति है । आज बिजली हमारे खेतों तक पहुँच रही है, खेतों में पानी की आवश्यकता है, जिस डीजल पम्पसेट के माध्यम से 150 रू0 घंटे हम पानी का पटवन कराते थे, आज बिजली की प्रगति होने से पानी का वह पटवन 5-7 रू0 घंटा का हो रहा है और लगातार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बाजप्ता विज्ञापन निकाल कर कह रहे हैं कि खेतों तक बिजली प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग में आप आवेदन कीजिए ताकि आपके खेतों तक बिजली का लाईन पहुँचा दिया जाय, पोल गाड़ दिया जाय, आप अपना नीचे पम्प लगाइयेगा और अपने खेत तक पानी पहुँचाइयेगा । लगातार इसका विज्ञापन निकल रहा है ।

महोदय, आज सभी क्षेत्रों में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है । निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो पहले का बिहार था सैकड़ों साल पूर्व का बिहार था, चाणक्य, चन्द्रगुप्त मौर्य का बिहार था, निश्चित रूप से उनकी नीतियों के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा ।

महोदय, आज भारत की सरकार ने किसान निधि सम्मान योजना दिया है, आज हर किसान को 6 हजार रू0 की राशि साल में तीन बार 2-2 हजार रू0 करके जानी है और पिछले ही बजट से 2 हजार रू0 आना शुरू हो गया है और बिहार की सरकार ने खेतों के बँटवारे के लिए पारिवारिक बँटवारा के लिए, जिस बँटवारे के लिए हम 10 साल - 20 साल मजिस्ट्रेट के यहाँ दौड़ते थे, जज के यहाँ जाते थे, आज 100 रू0 के स्टाम्प पर उस बँटवारा को क्लीयर किया है और कहा है रजिस्ट्रार को कि 100 रू0 के स्टाम्प पर अगर कोई अपना पारिवारिक जमीन का बँटवारा करके आपके यहाँ लाता है तो आप उसको रजिस्टर्ड करिये और सी0ओ0 के यहाँ भेजिये, सी0ओ0 के यहाँ उसका दाखिल-खारिज होगा, सी0ओ0 के यहाँ उसका म्यूटेशन होगा और उसके नाम

पर जमीन चली जायेगी । आज बिहार के कई किसान हमलोगों के क्षेत्र के किसान पारिवारिक बॅटवारा करके अपना किसान कोड खोलवा रहे हैं, अपना भी खोलवा रहे हैं, अपने पत्नी का भी खोलवा रहे हैं, अपने बाल-बच्चे का भी खोलवा रहे हैं पारिवारिक बॅटवारा करके और किसान सम्मान निधि का लाभ खुद भी प्राप्त कर रहे हैं और परिवार के अन्य लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त हो रहा है । हम आगे नहीं बढ़ें, कुछ करें नहीं, सिर्फ सरकार पर दोष लगाते रहें कि सरकार यह नहीं कर रही है, सरकार वह नहीं कर रही है तो इससे काम नहीं चलेगा । सरकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है ।

महोदय, मैं पूर्वी चम्पारण जिला से आता हूॅं, मैं अपने कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद और बधाई इसलिए देता हूॅं कि आज मुझे इस सदन में बोलने का अवसर हमारे यहॉं की महान जनता ने दिया है । आप चलिये मेरे यहॉं देखिये, आप गाय-भैंस का बढ़ोतरी देखिये, मदर डेयरी का प्लांट वहॉं लगा है । आज सैकड़ों किसान अपना दूध बेचकर खुशहाल है, खुशहाली की जिन्दगी जी रहे हैं । शायद कोई परिवार मिलेगा, गॉंव में चलियेगा जहॉं कोई न कोई गाय-भैंस उसके दरवाजे पर 10 लिटर - 20 लिटर दूध देने वाला नहीं हो । हमको करना पड़ेगा महोदय, हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ।

महोदय, प्रकृति कुछ मामलों में हमारा साथ नहीं दे रही है । हम भी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नैसर्गिक वस्तुओं का हम एक तरह से क्षरण कर रहे हैं, एक तरह से उसका अपहरण कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । यह बिजली बढ़ी है, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूॅं अपने आदरणीय नेतृत्व को, सदन में बैठे हुये अपने नेता को कि बिजली बढ़ी है, गॉंव-गॉंव में बिजली चली गई है लेकिन यह मानक भी तय होना चाहिए कि कितने लोगों के घर में ए0सी0 लगेगा, कितने लोगों के घर में कूलर चलेगा । आज जितना ढंडा हमें प्राप्त हो रहा है कूलर और ए0सी0 लगाकर उससे ज्यादा गर्मी हम पर्यावरण में फैला रहे हैं । उसके चलते भी हमको परेशानियॉं हो रही हैं । हमारे आदरणीय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी सदन में बैठे हुये हैं, ये वन विभाग के भी मंत्री हैं, मैं एक सुझाव देना चाहूॅंगा कि जो पेड़ लगाये जा रहे हैं उसमें ऐसे भी पेड़ लगाये जायं जो पेड़ हमको अधिक छाया दे सकें । पहले हमारे पूर्वज और हमलोग भी बच्चे थे तो पीपल, बरगद, नीम आदि का अधिकाधिक पेड़ लगाते थे, ये पेड़ अधिक छाया भी देते थे और इसमें से कई पेड़ ऐसे हैं जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं ।

आज हम जाते हैं किसी पेड़ बेचने वाले के दुकान पर, किसी फलदार पेड़ की आप चर्चा करते हैं और उसको कहते हैं कि छः महीने के अन्दर जो फलने वाला पेड़ है, वह पेड़ हमको दे दीजिए, जिस पेड़ की आयु 100 साल - 150 साल - 200 साल है जो अधिक से अधिक छाया देता है और अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी देता है, वैसे पेड़ की तरफ भी हमको आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, अभी चमकी बुखार की चर्चा हो रही है, यह तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा ही है, डॉक्टर इसपर शोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका निदान निकलेगा लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो आया है, किसानों के साथ जो आया है उसका भी निराकरण और निदान के लिए सरकार को कोई न कोई इसके लिए भी अपनी नीति और सुझाव देना चाहिए । दूसरा पहलू है कि लीची पर चर्चा हो रही है कि लीची खाने से चमकी बुखार की बढ़ोतरी हो रही है । जितने लीची उत्पादक हमारे किसान हैं और हमलोग जहॉ से आते हैं, वह इलाका भी लीची उत्पादन का है । ...क्रमशः...

टर्न-26/आजाद/01.07.2019

...... क्रमशः ....

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, महेशी का जो इलाका है, वह लीची उत्पादन का इलाका है और इस बार जो चमकी बुखार में लीची खाने की चर्चा शुरू हुई, इससे हमारे हजारों किसानों के खेत में लीची पड़े रह गये और उनका लीची बीका नहीं और वे आज दयनीय स्थिति में आ गये हैं और उनको आगे भी संशय है कि जिस प्रकार से लीची की चर्चा हुई है, लीची खाने से चमकी बुखार हो जाता है तो आगे भी हमारा लीची नहीं बिकेगा और लीची भी कोई नहीं खा पायेगा इसलिए सरकार को इसके बारे में बात स्पष्ट करनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि इस लीची पर जो दोष लगे हुए हैं, लीची पर जो धब्बा लगा हुआ है, उसपर जो दाग लगा हुआ है, उसपर कोई न कोई संशोधन करके सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए या विज्ञापन निकालना चाहिए ताकि लीची पर किसान जो आज संशय की स्थिति में है कि हम आगे जो लीची का उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन का क्या होगा, इस संशय की जो स्थिति है, उससे उनको निजात मिलना चाहिए ।

महोदय, सभी क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ी है, शौचालय की चर्चा हो रही थी । महोदय, एक समय था, जब हम अपने गाड़ियों से सड़कों पर निकलते थे तो हमलोग बेटी-बहुओं को सड़क पर देखकर के हमारा सर शर्म से झुक जाता था । आज तो सिर्फ उसके भुगतान की बात हो रही है । मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि निश्चित रूप से इसके भुगतान में प्रगति होनी चाहिए, जिन लोगों ने शौचालय बनाया है, उनके पैसा समय पर मिलना चाहिए । लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है, हमारी जो माँ-बहने हैं, जो गरीब परिवार की हैं, जो घर में जाकर के अपने इज्जत की रक्षा कर रही है, उसके लिए भी नरेन्द्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी एवं सुशील कुमार मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे गरीब माँ-बहनों की आज रक्षा हो रही है । एक समय था महोदय, जब हमलोग सड़क पर चलते थे तो हमारा सर शर्म से झुक जाता था ।

महोदय, हमारी सरकार अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है । पहले जहां मछली कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु का खाते थे लेकिन हम मछली उत्पादन में आज आगे बढ़े हैं । सरकार मछली उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे रही है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने दिव्यांगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया है । आज डेढ़ लाख रू0 का मोटरसाईकिल जिनका आँख ठीक है, माथा ठीक है, हाथ ठीक है, उनको प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना के तहत मोटरसाईकिल प्राप्त हो रहा है । जो मछुआरे मछली का उत्पादन करते थे, आज उनको मछली बेचने के लिए मोटरसाईकिल पर आईसबॉक्स सहित 40हजार रू0 छूट देकर के उनको मोटरसाईकिल दिया जा रहा है । जो छोट व्यापारी हैं, उनको फ्री में साईकिल दिया जा रहा है और मछुआ सोसाईटी के एक सदस्य उसके सेक्रेटरी या उनको जो पदाधिकारी हैं, उनको मछली को इस बाजार से उस बाजार तक पहुँचाने के लिए फ्री में 7 लाख रू0 की गाड़ी दी जा रही है । अब सरकार की कई प्रकार की योजनायें हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोग उन योजनाओं का कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इसमें हमारी भी कमी है, हमको उन योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करके इन योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी नीचे तक को देना चाहिए । महोदय, मैं एक और आग्रह करूँगा आपके माध्यम से सरकार से और मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नगर क्षेत्र में नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर निकाय है और वहां नगर क्षेत्रों में पोल पर नगर निगम, नगर निकाय या नगर पंचायत के तरफ से बड़े-बड़े एल0ई0डी0 लगाये जाते हैं, रोशनी होती है । गांव में भी हमारे आदरणीय श्रवण बाबू बैठे हुए हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, गांवों में भी पंचायतों को यह

अधिकार मिलना चाहिए । गांव में भी पंचायतों को यह अधिकार मिले, पंचायत में भी जहां गांवों में घना आबादी है, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, उस जगह पर वहां के पोल पर एल0ई0डी0 लाईट लगाना चाहिए, सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां भी 24 घंटों रोशनी रहे, ऐसा मेरा सरकार को सुझाव है ।

महोदय, जल संचय की बात हो रही है । निश्चित रूप से जल संचय पर जोर देना चाहिए । गांवा में बहुत सारे कुँअे हैं, जो अभी ठीक-ठाक की स्थिति में है, सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए । मनरेगा योजना हो या जो भी योजना हो, इसमें सरकार सहयोग करे, जिससे हमारे पुराने ट्यूबवेल भी चालू हो सकते हैं । जिस कुँअे से हमलोग कभी पानी निकाल कर पीने का काम करते थे, कभी पिलाने का काम करते थे और जिस कुँअे पर बाल्टी में पानी हमलोग 24 घंटे रखते थे, जिससे पशु-पक्षियों को भी पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहां आकर पानी पीते थे और पशु-पक्षी और जानवर पानी पीकर संतुष्ट होते थे, इसलिए आज कुँओं को भी चालू करना चाहिए । जिस प्रकार से जो नहर है, आहर है, पईन है, पोखर है, जल संचय पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भी जोर दे रही है । मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस काम को कर रहे हैं, जहां इस काम में और तेजी आनी चाहिए और जल संचय के लिए आपको सम्पूर्ण प्रयास करनी चाहिए ।

आप सभी पंचायतों में आर0टी0पी0टी0एस0 का काऊंटर खुल रहा है । ब्लॉक में एक आर0टी0पी0टी0एस0 के काऊंटर पर पूर ब्लॉक के लोग जाते थे, सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक जाकर रहते थे । आज सभी पंचायतों में आर0टी0पी0टी0एस0 का काऊंटर खुल गया है या खुल रहा है और लोग कम संख्या में पंचायत के आर0टी0पी0टी0एस0 के काऊंटर पर जा रहे हैं और वहां अपना काम सुविधा से करा रहे हैं । किसी भी प्रकार का ऑनलाईन आवेदन करना है तो लोग कर रहे हैं । भारत सरकार बिहार सरकार से मिलकर कई गांवों को जो बड़ी गांवे हैं, 5हजार की आबादी से ज्यादा की जो गांवे हैं, उसको डिजिटल ग्राम बनाया जा रहा है । मैं डिटिजल ग्राम के बारे में अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ । मेरे क्षेत्र कल्याणपुर विधान सभा में मेरा पंचायत है मच्छरगामा, जो डिजिटल ग्राम बना है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : बस दो मिनट में सर । उस गांव के लोग आज उस डिजिटल सेवा के माध्यम से उस गांव में बैठकर के डिजिटल सेवा के माध्यम से दिल्ली एम्स में लाईन लगा रहे हैं और डॉक्टर से विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से सलाह ले रहे

हैं। दिल्ली जाकर के जो लोग 10 दिन, 20 दिन बैठते थे, नम्बर लगाते थे, आज उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ रही है । जब डॉक्टर उनको नम्बर एलॉट करता है तब यहां से उनको जाना पड़ता है या साधारण कोई मामला होता है तो विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उनको सलाह मिल जाती है और इससे उनका काम चल जाता है ।

हर क्षेत्र में बिहार सरकार प्रोग्रेस कर रही है और अधिक प्रोग्रेस करने की जरूरत है । जो कुछ सुझाव हमने दिये हैं, मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से श्री सुशील कुमार मोदी जी से, श्री श्रवण कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आप इस सुझाव पर भी अमल करेंगे । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सदन ने मेरी बात को सुना, मैं आपके प्रति, सम्पूर्ण सदन के प्रति और अपने क्षेत्र के जनता के प्रति साधुवाद, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : धन्यवाद सभापति महोदय । सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे । जब सदन में बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के खिलाफ विरोध में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं । सभापति महोदय, विरोध में बोलने के लिए यों ही खड़े नहीं हुए हैं, बजट में जब विजन और डायरेक्शन का अभाव परिलक्षित हो तो स्वाभाविक रूप से हम इसको रूटीन बजट कहते हैं । क्यों कहते हैं, हम बिन्दुवार तरीके से सभी बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे । बजट का आकार तो हम पेश कर देते हैं लेकिन एक बात सबसे बड़ी हमारी जेहन में आयी जिसपर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है । यह बड़ी सार्थक चिन्ता है, यह चिन्ता है जलवायु परिवर्तन के प्रति सभी लोगों का, जल संचय के प्रति सभी लोगों का, चाहे वह पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि बढ़ते खतरे सभी के लिए यह चिन्ता का विषय है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

चिन्ता का जो विषय है, उसका निराकरण कैसे हो, इसपर निर्मूलता कैसे आये, इसपर स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम इसलिए कह रहे हैं महोदय डायरेक्शन और विजनलेस की बात, इसके अभाव की बात मैंने इसलिए कहा, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि यह रूटीन बजट है। आप देखिए कि जो सरकार के बजट का आवरण है, इसका मुख्य जो है मैं मानता

हूँ शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तो आवरण और यथार्थ दोनों पर चर्चा होगी । आवरण को यदि हम देखकर के चर्चा करते हैं तो उसके यथार्थ की ओर देखना होगा । इसलिए कहीं न कहीं हमको वहां पर ले जाने की जरूरत है । इसलिए ले जाने की जरूरत है कि हम बजट का आकार क्यों बनाते हैं ? बजट का आकार हम बनाते हैं सर्वांगिण विकास के लक्ष्य को निर्धारण करके और वह विकास की जो योजना होती है, उसमें सार्वभौमिकता की भाव होनी चाहिए ताकि जो निचले पैदान के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो खासकर के चाहे वे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले लोग हो, बहुलता किसी की हो गरीबी का, जब तक हम उसको ध्यान में रखकर के बजट का आकार हम नहीं बनाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसपर सवाल खड़े होते हैं । आवरण की चर्चा और यथार्थ की चर्चा हमने इसलिए किया कि आवरण मुख्य रूप से सरकार के बजट का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा है । अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा राज्य का बेहतर है तो आपका कहीं न कहीं आपकी चारों तरफ चर्चायें होंगी । ये तीन मुख्य विषय हमारे समझ से दिखता है । बाकी चीजें होती हैं, बनती है और बिगड़ती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत सारी चीजें कर जाते हैं । लेकिन जब तक हम अपने राज्य का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को मजबूत नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम पर सवाल खड़े हो जाते हैं ।

..... क्रमशः ......

टर्न-27/शंभु/01.07.19

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : क्रमशः..तो सवाल खड़ा न हो इसपर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है । हम इसलिए नहीं कहे कि डायरेक्शन और विजन का अभाव है । हम यूं ही कोई मुखालफत के लिए बात नहीं कह रहे हैं बल्कि हम सरकार को रचनात्मक सहयोग के लिए खड़ा है और यहां भी लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का अंग होता है और यह वाणी वहां लिखी जाती है जहां सरकार बैठती है ट्रेजरी बेंच के तरफ । यहां आपोजिशन के बेंच के तरफ नहीं लिखी जाती है ताकि बार-बार सरकार के ध्यान में रहे कि प्रतिपक्ष कहीं न कहीं सरकार का अंग है । यह अंग ऐसा अंग है जो आपको हमेशा सच्चाई का दर्शन कराता हो, रू-ब-रू होते रहता है । हमारे कई वक्ता आदरणीय ललन पासवान जी, मिथिलेश तिवारी जी ने कई बात कही अब कोट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन न कहें तो भी अच्छा नहीं

लगता दोनों बातें हैं। उन्होंने लोहिया जी से लेकर जयप्रकाश जी तक सब तरह की चर्चा कर दी- यह सत्य है कि राज्य में कई परिवर्तन हुए, किन्हीं की नाकामियों का और उनके द्वारा किये गये कार्यों को भी नकार नहीं सकते हैं दोनों चीजें साथ है । जिस तरह से लोकतंत्र जीवन में सुख-दुख साथ चलता है तो लोकतंत्र में ताली और गाली दोनों साथ चलता है इस बात को स्वीकारना चाहिए कि लोकतंत्र में अगर तालियाँ मिलती है तो गालियां भी मिलेगी इसको भी स्वीकारना पड़ेगा । इसको अगर न स्वीकारिये तो हमें लगता है- लेकिन एक चीज दिखना चाहिए लोहिया जी के शब्दों में कि गाली देने वाला व्यक्ति क्यों गाली दे रहा है ? जन सरोकारों के सवाल पर यदि गाली दे रहा है तो चिंतन करना चाहिए, लेकिन अगर गाली व्यक्तिगत कुंठा से दे रहा है तो बेपरवाह रहना चाहिए । इन चीजों को ध्यान में रखकर इसलिए मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हम बजट का आकार बनाएं तो एक बार निष्पक्ष होकर बनाएं । निष्पक्षता किस बावत कि आज वे गरीब लोग जो 13 परसेंट हैं जिनके माथे पर छत नहीं है, 30 परसेंट जो कृषि पर आधारित हैं । इसको नजरअंदाज करके बजट नहीं बनाया जा सकता और जो लोग भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं उनको नजरअंदाज करके बजट नहीं बन सकता जब तक इसकी निर्मूलता नहीं ढूढेंगे तब तक यह बार-बार सवाल आपके सामने खड़ा होता रहेगा। चाहे वह 22 परसेंट, 23 परसेंट लोग जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं आखिर क्यों यह सवाल बार-बार कभी इधर के लोग, कभी उधर के लोग खड़ा करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं ? आखिर कहीं न कहीं यह बात सामने दिख रही है शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर यह सत्य है कोई भी सरकार बन जाये यह सब कोई कह सकता है कि राम राज ला सकता है, कोई भी कह सकता है, कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ला नहीं सकता है । जब राम राज में राम राज नहीं आ सका तो अभी कैसे आ जायेगा, नहीं आ सकता है, लेकिन उसमें सावधान तो जरूर होंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि उसका जो शासक है- शासक की नीति लोगों को दिखता है कि शासक जो है उसकी नीति क्या है तो हम जिन सवालों पर आज खड़े हुए हैं कि आज बिहार 30.60 परसेंट अभी भी गरीबी रेखा से हम नीचे हैं, अभी सबसे ज्यादा निचले पायदान पर हम देशभर में हैं तो इसको कैसे निर्मूल कीजियेगा? इसका उपाय आपने अपने बजट में नहीं बताया । जलवायु परिवर्तन पर सबको चिंता हो रही है होनी भी चाहिए सबसे भयंकर समस्या है, होनी चाहिए, नहीं कैसे होगा

और नहीं होगा तो रोज उसी से लड़ते रहियेगा, जूझते रहियेगा तो होनी चाहिए चिंता । जल संरक्षण की बात कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करते कहां हैं आप निकल तो जाइये । उसके लिए सरकार के स्तर पर सामाजिक रूप से अवेयर करते रहिये अलग विषय है, लेकिन सरकारी कार्यालयों के बगल में नल खुले रहते हैं उसको कौन देखता है उसके लिए कौन फिक्स करेगा ? सरकारी कार्यालय परिसरों में पानी का जिस तरह से बेतहाशा बहाव होता है । इन्हीं के राज्य में सुशील कुमार मोदी जी के बगल में जो झारखण्ड प्रदेश है 15 दिन तक जिस तरह से पानी की बौछाड़ चलती रही और सरकार चुपचाप बैठी रही, देशभर की चिंता है । आपके प्रधानमंत्री ने जलशक्ति डिपार्टमेंट ही बना दिया बगल में बैठे चले गये । सोशल क्रांति आयी है तो सबमें आई है । हमारे भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने जो कहा लालटेन युग और क्या-क्या बोल गये । अरे युग तो परिवर्तित होते रहता है कभी आपका, कभी उसका, कभी उसका आते रहता है लोग सबको याद करते रहते हैं । जब हम लोहिया जी को याद करते हैं, जय प्रकाश जी को याद करते हैं तो लालू जी को भी आप उसी रूप में करते हैं तो सामाजिक क्रांति के नेता हैं इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आपको मानना पड़ेगा । हो सकता है कि दूसरे किसी बिन्दु पर हम फिसड्डी साबित हो गये, पीछे रह गये हों, लेकिन आज नरेन्द्र मोदी जी से लेकर से अमित शाह जी से लेकर के अभी सुशील कुमार मोदी बैठे हैं तो यह सोशल क्रांति की परिणति है कि आप आगे बैठे हैं वर्ना आज जिनको नेपथ्य के रास्ते से लाकर के आपने सामने रखा है वे आगे होते और आप पीछे होते । यह सामाजिक क्रांति की देन है । हर पार्टी में कोई एक नेता अगर सामाजिक क्रांति लाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसी के दल के अंदर लंबे समय तक उसी की सरकार रहे । अगर हर पार्टी में वह दृश्य दिखने लगे, सामाजिक क्रांति का असर दिखने लगे तो माफ कीजियेगा मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं । पहले की व्यवस्था में पूजा कराने में सुशील कुमार मोदी जी के घर में जो लोग कतराते थे आज साष्टांग कर रहे हैं, दण्डवत कर रहे हैं यही तो है क्रांति, यही क्रांति है माफ करियेगा । हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं । नहीं कराते थे उनके घर में पूजा कराने वाले परहेज करते थे आज आपके पैर छू रहे हैं यही न सामाजिक क्रांति है ? वही न इस जगह पर आये उस व्यवस्था के खिलाफ । आप लड़ते रहे तो आज आगे हैं । हर दल में वह दृश्य दिख रहा है इस बात को मानना पड़ेगा कहीं न कहीं । महोदय, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक जो

आपने जाति आधारित जनगणना किसी जाति में लोग गरीब हो सकते हैं, हर जाति में अमीर और गरीब हैं, लेकिन बहुलता किसमें है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादातर जो गरीब घर के बच्चे हैं शिकार हुए, चमकी रोग के शिकार कौन हुए जो गरीब हैं । कुपोषण के शिकार का प्रतिफल है कि कई तरह की भ्रांतियां उसके अंदर है । जिसकी चर्चा आपने की अपने वक्तव्य में, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी निर्मूलता के कारण क्या हो सकते हैं ? यह तो कहीं न कहीं प्रावधान आपको बजट में निहित करने पड़ेंगे । जब तक बजट में इन प्रावधानों को निहित नहीं कीजियेगा तब तक आनेवाला समय निश्चित तौर पर आपको देखेगा तभी जब इनकी निर्मूलता के समाधान के रास्ते आप ढूढ़ निकालेंगे । किसान कोई जाति है क्या ? गरीब हर जाति में है, संख्या चाहे जिस जाति में ज्यादा हो गरीब का । यह सत्य है कि हर जाति में गरीब है, बहुलता किसी में ज्यादा है, किसी में कम है । उसको ध्यान में रखकर बजट- इसलिए हमने कहा कि बजट में विजन और डायरेक्शन दोनों का अभाव है । इसलिए मैंने कहा कि रूटीन बजट है ।

अध्यक्ष : अब ललित जी की सलाह है कि आप समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, आपने जब समय का निर्धारण कर दिया है कुछ सोचकर खड़े हुए थे, लेकिन चलिये समय का अभाव है तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा ।

अध्यक्ष : अब आपको अपनी बात समाप्त करके बैठना है इसके लिए आप ललित जी को धन्यवाद दे दीजिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : जी मैं धन्यवाद देता हूँ । आपने जब कहा तो आसन की बात नहीं मानना भी उचित नहीं है इसलिए माननीय महोदय आदरणीय वित्त मंत्री जी से आपने जो बजट लाया है महोदय वही मिलाजुलाकर के घिसीपिटी स्थितियां है और एक सेकेंड में मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा । आदरणीय हमारे साथी ने कह दिया कई लोगों ने इसपर चर्चा किया महोदय सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई होती है सच्चाई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है तो बजट के प्रावधान में अब लगातार वही चीजें सबपर चर्चा करेंगे तो बिन्दुवार चर्चा करने के लिए समय ही कम है।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अब हम इन्हीं शब्दों के साथ हम बात को समाप्त कर रहे हैं कि आप निहित प्रावधान करें बजट में ताकि आनेवाले कल में सबको इसका लाभ मिल सके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में सार्वभौमता का जो रंग है चढ़ाकर बात कीजिए । धन्यवाद ।

टर्न-28/ज्योति/01-07-2019

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श कल दिनॉक 2 जुलाई 2019 को भी जारी रहेगा ।

आज दिनॉक 1 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 9 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अभी सभा की बैठक समाप्त होने के तुरत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी । समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे ।

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनॉक 2 जुलाई, 2019 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

AES पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य में AES (Acute Encephelitis Syndrome) से होने वाली मृत्यु आहत करने वाली है । सरकार इस विषय पर पूरी तरह संवेदनशील है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषय पर अवगत कराना है कि राज्य सरकार ने AES के नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास किए हैं । वस्तुतः AES किसी एक बीमारी का नाम नहीं है बल्कि यह बीमारियों का समूह है, जिसके प्रारंभिक लक्षण एक समान होते है ।

AES बीमारी का प्रकोप मुजफ्फरपुर जिले में वर्ष 1995 से ज्ञात है। इसके ईलाज हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्था यथा National Institute of Virology, Pune; National Centre for Disesae Control, Delhi; All India Institute of Medical Sciences, Delhi; Rajendra Memorial Research Institute, Agamkuan, Patna, Centre for Disease Control, अटलांटा (अमेरिका) द्वारा समय-समय पर शोध किया गया किन्तु किसी निश्चित कारक (Causative Agent) की जानकारी नहीं पायी जा सकी। बीमारी का प्रकोप धीरे-धीरे बढता गया। फलतः 2012 में भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा बिहार सहित कुल 5 राज्यो के 60 जिलो को आवश्यक निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया। इन 60 जिलो में से बिहार के 15 जिले यथा- पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वीचम्पारण ,प0 चम्पारण, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा एवं नालंदा सम्मिलित है। मंत्री समूह द्वारा दिये गये सुझावो के आलोक में AES मरीजों को चिकित्सा सुविधा हर स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु निदेशानुसार Standard Operating Procedure (SOP) की संरचना की गई एवं वर्ष 2013 SOP के आधार पर AES के मरीजों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्यकर्मी द्वारा जागरूकता की जाती रही है।

SOP के आधार पर ही बीमारी के प्रकोप माह जून के पूर्व से ही AES प्रभावित 12 जिलों यथा पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण,सीतामढ़ी एवं शिवहर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ,सदर अस्पतालों एवं इन जिलों के अंतर्गत पडने वाले चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों एवं दवाओं की व्यवस्था की जाती रही है।

बिहार में मस्तिष्क ज्वर (AES) का मुख्य केन्द्र (Epicenter) मुजफ्फरपुर है जबकि जापानी इंसेफलाईटिस (JE) का गया है। मुजफ्फरपुर जिले में तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने के साथ ही मस्तिष्क ज्वर के मरीज प्रतिवेदित होने लगते है जो बरसात शुरू होते ही समाप्त हो जाते है जबकि गया जिले में बरसात शुरू होते ही जापानी इंसेफलाईटिस (JE) के मरीज प्रतिवेदित होने लगते है जो जाडे की शुरूआत के साथ समाप्त हो जाते है। विगत वर्षो में मुजफ्फरपुर AES बीमारी की पहचान हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये विभिन्न शोधो में किसी विशेष कारक (Causative Agent) की पहचान नहीं की जा सकी।

मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की पहचान एवं इसके लक्षणः-

1. सरदर्द , तेज बुखार आना जो 5-7 दिनों से ज्यादा का ना हो।
2. अर्द्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना/भ्रम की स्थिति में होना/बच्चे का बेहोश हो जाना।
3. शरीर मे ऐंठन (Convulsion), चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना।
4. पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना।
5. बच्चे का शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होना।

इस वर्ष सर्वाधिक मृत्यु Hypoglycemia जो AES का एक लक्षण है, से हुई है, जिसका कारण प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी ,आद्रता एवं बारिश का नहीं होना है। बीमारी के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए आमजन में यह संदेश दिया जा रहा है कि बच्चों को धूप से बचाएँ

क्योंकि इसके कारण Dehydration की शिकायत होती है फलस्वरूप बच्चों की रुचि भोजन एवं पानी में कम हो जाती है और Hypoglycemia उत्पन्न होता है। साथ ही आमजनों को बच्चों को दिन में दो बार स्नान कराने, रात में खाली पेट नहीं सोने देने,सोने के समय नींबू पानी,शक्कर अथवा ओ0आर0एस0 का घोल पिलाने के संबंध में प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों में चमकी बुखार शारीरिक अथवा मानसिक संतुलन में कमी होते ही तुरन्त नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में भेजने के संबंध में अवगत कराया जाता रहा है जिससे कि प्राथमिक उपचार के पश्चात आवश्यकता होने पर 102 एम्बुलेन्स से निःशुल्क मरीज को उच्चत्तर स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जा सके।

AES नियंत्रणार्थ गतिविधियों की विस्तृत विवरणी –

1. भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा वर्ष 2012 के दिये निदेश के आलोक में क्षेत्र विशेष एवं लीची पैदावार वाले जिलों को ध्यान में रखते हुए **Standard Operating Procedure** (SOP) वर्ष 2013 (SOP) में तैयार किया गया जिसके आधार पर मरीजों की चिकित्सा एवं जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं क्षेत्र से प्राप्त Feedback के आधार पर पुनः वर्ष 2018 में SOP को संशोधित करते हुए सभी जिलों को नया SOP 2018 उपलब्ध कराया जा चुका है। इसे स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के Web Portal www.health.bih.nic.in के Operational guideline Section पर भी पूर्व की तरह Upload कर दिया गया है। JE/AES के Clinical Management के तहत 6656 SOP-2018 की प्रतियाँ सभी जिलो के चिकित्सा पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है।
2. प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी SOP के आधार पर AES/JE हेतु चिन्हित 12 जिलों के 222 स्वास्थ्य केन्द्रों यथा पी0एच0सी, सभी अनुमंडलीय अस्पताल, सभी रेफरल अस्पताल, सभी सदर अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रथम चक्र Gap Assessment 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक किया गया, जिसकी समीक्षा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2019 को की गई । तत्पश्चात सम्पुष्टि हेतु द्वितीय चक्र Gap Assessment 25 से 28 मई 2019 को किया गया जिसकी समीक्षा पुनः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30.05.2019 को की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं। इस प्रकार JE/AES नियंत्रणार्थ आवश्यक अनुशंसित दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता **बीमारी के प्रकोप से पहले कर दी गई है।**
3. राज्य के चिन्हित 29 जिलों के 445 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों एवं 472 आयुष चिकित्सकों को AES के Treatment Protocol पर Reorientation Training दिया जा चुका है।
4. सभी सरकारी अस्पतालो में इस रोग के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
5. चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभाग एवं जिला अस्पताल में अलग से आई0सी0यू0 एवं AES वार्ड की स्थापना की गयी है ताकि AES के मरीजों का त्वरित उपचार किया जा सके।
6. JE/AES मरीजों का Leptospirosis Test भी RMRIMS, Patna में 2018 से प्रारंभ कर दिया गया है।
7. Viral एवं Bacterial Test के Sample की क्रॉस जॉच 2014 से RMRI में भी कराई जा रही है।
8. चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का स्थानीय व्यवस्था से क्रय एवं भंडारण किया गया है।
9. आवश्यकतानुसार प्रभावित जिलों में MBBS चिकित्सक, आयुष चिकित्सक एवं एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति की गई है।

10.राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों यथा पी० एम० सी० एच०–पटना, एन० एम० सी० एच०–पटना, एस० के० एम० सी० एच०–मुजफ्फरपुर, मगध मेडिकल कॉलेज–गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज–दरभंगा एवं जे० एल० एन० एम० सी० एच०,भागलपुर को जे०ई० नियंत्रणार्थ भारत सरकार द्वारा Sentinel Sites के रूप में चयनित हैं । इन चिकित्सा महाविद्यालयों में निःशुल्क जे०ई० की जाँच के लिए ELISA Test Kit उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त कुर्जी हॉली फैमली अस्पताल,महावीर वात्सल्य अस्पताल,पटना, RMRIMS पटना एवं IGIMS पटना को निःशुल्क जे०ई० की जाँच के लिए ELISA Test Kit उपलब्ध कराया गया है।

11.मरीजों हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस के अलावा अन्य वाहन से अस्पताल आने पर 400/–(चार सौ रूपये)मात्र का प्रावधान रखा गया है।

12.आशा द्वारा घर–घर पम्फलेट का वितरण किया जाता रहा है साथ ही आशा एवं ऑगनबाडी सेविका द्वारा ORS का वितरण किया जाता रहा है।

13.मृत मरीजो के निकटतम आश्रितों को मुख्य मंत्री राहत कोष से 4,00,000/–(चार लाख रूपये) मात्र देने का प्रावधान किया गया है।

14.JE नियंत्रणार्थ बिहार के चयनित 24 जिलों में सामूहिक टीकाकरण (Mass Vaccination) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा कराया गया है जिसमें 91.3% बच्चों को टीका दिया गया है।

15.जैपनीज इंसेफलाईटिस(JE) के सम्पुष्ट मरीजों के गाँव में टेक्नीकल मालाथियॉन का फौगिंग कराया जा रहा है।

विगत वर्षो एवं इस वर्ष SOP के अनुसार जो जागरूकता अभियान और अन्य व्यवस्थाएँ की गई, उसकी विवरणी–

- वर्ष 2018 में कुल 6656 संशोधित SOP 2018 पुस्तिका राज्य के सभी जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध करायी गई जिसका वितरण स्वास्थ्य विभाग के Frontline कार्यकर्ता एवं कर्मी के द्वारा हुआ ।
- लीची पैदावार वाले जिलों के लिए 2018 में 21 लाख पैम्फलेट उपलब्ध कराई गई ।
- वर्ष 2019में आशा दीदीओं द्वारा माईकिंग के साथ अभी तक लगभग 14 लाख पम्फलेट्स बॉटे गए साथ ही लगभग 17 लाख पैकेट ORS का वितरण किया गया।
- वर्ष 2019 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो एवं सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर आदि पर एईएस विषयक संदेशों का प्रसार किया गया ।
- आई.ई.सी. से संबंधित विविध सामग्रियाँ यथा SOP, सामान्य मार्गदर्शिका, आशा एवं ANM के लिए मार्गदर्शिका, लीची पैदावार जिलों के लिए मार्गदर्शिका, फ्लेक्स बैनर का नमूना इत्यादि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के वेब–पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इन सामग्रियों को जिला स्तर पर छपवाने संबंधी निदेश वित्तीय मार्गदर्शिका में अंकित है। जिलों को Flex राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अलग से उपलब्ध कराया जाता रहा है।
- विगत वर्षो के अनुरूप इस वर्ष भी समय–समय पर समाचार पत्रों में ए.ई.एस. के लक्षण, बचाव एवं उपचार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया ।
- जीविका, विकास मित्र, किसान सलाहकार एवं जनप्रतिनिधि द्वारा प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- चिकित्सीय सलाह एवं आपातकाल स्थिति हेतु 104 न० का कॉल सेन्टर कार्यरत है।

विगत नौ वर्षो के आँकड़े पर एक दृष्टि डालें –

क्र0सं0	वर्ष	कुल मरीज	स्वस्थ	मृत	मृत्यु दर (%)
1	2011	944	740	204	22 %
2	2012	1247	823	424	34 %
3	2013	580	358	222	38 %
4	2014	1341	962	379	28 %
5	2015	298	208	90	30 %
6	2016	324	221	103	32 %
7	2017	189	135	54	29 %
8	2018	124	91	33	27 %
9	Till 28 June 2019(Source IDSP SHSB)	720	566	154	21 %

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में सरकार के प्रयास से मृत्यु दर में कमी आयी है ।

2014 के बाद AES के इलाज हेतु बढ़ाई गई चिकित्सीय सुविधाएँ –

1. SKMCH, मुजफ्फरपुर में PICU में बेड की संख्या 14 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है। इसमें PICU के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।
2. AES/JE नियंत्रणार्थ वित्त वर्ष 2019–20 में राज्य के सात जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा (इन चार जिलों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के शिशु रोग विभाग में), वैशाली, पूर्वी चम्पारण (इन दो जिलों के सदर अस्पताल में) तथा नवादा जिले के अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में PICU (Paediatric Intensive Care Unit) की स्थापना कर संचालन प्रारंभ किया गया है ।
3. आयुष्मान भारत PMJAY कार्यक्रम अंतर्गत M200078 एवं M00035 पैकेज केअंतर्गत AES के मरीजों का ईलाज किया जा रहा है।
4. AIIMS,पटना, DMCH, दरभंगा एवं PMCH,पटना से शिशु रोग विशेषज्ञो से एवं नर्सो की प्रतिनियुक्ति SKMCH,मुजफ्फरपुर में की गई है।
5. Central Team द्वारा 10 शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा एवं 5 पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति मुजफ्फरपुर में की गई है।
6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा Health Alert Advisory भी जारी की गई है।

2013 एवं 2018 के SOP की मुख्य विशेषता:–

1. सर्वप्रथम वर्ष 2013 में SOP का निर्माण किया गया। इसके आधार पर मरीजों के ईलाज में कुछ नए तथ्यों को समाहित करने की आवश्यकता चिकित्सकों द्वारा महसूस की गई। इसी के आधार पर पुनः वर्ष 2018 में संशोधित SOP का निर्माण किया गया।
2. वर्ष 2018 में Etiology / Causes of AES में कुछ नई बीमारियों को समाहित किया गया जिसमें नीपा इंसेफलाईटिस, चाँदीपुरा वायरस, Heat Pyrexia, Hypogycenia, Dyselectrolytemia, Leptospirosis इत्यादि को जोड़ा गया। इन बीमारियों में भी शुरूआती लक्षण AES के पाए जाते है।

3. मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु अन्य विभागों की सहभागिता SOP में वर्णित है ।
4. चिकित्सा संस्थान में मरीजों के आते ही तुरंत क्या करना चाहिए इसका एक Chapter शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त Treatment Guideline में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सुझाव पर आवश्यकतानुसार सुधार किया गया।
5. मृत मरीजों का Verbal Autopsy करने का प्रावधान किया गया है। इसमें जिला स्तर पर गठित कमिटी में अध्यक्ष सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य होते हैं।

इस वर्ष का तिथिवार, मरीजवार ऑकड़ा–

IDSP राज्य स्वास्थ्य समिति,बिहार,पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस वर्ष 28 जून 2019 तक 720 मरीज प्रतिवेदित हुए है जिसमें 154 मरीजों की मृत्यु हो गई है जिसकी विवरणी निम्नवत है –

Date wise no. of cases of AES in Bihar in 2018 (IDSP) (from 3 Jan 2018 till 29 June 2019)

STATE SURVEILLANCE UNIT, IDSP, STATE HEALTH SOCIETY,BIHAR

Date	Cases	Death	Date	Cases	Death	Date	Cases	Death	Date	Cases	Death	Date	Cases	Death
3 Jan 19	1	1	12 Feb 19	0	0	24 Mar 19	0	0	03 May 19	0	0	12 Jun 19	24	1
4 Jan 19	0	0	13 Feb 19	0	0	25 Mar 19	0	0	04 May 19	0	0	13 Jun 19	28	7
5 Jan 19	0	0	14 Feb 19	0	0	26 Mar 19	1	0	05 May 19	0	0	14 Jun 19	41	32
6 Jan 19	0	0	15 Feb 19	0	0	27 Mar 19	0	0	06 May 19	1	0	15 Jun 19	72	22
7 Jan 19	0	0	16 Feb 19	0	0	28 Mar 19	0	0	07 May 19	0	0	16 Jun 19	60	33
8 Jan 19	0	0	17 Feb 19	0	0	29 Mar 19	0	0	08 May 19	0	0	17 Jun 19	56	5
9 Jan 19	0	0	18 Feb 19	0	0	30 Mar 19	0	0	09 May 19	0	0	18 Jun 19	41	7
10 Jan 19	0	0	19 Feb 19	0	0	31 Mar 19	0	0	10 May 19	0	1	19 Jun 19	100	9
11 Jan 19	0	0	20 Feb 19	0	0	01 Apr 19	0	0	11 May 19	0	0	20 Jun 19	44	6
12 Jan 19	0	0	21 Feb 19	0	0	02 Apr 19	0	0	12 May 19	0	0	21 Jun 19	13	3
13 Jan 19	0	0	22 Feb 19	0	0	03 Apr 19	1	0	13 May 19	0	0	22 Jun 19	48	1
14 Jan 19	0	0	23 Feb 19	1	0	04 Apr 19	0	0	14 May 19	0	0	23 Jun 19	10	1
15 Jan 19	0	0	24 Feb 19	0	0	05 Apr 19	1	0	15 May 19	0	0	24 Jun 19	9	1
16 Jan 19	0	0	25 Feb 19	0	0	06 Apr 19	0	0	16 May 19	1	1	25 Jun 19	5	1
17 Jan 19	0	0	26 Feb 19	0	0	07 Apr 19	0	0	17 May 19	0	0	26 Jun 19	7	1
18 Jan 19	0	0	27 Feb 19	0	0	08 Apr 19	0	0	18 May 19	0	0	27 Jun 19	1	0
19 Jan 19	0	0	28 Feb 19	0	0	09 Apr 19	0	0	19 May 19	0	0	28 Jun 19	0	0
20 Jan 19	0	0	1 Mar 19	1	0	10 Apr 19	1	0	20 May 19	0	0			
21 Jan 19	0	0	2 Mar 19	0	0	11 Apr 19	0	0	21 May 19	0	0			
22 Jan 19	0	0	3 Mar 19	0	0	12 Apr 19	0	0	22 May 19	1	0			
23 Jan 19	0	0	4 Mar 19	0	0	13 Apr 19	0	0	23 May 19	1	0			
24 Jan 19	0	0	5 Mar 19	1	0	14 Apr 19	0	0	24 May 19	0	0			
25 Jan 19	1	0	6 Mar 19	0	0	15 Apr 19	0	0	25 May 19	0	0			
26 Jan 19	0	0	7 Mar 19	0	0	16 Apr 19	0	0	26 May 19	1	0			
27 Jan 19	0	0	8 Mar 19	0	0	17 Apr 19	1	0	27 May 19	0	0			
28 Jan 19	0	0	9 Mar 19	0	0	18 Apr 19	0	0	28 May 19	0	0			
29 Jan 19	0	0	10 Mar 19	0	0	19 Apr 19	0	1	29 May 19	0	0			
30 Jan 19	0	0	11 Mar 19	1	0	20 Apr 19	0	0	30 May 19	0	0			
31 Jan 19	0	0	12 Mar 19	0	0	21 Apr 19	0	0	31 May 19	0	2			
1 Feb 19	0	0	13 Mar 19	0	0	22 Apr 19	1	0	01 Jun 19	0	0			
2 Feb 19	0	0	14 Mar 19	0	0	23 Apr 19	0	0	02 Jun 19	1	0			
3 Feb 19	0	0	15 Mar 19	0	0	24 Apr 19	0	0	03 Jun 19	0	0			
4 Feb 19	0	0	16 Mar 19	0	0	25 Apr 19	1	0	04 Jun 19	9	2			
5 Feb 19	0	0	17 Mar 19	0	0	26 Apr 19	0	0	05 Jun 19	12	3			
6 Feb 19	0	0	18 Mar 19	0	0	27 Apr 19	1	0	06 Jun 19	11	7			
7 Feb 19	0	0	19 Mar 19	0	0	28 Apr 19	0	0	07 Jun 19	8	3			
8 Feb 19	0	0	20 Mar 19	0	0	29 Apr 19	0	1	08 Jun 19	11	3			
9 Feb 19	0	0	21 Mar 19	0	0	30 Apr 19	0	0	09 Jun 19	18	2			
10 Feb 19	0	0	22 Mar 19	0	0	01 May 19	0	0	10 Jun 19	44	10			
11 Feb 19	0	0	23 Mar 19	0	0	02 May 19	0	0	11 Jun 19	24	7			
	2	1		4	0		7	1		149	47		558	104

इस वर्ष SKMCH, मुजफ्फरपुर में प्रतिवेदित होने वाले AES के मरीजों की संख्या निम्न है–

जनवरी – 1
फरवरी – 0
मार्च – 1
अप्रैल – 4
मई – 8
5 जून तक – 9

इसके उपरान्त 6 जून से मरीजों की संख्या में अचानक बढोतरी होने लगी, जिसके बाद भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर पर सिविल सर्जन एवं एस.के.एम.सी.एच. के अधीक्षक के स्तर पर युद्ध स्तर पर कदम उठाए गए। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवरणी संलग्न है। उल्लेखनीय है कि मरीजों की बढती संख्या के साथ ही PICU (Paediatric Intensive Care Unit) के बेड की संख्या क्रमशः बढ़ाई गई जो वर्तमान में 66 है ।

मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार AES नियंत्रण हेतु कटिबद्ध है। आने वाले समय में एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में PICU के बेड की संख्या वर्तमान में कार्यरत 66 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। एस.के.एम.सी.एच. में अभी कुल बेड की संख्या 610 है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रथम चरण में इसे बढ़ाकर 1500 बेड किया जाएगा एवं द्वितीय चरण में अस्पताल के कुल बेड की संख्या 2500 की जाएगी । एस.के.एम.सी.एच परिसर में Virology Lab स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । मरीजों के परिजन के लिए विश्रामालय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, AIIMS, पटना में रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।

उपर वर्णित प्रयासों से मुझे आशा है कि अगले वर्ष बेहतर आधारभूत चिकित्सीय प्रबंधन (चिकित्सीय प्रोटोकॉल सहित) तथा अनुसंधान के जरिए इस बीमारी पर कारगर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा ।

धन्यवाद ।

AES नियंत्रण हेतु विभागीय स्तर पर लिये गये निर्णयों की तिथिवार विवरणी

दिनांक	विवरणी
08.06.2019	मुजफ्फरपुर एस0के0एम0सी0एच0 की स्थिति की समीक्षा कर माननीय मंत्री ने मीडिया से बात कर हो रहे उपचार व्यवस्था की दी जानकारी
09.06.2019	प्रधान सचिव को निर्देश दिया रविवार को प्रधान सचिव स्तर पर समीक्षा।
	प्रेस–विज्ञाप्ति जारी हुआ।
	माननीय केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, बिहार मिले।
10.06.2019	विभाग के प्रधान सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उपचार एवं हालात के संबंध में प्रेस को जानकारी दी गई।
	माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मिलकर दी स्थिति की जानकारी।
11.06.2019	निदेशक प्रमुख, चिकित्सकों एवं वरीय अधिकारियों के साथ एस0के0एम0सी0एच0 गये एवं सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा की।
12.06.2019	केन्द्रीय टीम माननीय केन्द्रीय मंत्री के निदेश पर एस0के0एम0सी0एच0 पहुँची। निरीक्षण, समीक्षा एवं आवश्यक निर्देश दिये।
13.06.2019	निदेशक प्रमुख एवं केन्द्रीय टीम की समीक्षा एवं सुझाव के आधार पर केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री, सचिव, स्वास्थ्य, भारत सरकार के साथ माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, बिहार की उच्चस्तरीय बैठक, कुछ आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए।
	निदेशक प्रमुख की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा किया गया। प्रेस–विज्ञप्ति जारी हुआ एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।
14.06.2019	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, बिहार एस0के0एम0सी0एच0 जाकर मरीजों से मिलें एवं चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक किया एवं बेड, एम्बुलेंस, जूनियर रेजिडेंट बढ़ाने के लिए निर्देश दिया।
	मुख्यालय से पूर्व में जारी एडवाइजरी को पुनः संशोधित एडवाइजरी जारी किया गया ।
	PICU में जूनियर रेजिडेन्ट की संख्या बढ़ाकर 15 की गई। बैक–अप में सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिया एवं अनुपालन किया गया।

15.06.2019	एन0एम0सी0एच0 में AES से पीड़ित भर्ती मरीजों से मिला एवं बेड बढ़ाने एवं समुचित उपचार का निर्देश दिया।
	बचाव से लेकर चिकित्सा सुविधा की सम्पूर्ण विवरणी, जानकारी मीडिया को प्रेस–विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया।
	पटना एम्स से दो चिकित्सक एवं PICU के छः ट्रेंड नर्स को वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया।
	प्रधान सचिव द्वारा S.K.M.C.H का निरीक्षण एवं मरीजों एवम उनके परिजनों से मुलाकात। उपलब्ध भौतिक एवं मानव आधारभूत की समीक्षा। PICU के 15 बेड 24 घंटे के अंदर बढ़ाने का निर्देश। निर्देश का हुआ 24 घंटे के अंदर अनुपालन।
	रात्रि में लू से मरने वाले गया, औरंगाबाद एवं नवादा की जानकारी प्राप्त हुई एवं तुरन्त माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से लू एवं AES से मरने वालों को चार–चार लाख का मुआवजा एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया।
16.06.2019	केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ एस0के0एम0सी0एच0 का दौरा किया एवं चार घंटे तक लगभग 100 मरीजों से मिले।
	समीक्षा बैठक कर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।
	एस0के0एम0सी0एच0 में 100 बेड के PICU का निर्माण एवं उच्चस्तरीय रिसर्च लेबोरेटरी के निर्माण का निर्णय।
	नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दस–दस बेड का PICU बनाना।
	एस0के0एम0सी0एच0 में बेडों की संख्या बढ़ाकर 50 की गई।
	राज्य में चार स्थानों पर वाइरोलॉजी लैब के निर्माण का निर्णय लिया गया।
17.06.2019	माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्य सचिव के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जिसके अनुपालन की जिम्मेवारी मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को दी गई।
	माननीय मुख्यमंत्री ने बीमारी के कारणों के बेहतर समझ एवं प्रभावकारी प्रबंधन हेतु प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों के सामाजिक, आर्थिक एवंम पर्यावरणीय (Enviormental) सर्वे करने का निदेश दिया। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के जीविका समूह के द्वारा एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक देख–रेख में Multi Departmental टीम के गठन का निदेश दिया।

18.06.2019	माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों का दौरा एस0के0एम0सी0एच0 में हुआ। माननीय महोदयों द्वारा मरीजों एवं परिजनों से मुलाकात एवं अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्था की पूरी समीक्षा।
	08 सीनियर रेजिडेंट को प्रतिनियुक्त किया गया।
	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा 100 PICU बेड बनेगा, एस0के0एम0सी0एच0 2500 बेड का अस्पताल बनेगा। प्रथम चरण में 1500 बेड तक।
	अटेंडेंट के रूकने के लिए धर्मशाला बनेगा।
	7 एक्सपर्ट रिसर्च के लिए भारत सरकार की ओर से एस0के0एम0सी0एच0 में भेजे गये।
	10 बी0एल0एस0 एवं 7 अलसा एम्बुलेंस भेजे गये।
19.06.2019	10 डॉक्टर और 5 पारामेडिकल स्टाफ दिल्ली से एस0के0एम0सी0एच0 में आये डॉ0 विश्वश्वरूप (पेडिएट्रिक न्यूरो एम्स) डॉ0 जुम्मा शंकर (आई0सी0यू0 एम्स पेडिएट्रिक) के साथ।
	16 बेड आई0सी0यू0 में बढ़ाये गये, कुल 66 बेड हो गये।
	BMSICL में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार हेतु बैठक आयोजित कर कई निर्णय हुए।
20.06.2019	12.50 लाख ओ.आर.एस. के घोल बांटे गये।
	788 गाँव में जागरूकता के लिए माइकिंग, 328 रैलियाँ निकाली गयीं।
	केयर इंडिया, यूनिसेफ एवं जीविका की टीम मुसहरी, कांटी, मीनापुर में विशेष तौर से मरीजों को खोज–खोज एवं पी.एच.सी. उपचार के लिए लगाया गया।
	जिलास्तरीय अधिकारी, टीबी ऑफिसर, ए.सी.एम.ओ. डी.आई.ओ. को ब्लॉक में प्रतिनियुक्त किया गया। प्रखण्ड स्तर से समन्वय बनाने के लिए।
	सर्च अभियान में 250 बच्चों की हुई पहचान मिले हल्के बुखार एवं अन्य प्रकार की तकलीफ, उनका किया गया उपचार।
	कुल 58 डॉक्टरों की टीम ने संभाला मोर्चा।
	माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप–मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में गर्मी एवं लू से प्रभावित मरीजों से मुलाकात। नवसृजित आपातकालीन वार्ड में मरीजों तथा उनके चिकित्सीय व्यवस्था के पूर्ण स्थिति का जायजा लिया। तदोपरांत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा मगध प्रमण्डल के सभी पदाधिकारियों के साथ AES के

	द्वितीय चरण में गया के आस–पास जापानी इन्सफलाईटिस से होने वाले सभी बीमारी के लिए उपायों एवं व्यवस्था की समीक्षा कर जागरूकता अभियान को सुदृढ करने, JE प्रतिरक्षण को और प्रभावकारी बनाने विशेष कर प्रभावित टोलों में छुटे हुए बच्चों को प्रतिरक्षित करने तथा PICU के लिए विद्यमान 10 बेडों के अतिरिक्त 20 बेडों की स्थापना का निदेश।
21.06.2019	अपर सचिव सह–एम0 डी0, एन0 एच0 एम0, श्री मनोज झलानी, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में आयी 4 सदस्यीय टीम ने भविष्य में आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए एस0के0एम0सी0एच0 का दौरा किया।
	भारत सरकार के स्वास्थ्य परामर्शी डॉ0 अरूण कुमार जी के नेतृत्व में टीम अभी भी कार्यरत है। साथ ही शोध कार्य भी चल रहा है।

– वर्त्तमान में एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में कुल 63 चिकित्सक सेवा में।

– 18.06.2019 से 23.06.2019 तक अपर सचिव, डॉ0 कौशल किशोर, मुजफ्फरपुर में कैम्प कर चिकित्सा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे।

– 18.06.2019 से 21.06.2019 तक E.D, S.H.S. श्री मनोज कुमार, मुजफ्फरपुर में कैम्प कर चिकित्सा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे।